रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 18, 1985/वैशाख 28, 1907
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 18, 1985/Vaisakha 28, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 1 मई, 1985

का.आ. 2097.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) (संशोधन) द्वितीय नियम, 1985 है ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में —

(1) नियम 6 के उपनियम (1) में परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित और परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(ग) नियम 13 के उपनियम (3) द्वारा शासित किसी ऐसे आवेदक की दशा में जिसके मामले में पेंशन का संराशीकृत मूल्य उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख के अगले दिन देय हो जाता है, संराशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कमी उसके प्रारम्भ मे प्रवर्तित होगी। तथपि, जहां पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय सेवा निवृत्ति की तारीख के पश्चात् एक मास के भीतर नहीं किया जा सका है, वहां निवृत्ति की तारीख के अगले दिन और उस तारीख की जिसको पेंशन के संराशीकृत मूल्य

का केन्द्रीय सरकार लेखा प्राप्ति और संदाय) नियम, 1983 के नियम 49 के निबंधनों के अनुसार संदाय किया गया, माना जाता है, पूर्ववर्ती तारीख के बीच वाली [redacted] लिए मासिक पेंशन का अन्तर लेखा [redacted] द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा ।"

2. नियम 15 के उपनियम (3) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(ख) (1) लेखा अधिकारी प्ररूप 1 क में दी गई जानकारी आवश्यक सत्यापन करने के पश्चात्—

(क) कार्यालय अध्यक्ष को बिल प्रस्तुत किए जाने पर पेंशन के संराशीकृत मूल्य की रकम निकालने के लिए और पेंशनभोगी को चैक/ड्राफ्ट जिस पर, (सेवा निवृत्ति की तारीख से अगली तारीख) के पूर्व संदेय नहीं", लिखा होगा, देने के लिए प्राधिकृत करेगा ।

(ख) पेंशन संदाय आदेश के दोनों प्रभागों में (1) कुल पेंशन ;

(2) संराशीकृत पेंशन की रकम, और (3) यह तथ्य कि पेंशन का संराशीकृत मूल्य आहरण और संवितरक अधिकारी द्वारा पृथक रूप से प्राधिकृत किया गया है, उपदर्शित करेगा ;

(ग) तत्समान रूप से उसके प्रारम्भ से मासिक पेंशन कम करेगा ;

(घ) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक को पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय किए जाने का एक टिप्पण उसकी सेवा पंजिका में करेगा, और

(ङ) जहां पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय सेवा निवृत्ति की तारीख के पश्चात् पहले मास के भीतर नहीं किया गया है और विलम्ब पेंशनभोगी की ओर से हुआ नहीं माना जा सकता है, वहां लेखा अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष को सेवा-निवृत्ति की तारीख के अगले दिन और उस तारीख की, जिसको पेंशन के संराशीकृत मूल्य का, केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति और संदाय) नियम, 1983 के नियम 49 के निबंधनों के अनुसार संदाय किया गया माना जाता है, पूर्ववर्ती तारीख के बीच वाली अवधि के लिए मासिक पेंशन के अन्तर के संदाय के लिए प्राधिकार पत्र जारी करेगा ।

(II) लेखा अधिकारी आवेदक को वह तारीख सूचित करेगा जिसको पेंशन संदाय आदेश संवितरक प्राधिकारी को भेजा गया है ।

(III) लेखा अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष से वह तारीख जिसको पेंशन के संराशीकृत मूल्य का चैक/ड्राफ्ट आवेदक को सौंपा गया है; सूचित करने के लिए भी अनुरोध करेगा ।"

3 प्ररूप 1 क के भाग 1 में, अन्त में दिए गए टिप्पणी का लोप किया जाएगा ।

[सं. 34/6/84-पेंशन एकक]

साधू राम अहीर, उप सचिव

टिप्पणी : मूल नियम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं. 6(4)-पेंशन(क)/79 तारीख 23-3-1981 द्वारा पुन: स्थापित किए गए थे और भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 11-4-84 में का. आ. 1134 के रूप में प्रकाशित किए गए थे । बाद में इनका कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं. 34/1/81-पेंशन एकक तारीख 8 जुलाई 1983 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING,

ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES and PENSION

(Department of Pension & Pensioners' Welfare)

New Delhi, the 1st May, 1985

S.O. 2097.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Commutation of Pension) (Second Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981—

(1) in rule 6, in sub-rule (1) at the end of the proviso, the following shall be inserted, namely :—

"(C) in the case of an applicant governed by sub-rule (3) of rule 13 in whose case the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of his retirement, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall be operative from its inception. Where, however, payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement, the difference of monthly pension for the period between the day following the date of retirement and the date preceding the date on which the commuted value of pension is deemed to have been paid in terms of rule 49 of the Central Government Accounts (Receipts and Payments) Rules, 1983, shall be authorised by the Accounts Officer.";

(2) in rule 15, in sub-rule (3), for clause (b) the following clause shall be substituted, namely :—

"(b)(i) The Accounts Officer after necessary verification of the information furnished in Form 1A shall

(A) authorise the Head of Office to draw the amount of commuted value of pension on submission of a bill to him and hand over the cheque/draft superscribed 'Not payable before the ————"(date following the date of retirement) to the pensioner;

(B) indicate in both the halves of the Pension Payment Order (1) the gross pension; (2) the amount of pension commuted; and (3) the fact that the commuted value of pension has been authorised separately through the Drawing and Disbursing Officer;

(C) correspondingly reduce the monthly pension from its inception;

(D) make a note of payment of the commuted value of pension having been made to the retiring Government servant in his Service Book; and

(E) where the payment of commuted value of pension has not been made within the first month after the date of retirement and the delay is not attributable to the pensioner, the Accounts Officer shall issue an authority to the Head of Office for the payment of the difference of monthly pension for the period between the day following the date of retirement and the date preceding the date on which the commuted value of pension is deemed to have been paid in terms of rule 49 of the Central Government Accounts (Receipts and Payments) Rules, 1983.

(ii) The Accounts Officer shall intimate to the applicant the date on which the Pension Payment Order has been despatched to the disbursing authority.

(iii) The Accounts Officer shall also request the Head of Office to intimate the date on which the cheque/draft of the commuted value of the pension has been handed over to the applicant.'

3. In Form IA, in Part I, the note at the end shall be omitted.

[No. 34/6/84-Pension Unit]

S. R. AHIR, Dy. Secy.

NOTE.—The Principal Rules were introduced by Department of Personnel & Administrative Reforms Notification No. 6(4)-Pen(A)/79, dated 23-3-1981 and published as SO 1134 in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, dated 11-4-1981. Subsequently, amended by Department of Personnel and Administrative Reforms Notification No. 34/1/81-Pension Unit dated 8th July, 1983 and No. 34(5)/83-Pension Unit dated 17-4-'85.

नई दिल्ली, 2 मई, 1985

आदेश

का. आ. 2098:—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब सरकार की सहमति से, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 121, 121क, 122, 123, 124क, 153, 153ख, 302, 307, 332, 333, और 353, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 25 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराधों के संबंध में या उससे संबंधित प्रयत्नों दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के तथा पंजाब राज्य में पुलिस सिविल लाइंस पटियाला में रजिस्ट्रीकृत अपराध सं. 178/84 तारीख 6 जून, 1984 के संबंध में वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण पंजाब राज्य पर करती है।

[संख्या 228/7/85-ए०वी०डी० (II)]

New Delhi, the 2nd May, 1985

ORDER

S.O. 2098.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Punjab hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Punjab for the investigation of offences punishable under section 121, 121-A, 122, 123, 124-A, 153, 153B, 302, 307, 332, 333 and 353 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860); sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959); and sub-section (3) of section 5 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to Crime No. 178/84 dated 6-6-84 registered at Police State Civil Lines, Patiala in the State of Punjab.

[No. 228/7/85-AVD. II]

आदेश

का० आ० 2099:—केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 436, 326 और 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराध के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के तथा तारीख 10 और 11 अगस्त 1981 के बीच वाली रात को करीमनगर शहर (आं.प्र.) में कोलीपाका नामपल्ली के घर जलाने और उनकी पत्नी तथा चार अन्य व्यक्तियों की मृत्यु की बाबत पुलिस थाना करीमनगर शहर (आं.प्र.) में रजिस्ट्रीकृत आपराधिक मामला सं. 179/81 तारीख 11 अगस्त, के संबंध में वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए उन्हीं तथ्यों से उदभूत किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर करती है।

[संख्या 228/9/85-ए०वी०डी० (II)]

एम.एस. प्रसाद, अवर सचिव

ORDER

S.O. 2099.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Andhra Pradesh, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for the investigation of offences punishable under sections 436, 326 and 302 of the

Indian Penal Code, 1860(45 of 1860) & attempts abetments & conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of same transaction in regard to Criminal Case No. 179|81, dated the 11th August, 1981, registered at Police State Karimnagar Town (A.P.) in regard to burning of the house of Kolipaka Nampalli and the death of his wife and four others in Karimnagar Town (A.P.), on the intervening night of 10th and 11th August, 1981.

[No. 228|9|85-AVD. II]

M. S. PRASAD, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1985

आयकर

का. आ. 2100—आयकर अधिनियम, राजकोट 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (1) के अनुसरण मे केन्द्र सरकार आयुक्त नगरनिगम राजकोट को अथवा प्रत्येक विशिष्ट मामले मे उसके द्वारा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एतदद्वारा प्राधिकृत करती है ।

[सं० 6139/फा०सं० 225/8/84-आ०क०नि० II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th February, 1985

INCOME-TAX

S.O. 2100.—In pursuance of sub-clause (1) of clause (a) of sub-section (1) of Section 138 of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby authorises the Commissioner, Municipal Corporation, Rajkot, or any other duly authorised by him in writing in respect of each specific case for the purposes of said sub-clause.

[No. 6139|F. No. 225|8|84|ITA. II]

का. आ. 2101—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुसरण में केंद्र सरकार निदेशक/महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार विरोध ब्यूरो महाराष्ट्र सरकार का अथवा प्रत्येक विशिष्ट मामले में लिखित में उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० 6135/फा०सं० 225/144/84-आ०क०नि० II]

S.O. 2101.—In pursuance of sub-section (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the Director|I.G.P., Anti Corruption Bureau, Government of Maharashtra or any other Officer duly authorised by him in writing in respect of each specific case for the purpose of the said sub-clause.

[No. 6135|F. No. 225|144|84-ITA. II]

का. आ. 2102 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुसरण में केंद्र सरकार पंजीयक सहकारी समितियां सचिवालय गांधीनगर अहमदाबाद को अथवा प्रत्येक मामले में उसके द्वारा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एतदद्वारा प्राधिकृत करती है ।

[सं० 6136/फा०सं० 225/39/84-आ०क०नि०-II]

S.O. 2102.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the Registrar of Co-op. Societies, Sachivalaya, Gandhi Nagar, Ahmedabad, or any other officer duly authorised by him in writing in respect of each specific case for the purpose of the said sub-clause.

[No. 6136|F. No. 225|39|84-ITA. II]

का. आ. 2103 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने निदेशक पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता ब्यूरो पंजाब पटियाला को अथवा प्रत्येक मामले में उसके द्वारा लिखित मे विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एतदद्वारा प्राधिकृत करती है ।

[सं. 6137/फा. सं. 225/91/84-आ.क.नि. II]

S.O. 2103.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the Director|I.G.P., Vigilance Bureau of Punjab, Patiala or any officer duly authorised in writing by him in each specific case, for the purposes of the said sub-clause.

[No. 6137|F. No. 225|91|84-ITA. II]

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1985

का. आ. 2104 :—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतदद्वारा निदेशक, भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो हैदराबाद आंध्रप्रदेश सरकार और उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ विशिष्ट मामले के संबंध में उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 6196/फा.सं. 225/153/84-आ.क.नि. II]

दलीप सिंह, विशेष कार्य अधिकारी

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

New Delhi, the 17th April, 1985

S.O. 2104.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the Director, Anti Corruption Bureau, Hyderabad, Government of Andhra Pradesh and any other officer duly authorized by him in writing in respect of a specific case for the purpose of the said sub-clause.

[No. 9196|F. No. 225 153|84|ITA. II]

DALIP SINGH, Officer on Special Duty,

Central Board of Direct Taxes

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1985

आयकर

का. आ. 2105.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, नीचे स्तम्भ 4 में उल्लिखित अधिसूचना (अधिसूचनाओं) का अधिलंघन करते हुए, नीचे स्तम्भ 3 मे उल्लिखित कर वसूली अधिकारियों के स्थान पर नीचे स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी (अधिकारियों) की शक्तियों का प्रयोग करने के के लिए प्राधिकृत करती है :—

क्रम सं.	उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाना है	उन कर वसूली अधिकारी (अधिकारियों) के नाम जिनके स्थान पर स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाना है	अधिलंघन की जाने वाली पुरानी अधिसूचना की संख्या और तारीख
1	2	3	4
1.	श्री एम. के. मालवीय	श्री एम. वी. भिसे	सं. 5189 [फा० सं. 698/16/83-अ. क. (ब.)] दिनांक 19-5-83।
2.	श्री पी. पी. पाटनकर	श्री सी. ए. वास्निक	सं. 4489 [फा. सं. 398/19/81-आ. क. (ब.)] दिनांक 25-2-82।

2. यह अधिसूचना तत्काल लागू होगी और जहां तक स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों का संबंध है, कर वसूली अधिकारियों के रूप में उनके कार्यभार संभालने की तारीख (तारीखों) से लागु होगी ।

[सं. 6194 (फा. सं 398/9/85-आ. का (ब.)]
बी. ई. अलेक्जेंडर, अवर सचिव

New Delhi, the 15th April, 1985

INCOME TAX

S.O. 2105.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the persons mentioned below column 2, being the Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer(s) under the said Act in place of the Tax Recovery Officers mentioned below in column 3 in supersession of the Notification (s) mentioned below in column 4 :

S.No.	Name of the persons to be authorised to exercise powers of Tax Recovery Officer(s)	Name of Tax Recovery Officer(s) in place of whom the persons mentioned in column 2 are to be authorised	Old Notification No. and date to be superseded
1	2	3	4
	S/Shri	S/Shri	
1.	S K. Malviya	M.V. Bhise	No. 5189 [F.No.398/16/83-IT (B)], dt. 19-5-83
2.	P.P. Patankar	C.A. Wasnik	No. 4489 [F. No. 398/19/81-IT (B)], dt. 25-2-82

2. This Notification shall come into force with immediate effect and in so far as persons mentioned in column 2 from the date(s) take over charge(s) as Tax Recovery Officers.

[No. 6194 (F. No. 398/9/85-IT (B)]
B.E. ALEXANDER, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

(आयकर)

का. आ. 2106.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम के 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिये अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1 यह कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मैडिकल साइंसेज एंड टैक्नालाजी, त्रिवेन्द्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये उसके द्वारा प्राप्त राशियो का पृथक लेखा रखेगी ।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररुप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिये अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

संस्था

"श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मैडिकल साइंसेज एंड टैक्नालाजी, त्रिवेन्द्रम"

यह अधिसूचना 21 फरवरी, 1983 से 20 फरवरी, 1986 तक तीन साल की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 6208 (फा. सं. 203/242/82-आ. का.नि.II)]

गिरीश दवे, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 1985

INCOME-TAX

S.O. 2106.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income tax Rules, 1962 under the category Institution" in the area of other natural and applied sciences, subject to the following conditions :—

(i) That the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology, Trivandrum will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology, Trivandrum."

This Notification is effective for a period of three years from 21st February, 1983 to 20th February, 1986.

[No. 6208 F. No. 203/242/82-ITA. II]

GIRISH DAVE, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1985

का. आ. 2107 :— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा डा. पी. डी. ओझा को 29 अप्रैल, 1985 से आरम्भ होने वाली और 28, अप्रैल 1990 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रुप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 7/4/85-बी.ओ.-I]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 27th April, 1985

S.O. 2107.—In pursuance of clause (a) of sub section (1), read with sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby appoints Dr. P. D. Ojha as Deputy Governor of the Reserve Bank of India for the period commencing on April 29, 1985 and ending with April 28, 1990.

[No. F. 7/4/85-BO. I]

का. आ. 2108 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खंड 8 के उपखंड (i) के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री एम. एन. गोईपोड़िया को 29 अप्रैल, 1985 से आरम्भ होने वाली और 28 अप्रैल, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रुप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/23/85-बी. ओ. -I(i)]

S.O. 2108.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri M. N. Goiporia as the Managing Director of Central Bank of India for a period commencing on April 29, 1985 and ending with April 28, 1988.

[No. F. 9/23/85-BOI(i)]

का. आ. 2109 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 के उपखंड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय

रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री एम. एन. गोई-पोड़िया को जिन्हें 29 अप्रैल, 1985 से सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/23/85-बी. ओ.-I(2)]

S.O. 2109.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri M. N. Goiporia, who has been appointed as Managing Director of Central Bank of India with effect from April 29, 1985 to be the Chairman of the Board of Directors of Central Bank of India with effect from the same date.

[No. F. 9/23/85-BO.-I(2)]

का आ. 2110—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 8 के उपखंड (i) के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात श्री प्रेमजीत सिंह को 29 अप्रैल, 1985 से आरम्भ होने वाली और 28 अप्रैल, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/23/85-बी.ओ.-I (3)]

S.O. 2110.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Premjit Singh as the Managing Director of Bank of Baroda for a period commencing on April 29, 1985 and ending with April 28, 1988.

[No. F. 9/23/85-BO.-I(3)]

का. आ. 2111—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 के उपखंड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात श्री प्रेमजीत सिंह को जिन्हें 29 अप्रैल, 1985 से बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से बैंक आफ बड़ौदा के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/23/85-बी.ओ.-I(4)]

एस. एस. हसूरकर, निदेशक

S.O. 2111.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Premjit Singh, who has been appointed as Managing Director of Bank of Baroda with effect from April 29, 1985 to be the Chairman of the Board of Directors of Bank of Baroda with effect from the same date.

[No. F. 9/23/85-BO.-I(4)]

S. S. HASURKAR, Director

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली 18 मई, 1985

का० आ 2112.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स इन्सपैक्शन सर्वे तथा सर्विलेंस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, 26 डी/27 पार्क लेन, कलकत्ता-700016 को इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क ग्रुप-II का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए अधिकरण के रूप में इन शर्तों के अधीन रहते हुए 24 मार्च, 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है कि खनिज तथा अयस्क ग्रुप-II के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन निरीक्षण प्रमाणपत्र देने के लिए संगठन द्वारा चलाई गई निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् के किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगी।

अनूसूची

1. मैंगनीज डायाक्साइड
2. कोयनाईट
3. सिलीमिनाइट
4. जिंक सांद्रित चूर्ण सहित जिंक अयस्क
5. डैड बर्नट तथा केलसिड मैंगसाइट सहित मैंगनेसाइट
6. बैराट्स
7. लाल आक्साइड
8. पीला गैरिक
9. स्टेटाइट
10. फैल्डस्टार

[फा० सं० 5/11/83-ई-आई एण्ड ई-पी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th May, 1985

S.O. 2112.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 24th March, 1985 M/s. Inspection Survey & Surveillance (India) Pvt. Ltd., 26D/27, Park Lane, Calcutta-700016, as an agency for inspection of the Mineral and Ores Group II specified in Schedule annexed hereto prior to export subject to the condition that the organisation shall give adequate facilities to any officer of the Export Inspection Council to examine the method of inspection followed by the organisation in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the Export Minerals and Ores Group-II (Inspection) Rules, 1965.

SCHEDULE

1. Manganese Dioxide
2. Keynite
3. Sillimanite
4. Zinc Ores, including Zinc concentrates
5. Magnesite, including dead-burnt and calcined magnesite.

6. Barytes
7. Red Oxide
8. Yellow Ochre
9. Steatite
10. Feldsper

[F. No. S 5|11|83-EI&EP]

का० आ० 2113—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मैसर्स इन्सपैक्शन सर्वे एण्ड सर्विलैंस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, 26 डी/ 27, पार्क लेन, कलकता-700016 को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1270, तारीख 25 मार्च, 1966 की अनुसूची-II में अकार्बनिक रसायनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में इन शर्तों के अधीन रहते हुए, 24 मार्च, 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है कि अकार्बनिक रसायन के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन निरीक्षण प्रमाण पत्र देने के लिए संगठन के द्वारा चलाई गई निरिक्षण पद्धति की जांच करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् के किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगी।

[फा० सं० 5/11/83-ई आई एण्ड ई पो]

एन० एस० हरिहरन, निदेशक

S.O. 2113.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 24th March, 1985 M|s. Inspection Survey & Surveillance (India) Pvt. Ltd. 26D|27, Park Lane, Calcutta-700016 as an agency for inspection of the Inorganic Chemicals specified in Schedule II annexed to the notification of the Government of India, Ministry of Commerce No. S.O. 1270 dated the 25th March 1966 prior to their export subject to the condition that the organisation shall give adequate facilities to any officer of the Export Inspection Council to examine the method of inspection followed by the organisation in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Rules, 1966.

[F. No. 5|11|83-EI&EP]
N. S. HARIHARAN, Director

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

(बी. एल. अनुभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 1985

आदेश

का. आ. 2114—श्री किशोर उधाराम लूथरिया, 48, पाली हिल, बांदरा, बम्बई-400050 को मर्सीडीज बेंज 240-डी कार के आयात के लिये केवल 1,00,000/- रु. का एक सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/ 1463099, दिनांक 21-11-83 दिया गया था। आवेदक ने उपर्युक्त सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थ हो गया है। आगे यह बताया गया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं किया गया था और इस प्रकार सीमा-शुल्क निकासी परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नही किया गया है।

2 अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने यथोचित न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि आवेदक से मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं. पी/ जे/ 1463099 दिनांक 21/11/83 खो गया है। समय-समय पर यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 के उपखंड 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री किशोर उधाराम लूथरिया को जारी किया गया उक्त मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी/ जे/ 1463099, दिनांक 21-11-83 एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं. ए/आई-पी/175/83-84/ बी एल एस/440]

एन. एस. कृष्णामूर्ति,
उपमुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

(B. L. Section)

New Delhi, the 2nd May, 1985

ORDER

S.O. 2114.—Shri Kishore Udharam Luthria 48, Pali Hill, Bandra, Bombay-400050 was granted a Customs Clearance Permit No. P|J|1463099 dated 21-11-83 for Rs. 1,00,000 only for import of Mercedes Benz 240-D car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced. It has further been stated that the original CCP was not registered with any customs authority and such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P|J| 1463099 dated 21-11-83 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P|J|1463099 dated 21-11-83 issued to Shri Kishore U. Luthria is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[No. A|I-P|175|83-84|BLS|440]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Export For Chief Controller of Imports & Exports

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली 18 मई 1985

का.आ. 2115—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र भाग-II खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 19 जनवरी, 1985 में प्रकाशित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 156 तारीख 1 जनवरी 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

क्रम से 14 पर दर्शित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा :

"14. अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास" ।

[फा.सं. 3(94)/75-ई-आई एण्ड ई-पी.]

एन.एस. हरिहरन, निदेशक

*का.आ. 151 तारीख 1-1-1985.

(Department of Commerce)

New Delhi, the 18th May 1985

S.O. 2115.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with Rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification No. S.O. 156 dated 1st January, 1985 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 19th January, 1985 of Ministry of Commerce.

For the entry appearing at Sr. No. 14 the following shall be substituted :

"14. Chairman, Council for Leather Exports, Madras."

[F. No. 3(94)/75-EI&EP]

N. S. HARIHARAN, Director

*S.O. 156 dated 1-1-1985.

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1985

का. आ. 2116—खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आई. ए. एंड ए. एस. के अधिकारी, श्री सी. आर. भागवत को 22 मार्च, 1985 के पूर्वाह्न से 31 अगस्त, 1987 अर्थात् सरकारी सेवा से उनके सेवानिवृत्त होने की तारीख तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग का वित्तीय सलाहकार नियुक्त करती है ।

[सं. ए-12034/3/85-के. बी. आई. (2)]

एस. बी. गोयल, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 20th April, 1985

S.O. 2116.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, the Central Government hereby appoints Shri C. R. Bhagwat, an Officer of the I.A. & A.S. as Financial Adviser to the Khadi and Village Industries Commission with effect from the forenoon of 22nd March, 1985 upto 31st August, 1987, i.e., the date of his superannuation from Government Service.

[No. A-12034/3/85-KVI(II)]

S. B. GOEL, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1985

आदेश

का० आ० 2117—यत: भारत सरकार, स्वास्थ्य, मंत्रालय की 7 जुलाई, 1984 की अधिसूचना संख्या वी० 11016/3/84-एम ई. (पी.) में भारत सरकार ने निदेश किया है कि "एम. बी बी.एस (कराची विश्वविद्यालय) पाकिस्तान" को चिकित्सा अर्हता को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता माना जाए;

और यत: डा० गुरदास सनमुखदास गुरनानी को, जो उक्त अर्हता रखते हैं फिलहाल धर्मार्थ-कार्य के प्रयोजन के लिए स्वामी सच्चिनन्द अस्पताल, उलहासनगर के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश करती है :—

(i) दो वर्ष की अवधि अथवा

(ii) वह अवधि जब तक डा. गुरदास सनमुखदास गुरनानी उक्त अस्पताल स्वामी सच्चिनन्द अस्पताल, उलहासनगर, बम्बई से सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो, उक्त डाक्टर को मैडिसिन प्रैक्टिस करने की सीमित अवधि होगी ।

[सं. वी. 11016/11/84-एम ई. (पी.)]

चन्द्र भानु, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 27th April, 1985

ORDER

S.O. 2117.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. V. 11016/3/84-ME(P) dated the 7th July, 1984, the Central Government has directed that the medical qualification, MBBS (University of Karachi) Pakistan shall be recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Gurdas Sanmukhdas Gurnani, who possesses the said qualification is for the time being attached to the Swami Sarvanand Hospital, Ulhasnagar for the purposes of charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies :—

(i) a period of 2 years or

(ii) the period during which Dr. Gurdas Sanmukhdas Gurnani is attached to the said Swami Sarvanand Hospital, Ulhasnagar, Bombay whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V-11016/11/84-ME(P)]
CHANDER BHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, मई, 1985

का०आ० 2118—यतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 (1970 का 48 वां) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में आयुर्वेद संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ने डा० आर० एन० सिंह को 11 जुलाई 1984 से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 21 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या का० आ 3259 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना की धारा 3 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित शीर्ष के अन्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:-

1	2	3	4
"लखनऊ विश्वविद्यालय	डा आर० एन० सिंह डीन, आयुर्वेद संकाय लखनऊ,	आयुर्वेद	11-7-1984"

[फा० सी० 26013/1/84-ए० ई०]
हसीब अहमद अवर सचिव,

New Delhi, the 6th May, 1985

S.O.2111.—Whereas in pursuance of clause (b) of Sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), Dr. R.N. Singh has been elected by the Faculty of Ayurveda Lucknow University, Lucknow to be a member of he Central Council of Indian Medicine with effect from the 11th July, 1984.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government makes the following further amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. S.O. 3259, dated the 21st August, 1971, namely :—

In the said notification under the heading "Elected under clause (b) of sub-section 1 of theSection 3"— after the entries relating to the Aligarh Muslim University, the following entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4
"Lucknow University	Dr. R.N. Singh, Dean, Faculty of Ayurveda Lucknow Unive sity, Lucknow	Ayurveda	11-7-1984"

[No. V. 26013/1/84-AE]
HASIB AHMED, Under Secry.

पैट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1985

का. आ. 2119—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 4386 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने की बजाये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. बी. ए. सी से सोकासन जी.जी.एस. I तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य– गुजरात जिला व तालुका — मेहसाणा

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेअर	एआरई	सेन्टीअर
कुकस	318	0	09	24

[सं. O–12016/117/84–ओ एन जी–डी 4]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 27th April, 1985

S.O. 2119.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4286 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From SBAC to SOB. GGS I.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kukas	318	0	09	24

[No. O-12016/117/84-OGN-D-4]

का.आ. 2120.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन. के. 34 से एन. के. जी. जी. एस. I तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहियें।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा–9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रुप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एन. के. 34 से एन. के. जी. जी. एस–I तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य – गुजरात जिला व तालुका – मेहसाणा

गांव	सं नं.	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीअर
भटारिया	72/3	0	09	40
	72/2	0	10	60
	71/1ए	0	07	20
	71/2ए	0	02	70
	71/3ए	0	04	90
	71/4	0	07	90
	65/1	0	07	70
	65/2	0	10	80
	65/3	0	03	40
	65/7	0	14	90
	64/9	0	09	20
	87	0	10	90

[सं. O–12016/47/85 – ओ एन जी – डी 4]

S.O. 2120.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NK-34 to NK GSS I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from K-34 to N KGGS I

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bhataria	72/3	0	9	40
	72/2	0	10	60
	71/1A	0	07	20
	71/2A	0	02	70
	71/3A	0	04	90
	71/4	0	07	90
	65/1	0	07	70
	65/2	0	10	80
	65/3	0	03	40
	65/7	0	14	90
	64/9	0	09	20
	87	0	10	90

[No. O-12016/47/85-ONG-D4]

का. आ. 2121.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०आ० सं० 4579, तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन. के. 9 से एन. के. जी. जी. एस.I तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य – गुजरात जिला व तालुका – मेहसाणा

गांव	ब्लाक न.	हेक्टेअर	एआरई	सेन्टीअर
मेमदपुरा	54	0	14	88
	कार्ट ट्रेक	0	01	32
	48	0	01	44
	53	0	12	96
	53	0	02	40

[सं O–12016/131/84–ओएनजी–डी4]

S.O. 2121.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4579 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From NK-9 to GGS-I

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Mehmedpura	54	0	14	88
	cart track	0	01	32
	48	0	01	44
	53	0	12	96
	53	0	2	40

[No. O-12016/131/84-ONG-D 4]

का. आ. 2122.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरवराह के लिये नामरूप, जिला डिब्रूगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप III एक्सपैन्शन योजना के लिये ओ. एन. जी. सी. जी. जी. एस. न. एक (सी. टी. एफ.) लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, नामरूप तक पाइप लाइन आयल गैस कम्पनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्‌द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपायुक्त शिवसागर, आसाम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ओ. एन. जी. सी. जी. एस. नं. एक, लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना

राज्य — आसाम जिला — शिवसागर तालुक — अभयपुर

गांव	पट्टा नं.	दाग नं.	परिक्षा बी.	क.	ल.
आइदेवबारी					
काठनी (द्वितीय भाग)	30 नं. मियादी	362	—	1	2
	कुल क्षेत्रफल		0	1	2
आइदेव बारी चाय बगीचा पहला भाग	21 नं. मियादी	47	1	4	19
	24 " "	48	—	1	17
	34 " "	98	—	1	2
	72 " "	113	—	4	19
	एकसाला	396	—	0	18
	"	99	—	1	4
	"	105	—	0	11
	"	691	—	0	4
	"	180	—	2	8
	कुल क्षेत्रफल		1	3	2

[सं. O-12016/9/85-ओएनजी-डी 4]

S.O. 2122.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for Expansion Project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup, District Diburgarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl. No. 1 (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Duliajan;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority viz Deputy Commissioner|Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Abhoypur

Name of Village	Patta No.	Dag No.	Area
Aideo Bari T.E. Part 1.	Annual Patta	396	0B-0K-18L
	—do—	99	0B-1K-4L
	—do—	105	0B-0K-11L
	—do—	691	0B-0K-4L
	—do—	180	0B-2K-8L
	P.P.No.24	47	1B-4K-19L
	—do—	48	0B-1K-17L
	P.P.No.34	98	0B-1K-2L
	P.P.No. 72	113	0B-4K-19L
	Sub-Total		4B-3K-2L
Aidoo Bari Kathoni Part 2.	P.P.No.30	362	0B-1K-2L.
	Sub-Total		0B-1K-2L
	Grand-Total		4B-4K-4L.

[No. O-12016/9/85-ONG-D 4]

का. आ. 2123.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिये नामरूप जिला डिब्रूगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप III एक्सपैन्शन योजना के लिये ओ.एन.जी.सी.जी.एस.नं.एक (सी.टी.एफ.), लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम में नामरूप तक पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपायुक्त शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ओ. एन. जी. सी. जी. एस. नं. 1 लाकुआ से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना

राज्य — असम जिला — शिवसागर तालुक — अभयपुर

गांव	पट्टा नं.	दाग नं.	एरिया बी. क. ल.		
1	2	3	4		
न. कचारी	35 नं. मियादी	250	—	3	1
	35 " "	251	—	0	17
	35 " "	252	—	1	15
	79 " "	253	—	0	18
	80 " "	254	—	1	8
	एकसाना	264	—	4	3
	2 " "	265	—	2	0
	2 " "	111	—	2	2
	2 " "	266	—	0	15
	22 " "	269	—	1	15
	8 " "	270	—	3	12
	14 " "	274	—	0	1
	एकसना	273	—	2	2
	16 " "	275	—	2	13
	25 " "	278	—	3	4
	60 " "	279	—	1	6
	31 " "	281	—	1	8
	31 " "	282	—	0	18
	4 " "	283	—	0	17
	45 " "	204	—	3	13
	45 " "	199	—	4	10
	32 " "	200	—	3	6
	78 " "	258	—	0	2
	एकसाना	101	—	0	4
	80 " "	355	—	3	17
	45 " "	109	—	3	6
	32 नं. मियादी	121	—	0	12
	32 " "	123	—	1	11
	32 " "	103	—	1	0
	एकसना	312	—	0	9
	" "	313	—	4	9
	18 " "	314	—	0	5
	21 " "	318	—	4	9
	23 " "	119	—	1	4
	29 " "	343	—	0	18
	कुल क्षेत्रफल		13	3	10

[सं. O-12016/4/85 आरक्षक-डा 4]

S.O. 2123.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for expansion Project-III of M/s Hindustan Fertilizer Corpn., Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl. No. 1 (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd, Namrup by Assam Gas Company Limited, Duliajan.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority viz. Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Abhoypur

Name of Village	Patta No.	Dag No.	Area
1	2	3	4
Na Kachari	P.P.No.35	250	0B-3K-1L
	—do—	251	0B-0K-17L
	—do—	252	0B-1K-15L
	P.P.No. 79	253	0B-0K-18L
	P.P.No. 80	254	0B-1K-8L
	Annual Patta	264	0B-4K-3L
	P.P.No.2	265	0B-2K-0L
	—do—	111	0B-2K-2L
	—do—	266	B-0K-15L
	P.P.No.22	269	0B-1K-15L
	P.P.No. 8	270	0B-3K-12L
	P.P.No.14	274	0B-0K-1L
	Annual Patta	273	0B-2K-2L
	P.P.No.16	275	0B-2K-13L
	P.P.No. 25	278	0B-3K-4L
	P.P.No. 60	279	0B-1K-6L
	P.P.No.31	281	0B-1K-8L

1	2	3
P.P. No. 31	282	OB-0K-18L
P.P.No. 4	283	OB-0K-17L
P.P.No. 45	204	OB-3K-13L
—do—	199	OB-4K-10L
P.P.No.32	200	OB-3K-6L
P.P.No.78	258	OB-0K-2L
Annual Patta	101	OB-0K-4L
P.P.No.89	355	OB-3K-17L
P.P.No.45	109	OB-3K-6L
P.P.No.32	121	OB-0K-12L
—do—	123	OB-1K-11L
—do—	103	OB-1K-0L
Annual Patta	312	OB-0K-9L
—do—	313	OB-4K-9L
P.P.No.18	314	0B-0K-5L
P.P.No. 21	318	0B-4K-9L
P.P.No.23	119	0B-1K-4L
P.P.No. 29	343	0B-0K-18L
	Total :—	13B-3K-10L

[No. O-12016/4/85—ONG-D 4]

29 अप्रैल 1985

का. आ. 2124.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन. के. एफ. ई. (186) से एन. के. जी.जी. एस. 1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एन.के.एफ.ई. (186) से एन. के. जी.जी. एस-1 तक पाईप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य-गुजरात जिला-अहमदाबाद तालुका-विरमगाम

गांव	सं. नं.	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीअर
भटारीया	कार्ट ट्रेक	0	01	68
	30/1	0	18	96
	कार्ट ट्रेक	0	00	48
	31/1	0	02	40
	55/पी	0	08	70
	54/2	0	05	52
	55	0	04	02

[सं. O-12016/45/85-ओ. एन जी-डी 4)]

New Delhi, the 29th April, 1985

S.O. 2124.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKFE (186) to NKGGSI in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

PIPELINE FROM D.S.No. NKFE (186) TO NK GGS—I.

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam.

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bhatariay . .	C.T.	0	01	68
	30/1	0	18	96
	C.T.	0	00	48
	31/1	0	02	40
	55/P	0	08	70
	54/2	0	05	52
	55	0	04	02

[No. O—12016/45/85—ONG-D4]

का. आ. 2125.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य एस.बी.डी.आर. सीटीएफ सोभासन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. बी. डी. आर. से सीटीएफ सोभासण तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य-गजरात जिला और तालका-मेहसाणा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेअर	एआरई	सेन्टीअर
रामपूरा	177	0	02	28
	187	0	09	72
	188	0	03	00
	190	0	07	74

[सं. 0-12016/44/85-ओ.एन.जी. डी-4]

S.O. 2125.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SBDR to CTF Sobhasan in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

PIPELINE FROM SBDR TO CTF SOB

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hect-are	Are	Centi-are
Rampura . .	177	0	02	28
	187	0	09	72
	188	0	03	00
	190	0	07	74

[No. O-12016/44/85-ONG D-4

का. आ. 2126.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस.डी.डी.डी. से सी.टी. एफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एच. डी. डी. से सी. टी. एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य-गुजरात जिला-भरुच तालुका-अंकलेश्वर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीअर
पारडी-हंड्रीस	109	0	11	38
	111	0	17	03
	113	0	18	85
	116	0	08	58

[सं. O-12016/46/85-ओ एम.जी-डी-4]

S.O. 2126.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SDDD to CTF in Gujarat State pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl. No. 1 (CTF), And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisi-Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority viz. Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commis-Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No.SDDD to C.T.F.
State, Gujarat: District Bharuch, Taluka: Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Pardi Indris	109	0	11	38
	111	0	17	03
	113	0	18	85
	116	0	08	58

[No. O-12016/46/85—ONG-D4]

का. आ. 2127.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिये नामरूप, जिला डिब्रुगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की नामरूप III एक्सपैन्शन योजना के लिये ओ. एन. जी. सी./जी. जी. एस. नं. एक (सी. टी. एफ.), (लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, नामरूप तक पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड (दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपायुक्त शिवसागर, आसाम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

ओ.एन.जी.सी.जी. एस. नं. एक लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना

राज्य—आसाम जिला—शिवसागर तालुक—सापेकाट

क्र. सं.	गांव	पट्टा नं.	दाग नं.	एरिया		
				बी.	क.	ल.
1.	2 नं. मेडला-जान	6 नं. मियादी	150	—	1	17
		6 नं. मियादी	149	—	0	18
		6 नं मियादी	152	—	2	19
		एकसना	153	—	3	6
	कुल क्षेत्रफल			1	4	0

[सं. O-12016/13/85-ओएनजी-डी 4]

S.O. 2127.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for Expansion Project-III of M/s. Sindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G.Sl. No. 1 (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fartilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Duliajan;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipaline under the land to the competent Authority viz. Deputy Commissoner/Addi. Deputy Commissioner, Sibsagar Bistrict, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a lagal practitioner.

LAND SCHEDULE

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Sapekhat

Name of village	Patta No.	Dag No.	Area
Modela jan No. 2	P.P. No. 6	150	0B-1K-17L
		149	0B-0K-18L
		152	0B-2K-19L
	Annual Patta	153	0B-3K-6L
	Total		1B-4K-0L

[No.O—12016/13/85—ONG D-4]

का.आ. 2128.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिए नामरूप, जिला डिब्रुगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप III एक्सपैन्शन योजना के लिये ओ. एन. जी. सी. जी. जी. एस. नं. एक (सी. टी.

एफ.), (लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, नामरूप तक पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड, डुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार को उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप, सक्षम अधिकारी, उपायुक्त, शिवसागर, आसाम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत

अनुसूची

ओ. एन. जी. सी. जी. एस. नं. एक लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना

राज्य—आसाम जिला—शिवसागर तालुक—सांपेकाठी

क्र. सं.	गांव	पाटा नं.	धाग नं.	एरिया बी.	क.	ल.
1	2	3	4		5	
1.	बरहू गांव	एकसना 8 नं.	313	—	1	11
		मियादी 38 नं.	318	—	0	15
		मियादी 104 नं.	369	—	2	15
		मियादी 38 नं.	374	—	1	4
		मियादी 38 नं.	375	—	2	15
		मियादी 105 नं.	376	—	1	17
		मियादी 105 नं.	368	—	3	6
		मियादी 51 नं.	771	—	2	2
		मियादी	577	1	0	10
		कुल क्षेत्रफल		4	1	15

[सं. O-12016/5/85-ओ.एन.जी.-डी 4]

S.O. 2128.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for Expansion Project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl No. I (CTF), Lakwa to M/s Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Dulliajan;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Gooevernment hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, may, within 21 days from the date of this notifications object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority viz. Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar, District, Sibsagar, Assam;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

State : Assam District : SIBSAGAR Taluk Sapekhati

Name of village	Patta No.	Dag No.	Area
	Annual Patta	313	0B–1K–11L
	P.P.No.8	318	0B–0K–15L
BOROH GAON			
	P.P.No. 38	369	0B–2K–15L
	P.P.No. 104	374	0B–1K–4L
	P.P.No. 38	375	0B–2K–15L
		376	0B–1K–17L
	P.P.No. 105	368	0B–3K–6L
		771	0B–2K–2L
	P.P.No. 51	577	1B–0K–10
		Total	4B–1K–15L

[No. O—12016/5/85—ONG-D4]

नई दिल्ली, 1 मई, 1985

का.आ. 2129. यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिए नामरूप जिला डिब्रुगढ़, असम में हिन्दुस्तान—

उर्वरक निगम की नामरूप III एक्सपैन्शन योजना के लिए ओ.एन.जी.सी. जी. जी. एस. एन. एक (सी.टी.एफ.), लाकुआ से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप, तक पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन) अतिधनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग को अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपायक्त, शिवसागर, आसाम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ओ.एन.जी.सी.जी. एस. नं. एक, लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना

राज्य : आसाम जिला : शिवसागर तालुक : सापेकाठी

क्रम सं.	गांव	पट्टा नं.	दाग नं.	एरिया बी.	क.	ल.
1.	धरम पाथार गांव	66 नं. मियादी	281	—	3	10
		66 ,, ,,	288	—	1	15
		9 ,, ,,	283	—	1	11
		9 ,, ,,	284	—	0	15
		9 ,, ,,	285	—	2	2
		9 ,, ,,	286	—	1	17
		एकसना	239	—	3	1
		33 ,, ,,	237	—	2	4
		कुल क्षेत्रफल		3	1	15

[सं. O-12016/8/85-ओएनजी-डी4]

New Delhi, the 1st May, 1985

S.O. 2129.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for Expansion Project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corp. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be said from ONGC, G|G. Sl. No. 1 (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Dullijan;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Goovernment hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority viz. Deputy Commissioner|Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam,

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Sapekkhat

Name of Village	Patta No,	Dag No.	Area
Dharama Pathar	P.P. No. 66	281	0B-3K-10L
		288	0B-1K-15L
	P.P.No. 9	283	0B-1K-11L
		284	0B-0K-15L
		285	0B-2K-2L
		286	0B-1K-17L
	P.P.No. 33	237	0B-2K-4L
	Annual Patta	239	0B-3K-1L
		Total	3B-1K-15L

[No. O-12016/8/85-ONG-D4]

का.आ. 2130:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिए नामरूप जिला डिब्रुगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की नामरूप III एक्सपैन्शन योजना के लिए ओ.एन.जी.सी.जी.जी.एस.न.एक (सी.टी.फ.), लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, नामरूप तक पाईप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग को अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपायक्त, शिवसागर, आसाम के कार्यालय इस में अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ओ.एन.जी.सी.जी.एस. नं० एक, लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना।

राज्य : आसाम जिला : शिवसागर तालुक : बरासाली

क्र. सं.	गांव	पट्टा नं.	दाग नं.	एरिया बी.	क.	ल
1. उत्तर सोन्दार 2 भाग	30 सना मियादी	450		1	1	12
		कुल क्षेत्रफल		1	1	12
1. उत्तर सोन्दार, 3 भाग	86 नं. मियादी	771		—	0	13
	30 ,, ,,	774		—	1	17
	एकसना	777		—	3	19
	,,	778		—	1	9
	,,	779		—	2	19
	,,	780		—	1	0
	,,	785		—	2	15
	,,	781		—	2	19
	,,	790		—	0	18
	,,	803		—	3	6
	,,	804		—	1	8
	,,	808		—	1	17
	108 नं. मियादी	802		—	1	6
	49 ,, ,,	805		—	1	19
	109 ,, ,,	810		—	3	6
		कुल क्षेत्रफल		7	3	3

[सं. O-12016/17/85-ओ एन जी-डी4]

S.O. 2130.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for Expansion Project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC G.G. Sl. No 1 (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Dullajan.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority viz. Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Village	Name of Mauza	Patta No	Dag No	Area
I.	Uttar Bora-Somdar Chali	30 Yrs Periodical	450	1B-1K-12L	
II and part III		P.P.No. 86	771	0B-0K-13L	
		30 Yrs. Periodcal	774	0B-1K-17L	
		Annual	777	0B-3K-19L	
		Annual	778	0B-1K-9L	
		Annual	779	0B-2K-19L	
		Annual	780	0B-1K-0L	
		Annual	875	0B-2K-15L	
		Annual	781	0B-2K-19L	
		Annual	790	0B-0K-18L	
		P.P. No. 108	802	0B-1K-6L	
		Annual	803	0B-3K-6L	
		Annual	804	0B-1K-8L	
		P.P.No. 49	805	0B-1K-19L	
		Annual	808	0B-1K-17L	
		P.P.No.106	810	0B-3K-6L	
		Total area to be taken			7B-3K-3L

[No. O-12016/17/85-ONG-D4]

का० आ० 2133. यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिए नामरूप, जिला डिब्रूगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की नामरूप III एक्सपैन्शन योजना के लिए ओ.एन.जी.सी.जी.जी एस. नं एक (सी.टी.एफ.) लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, नामरूप तक पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड, दुलिआजान द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपायुक्त, शिवसागर, आसाम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ओ.एन.जी.सी.जी.एस. नं एक लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइपलाइन बिछाना।

राज्य : आसाम जिला : शिवसागर तालूक : सापेकाटी

क्रम सं.	गांव	पाटा नं.	दाग नं.	एरिया बी.	एरिया क.	एरिया ल.
1.	बर-बरूवा खाट गांव एरजा 1, 2 भाग	33 नं. मियादी	195	——	0	4
			196	—	0	4
			कुल क्षेत्रफल	0	0	8

[सं. O-12016/8/85-ओ एन जी-डी 4]

S.O.2131.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for expansion Project-III of M|s. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl. No. 1 (CTF), Lakwa to M|s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Duliajan.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962 the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may within 21 day from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority viz., Deputy Commissioner|Addl. Deputy Commsisioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

LAND SCHEDULE

State : Assam, District : Sibsagar, Taluk : Sapekhati

Name of village	Patta No.	Bag No.	Area
	P.P. No. 33	195	0B-0K-4L
Borbarua Khat	Annual Patta	196	0B-0K-4L
		Total	0B-0K-8L

[No. O-12016/8/85—ONG-D-4]

का.आ. 2132—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिए नामरूप, जिला डिब्रूगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप III एक्सपेंशन योजना के लिए ओ.एन. जी.सी.जी.जी.एस.नं. एक (सी.टी.एफ.) लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपायुक्त शिवसागर, आसाम की कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ओ.एन.जी.सी.जी.एस. नं० एक लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइपलाइन बिछाना।

राज्य : आसाम जिला : शिवसागर तालुक : अभयपूर

क्रम सं.	गांव	पाटा नं.	दाग नं.	एरिया बी.	एरिया क.	एरिया ल.
1.	बनफेरा ग्राण्ट	1 नं. मियादी	13	2	4	2
		,, ,,	6	——	2	6
		,, ,,	47	——	2	11
		,, ,,	56	——	0	4
		,, ,,	55	——	3	17
		,, ,,	61	1	4	11
		,, ,,	60	——	3	13
		1 नं. 30 साल मियादी	54	——	0	4
		,,	59	2	3	11
			कुल क्षेत्रफल	9	4	19

[सं. O-12016/14/85-ओ.एन.जी.-डी 4]

S.O. 2132.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for expansion Project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl. No. I (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Duliajan.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority viz. Deputy Commission/Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

LAND SCHEDULE

State : Assam District: Sibsagar Taluk : Abhoypur

Name of Village	Patta No.	Dag No.	Area
	P.P. No. 1	13	2B-4K-2L.
	(30 Years)	6	0B-2K-6L.
Banfera Grant		47	0B-2K-11L.
		56	0B-0K-4L.
		55	0B-3K-17L.
		54	0B-0K-4L.
		59	2B-3K-11L.
		60	0B-3K-13L.
	T.P. No.1	61	1B-4K-11L.
		Total	9B-4K-19L.

[No. O-12016/14/85-ONG-D 4]

का.आ. 2133.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ. सं. 4530 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस.बी.ए.सी. से सोभासन जी.जी.एस. I तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाणा

गांव	स.नं.	हैक्टेयर	एआर	सेन्टीआर
मेहसाणा	2004/170	0	10	44
	2004/171	0	06	84
	2004/163	0	12	36
	2004/161/2	0	14	52
	2004/156	0	15	00

[सं. O-12016/132/84-ओ.एन.जी.-डी 4]

S.O. 2133.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4580 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SBAC to SOB. GGS I.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Mehsana	2004/170	0	10	44
	2004/171	0	06	84
	2004/163	0	12	36
	2004/161/2	0	14	52
	2004/156	0	15	00

[No. O-12016/132/84-ONG-D4]

का०आ० 2134—यतःकेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कुवां नं एस. ई. डी. 'अ' से वाटर इंजैक्शन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वार्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना अवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फ़त ।

अनुसूची

कुवां नं०अ०एस० ई०डी०'अ' से वाटर इजेक्शन तक पाइपलाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : महैसाना तालूका : कडी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	आरके	सेन्टीन्यर
कडी	1953	0	05	00
	1857	0	06	15

[सं० O-12016/42/85-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2134.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. SED-'A' to Water Injection in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. SED 'A' to Water Injection

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Kadi	1953	0	05	00
	1857	0	06	15

[No. O-12016/42/85-ONG-D4]

का० आ० 2135—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वायर वेड और एनोड बेड तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वार्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना अवश्यक है ।

अतः अबः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने को अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फ़त ।

अनुसूची

वायर बेड और एनोड बेड पाइपलाइन

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा ता० : कडी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
वालावाडी	248	0	01	20
	250	0	01	25

[सं० O-12016/43/85-ओ एन जी-डी 4]

S.O. 2135.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleom from Wire Bed and ANODE BED in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from WIRE BED & ANODE BED

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen tiare
Valavadi	248	0	01	20
	250	0	01	25

[No. O-12016/43/85-ONG-D4]

नई दिल्ली, 8 मई, 1985

का. आ. 2136:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मेवाड-4 से सोकासन—68 से सोकासन—54 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बडोदरा—9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी करेगा कि कथन क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

मेवाड-4 से सोकासन-68 से सोकासन-54 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाणा

गांव	सर्वे.नं.	हैक्टेयर	आरई	सेन्टीयर
मेवड	403	0	04	80

[सं. O-12016/55/85-ओ एन जी-डी 4]

New Delhi, the 8th May, 1985

S.O. 2136.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Mevad-4 to Sob-68 to Sob-54 in Gujarat State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gos Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road,Vadodara (390009.)

And every peerson making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from MEVAD-4 to SOB-68 to SOB-54

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Mevad	403	0	04	80

[No. O-12016/55/85-ONG-D4]

का. आ. 2137—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन.के.इ.टी. से रेलवे क्रासिंग तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करना का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एन.के.ई.टी. से रेलवे क्रासिंग तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : बिरमगाम

गांव	सर्वे.नं.	हैक्टेयर	ए आर	ई सेन्टीयर
सुजपुरा	85/7	0	11	64
	86/4	0	07	44
	86/1	0	17	00

[सं. O-12016/48/85-ओ एन जी-डी 4]

S.O. 2137.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKET to Rly. Crossing in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKET to Railway Crossing

State : Gujarat District : Ahmedabad

Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Sujpura	85/7	0	11	64
	86/4	0	07	44
	86/1	0	17	00

[No. O-12016/48/85-ONG-D4

का.आ. 2138—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन.के.इ. ब्लेड से एन के सी एच से एन के जी जी एस तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एन.के.इ. ब्लेड से एन.के.सी.एच. से एन.के.जी.जी.एस. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : बिरमगाम

गांव	सर्वे.नं.	हैक्टेयर	ए आर	ई सेन्टीयर
भटारीया	46/1	0	02	40
	46/5	0	00	96
	46/3	0	06	48

[सं. O-12016/49/85-ओ एन जी-डी-4]

का०आ० 2140—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सोकासण-26 से सोकासण-18 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनो को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप स हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

सोकासण-26 से सोकासण-18 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य-गुजरात जिला और तालुका—मेहसाना

गाव	सं०नं०	हैक्टेयर	एआर ई सेंटीआर-
जगुदण	98	0	04 20
	97	0	07 32
	96	0	11 28

[सं० O-12016/51/85-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2140.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Sobhasan-26 to Sobhasan-18 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara (390009)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from SOB-26 to SOB-18

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Jagudan	98	0	04	20
	97	0	07	32
	96	0	11	28

[No. O-12016/51/85-ONG-D4]

का०आ० 2141—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे एन०के०जी० एल० से एन०के०सी०एल० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एन०के०जी०एल० से एन०के०ई०एल० तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य-गुजरात जिला-मेहसाणा तालुका-कड़ी

गांव	सं०नं०	हैक्टेयर	एआर ई सेंटीयर
	650	0	06 36
सूरज	653/1	0	09 12
	653/2		
	654	0	18 48
	654	0	08 16

[सं० O-12016/52/85-ओ०एन०जी-डी-4]

S.O. 2141.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKGL to NKCL in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interestat in the said land may, within 21 days from the date of this nctification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009)

And every person making such an objection srall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from NKGL to NKEL

State : Gujarat District : Mehsana

Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Suraj	650	0	06	36
	653/1	0	09	12
	653/2			
	654	0	18	48
	654	0	08	16

[No. O-12016/52/85-ONG-D4]

का०आ० 2142—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन०के० 141 से एन०के०जी० जी०एस० III तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देख-भाल प्रभाग मकरपुरा रोड, वडोदरा–9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एन०के० 141 से एन०के० जीजी एस III तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य--गुजरात जिला- अहमदाबाद तालुका–विरमगाम

गांव	सर्वे०	हैक्टेयर	ए आर ई	सेंटीयर
तेलावी	33	0	06	36
	34	0	05	52
	35	0	20	46
	कार्ट ट्रैक	0	00	72

[सं० O-12016/53/85-ओ०एन० जी०-डी 4]

S.O. 2142.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NK-141 to NK-GGSIII in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, withn 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara(390009)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from NK-141 to NK GGS III.

State : Gujarat District : Ahmedabad

Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Telavi	33	0	06	36
	34	0	05	52
	35	0	20	46
	Cart track	0	00	72

[No. O-12016/53/85-ONG-D4]

का०आ० 2143—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एनकेईपी से एनकेजीजीएस–II तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा–9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाल हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एनकेईपी से एनकेजीजीएस II तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य–गुजरात जिला–अहमदाबाद तालुका–विरमगाम

गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर	एआर ई	सेंटीयर
बालसासण	387/4	0	03	18
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	388/2	0	06	72
	392/2	0	13	44
	393	0	07	56
	394	0	06	12
	कार्ट ट्रेक	0	00	72
	402/पी	0	03	12
	402/पी	0	03	12
	402/पी	0	03	00
	402/पी	0	03	60
	413	0	04	08

[सं० O-12016/54/85 ओ एन जी–डी 4]

S.O. 2143.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKEP to NK GGSII, in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKEP to NK GGS II

State : Gujarat District : Ahmedabad

Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Balsasan	387/4	0	03	18
	Cart track	0	00	60
	388/2	0	06	72
	392/2	0	13	44
	393	0	07	56
	394	0	06	12
	Cart track	0	00	72
	402/P	0	03	12
	402/P	0	03	12
	402/P	0	03	00
	402/P	0	03	60
	413	0	04	08

[No. O-12016/54/85-ONG-D4]

का०आ० 2144—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एनकेईजी से एनकेओ तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि-

कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एनकेईजी से एनकेओ तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—विरमगाम

गांव	सं०नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
मेमदपुरा	44	0	07	08
	46	0	05	72

[सं० O-12016/57/85-ओएनजी-डी 4]

S.O. 2144.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKEG to NKO in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right user therein :

Provided that any person interested in the said land may, wthin 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission Construction & Maintenance Division, Kakarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner :

SCHEDULE

Pipeline from Well No. NKEG to NKO

State : Gujarat District : Ahmedabad

Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Mehmadpura	44	0	07	08
	46	0	05	72

[No. O-12016/57/85-ONG-D4]

का. आ. 2145—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन. के. ई. जी. से एन. के. ओ. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एन. के. ई. जी. से एन. के. ओ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : अमहाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	स. न.	हे.	एआरई.	से.
1	2	3	4	5
भटारीया	12	0	01	08
	13	0	09	16
	11	0	05	04
	10	0	06	66

[सं. O-12016/56/85 ओएनजी-डी 4]

पी. के. राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

S.O. 2145.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKEG to NKO in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline, (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction &. Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKEG to NKO

State : Gujarat District : Ahmedabad

Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bhatariya	12	0	01	08
	13	0	09	16
	11	0	05	04
	10	0	06	66

[No. O-12016/56/85-ONG-D4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(नागरिक पूर्ति विभाग)
भारतीय मानक संस्था
नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1985

का. आ. 2146—समय-समय पर संशोधित भा.मा. संस्था (प्रमाणन मुहर) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि लाइसेंस सं. सीएम/एल—0122014, 0682961, 1127636, 0124826 और 0754859 जिनके विवरण अनुसूची में दिए गए है रद्द कर दिए गए है, क्योंकि कम्पनियों की लाइसेंस जारी रखने में रुचि नहीं है। रद्द करने की तिथि अनुसूची के कालम (6) में प्रत्येक लाइसेंस के सामने दी गई हैं:

अनुसूची

क्र. सं.	लाइसेंस सं० और दिनांक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द लाइसेंस अधीन वस्तु/प्रक्रिया	सम्बद्ध भारतीय मानक	रद्द करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सीएम/ए -0122014 1966-03-03	मैसर्ज जे.के. स्टील, रिशरा हुगली, पश्चिम बंगाल	वाइंडिंग कार्यों के लिए इस्पात के तार रस्से	IS : 1855—1977 खानों में वाइंडिंग और सवारी ढुलाई के लिए इस्पात तार के लड़दार रस्सों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	1983-08-01
2.	सी एम/एल—0682961 1978-03-03	मसर्ज जे.के. स्टील रिशरा, हुगली, पश्चिम बंगाल	जस्तीकृत स्टे स्ट्रैड	IS : 2141—1979 जस्तीकृत स्टे स्ट्रैड की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	1983-08-01
3.	सी एम/एल-1127636 1982-10-22	मैसर्ज जे. के. स्टील, रिशरा, हुगली, पश्चिम बंगाल	खानों में ढुलाई कार्य के लिए इस्पात के तार रस्से	IS : 1856—1971 ढुलाई कार्य के लिए इस्पात के तार रस्सों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	1983-08-01
4	सी एम/एल-0124826 1966-04-22	मेसर्ज जे. के. स्टील, रिशरा, हुगली, पश्चिम बंगाल	सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए इस्पात के तार रस्से	IS : 2266—1977 सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए इस्पात के तार रस्सों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	1983-08-01
5.	सी एम/एल-0754859 1979-02-21	मेसर्ज विश्वास इंजी. कार्पो. 2, एमलिपा मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700056	कृषि कार्य के लिए साफ, ठंडे और ताजा पानी के लिए शैतिज अपकेन्द्री पम्प साइज 80×65 मिमी ड्यूटी प्वाईंट 13 मी उठान पर, निकास 840 लि., प्र. मि. दक्षता 68% पावर निवेश—5.5 किवा	IS : 6999—1980 कृषि कार्य के लिए साफ, ठंडे और ताजा पानी के लिए शैतिज अपकेन्द्री पम्प की विशिष्टि गति 1450 च.प्र.मि.	1984-07-30

[सं. सी एम डी/55 : 12 2014]

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES
(Department of Civil Supplies)
INDIAN STANDARDS INSTITUTION
New Delhi, the 23rd April, 1985

S. O. 2146:—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Ssandards Institution (Certification Marks), Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licences No. CM/L-0122014 0682961, 1127636 & 0124826 & 0754859 particulars of which are given in the schedule have been cancelled as the firms are not interested in retaining the licences. The date of cancellation has been given in Col. (6) of the Schedule against each licence:

SCHEDULE

Sl No	Licence No and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licence Cancelled	Relevant Indian Standards	Date of Cancellation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CM/L—0122014 1966-03-03	M/s J K Steel, Rishra, Hoogly, West Bengal	Steel Wire Ropes for winding purposes	IS : 1855—1977 Specification for standard steel wire ropes for winding and manriding haulages in mines (first revision)	1983-08-01
2	CM/L—0682961 1978-03-03	M/s J K Steel, Rishra, Hooghly, Wess Bengal	Galvanised stay strand	IS . 2141—1979 Specification for galvanized stay strand (second revision)	1983-08-01
3	CM/L—1127636 1982-10-22	M/s J K Steel, Rishtra Hooghly, West Bengal	Steel Wire Ropes for haulage purposes in mines	IS 1856—1977 Specification for steel wire ropes for haulage purposes (second revision)	1983-08-01
4	CM/L—0124826 1966-04-22	M/s J K Steel, Rishra, Hooghly, West Bengal	Steel Wire Ropes for general engineering purposes	IS . 2266—1977 Specification for steel wire ropes for general engineering purposes (second revision)	1983-08-01
5	CM/L—0754859 1979-02-21	M/s Biswas Engg Corpn, 2 Amlipa Mukherjee Road, Calcutta-700056	Horizontal Centrifugal pumps for clear, cold and fresh Water for agricultural purposes : Size 80 × 65mm Speed 1450 RPM Duty Point at 13M head discharge, 840 LPM efficiency 68% power input—3 5kw	IS . 6595—1980 Specification for horizontal centrifugal pumps for clear, cold and fresh water for agricultural purposes	1984-07-30

[No CMD/55 : 122014]

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1985

का आ 2147—भारतीय मानक सस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम और विनियम, 1955 के नियम 3 के उपनियम (2) और विनियम 3 के उपविनियम (2) एव (3) के अनुसार , भारतीय मानक सस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची मे जिन भारतीय मानको के ब्यौरे दिये गये है, वे 1982-05-31 को निर्धारित किये गये है

अनुसूची

क्रम सख्या	निर्धारित भारतीय मानको की पद सख्या और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा रद्द हुए भारतीय मानक की पदसख्या और शीर्षक	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IS . 228 (भाग 13)—1982 इस्पातो के रासायनिक विश्लेषण की पद्धतिया भाग 13 आर्सेनिक ज्ञात करना	—	—
2	IS 995—1982 टेबल चाकुओ डेसर्ट चाकुओ और फल चाकुओ की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS 995—1964 टेबल चाकुओ, डेसर्ट चाकुओ और फल चाकुओ की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	—

1	2	3	4
3.	IS : 1018—1982 पीतल के स्लीवर टाइप मशीन निर्मित तालों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 1018—1961 एम टाइप, पीतल के तालों की विशिष्टि (संशोधित)	—
4.	IS : 1223 (भाग 2)—1982 गर्बर विधि द्वारा दुग्ध वसा ज्ञात करने के उपकरण की विशिष्टि भाग 2 पिपेट और स्वतः मापन उपकरण (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 1223—1958 गर्बर विधि द्वारा पूर्ण दुग्ध वाष्पित (असंतृप्त) दुग्ध, सप्रेटा दुग्ध, मक्खन उतारा दुग्ध, दुग्ध और क्रीम में वसा ज्ञात करने के उपकरण की विशिष्टि	1982-05-31 को निर्धारित
5.	IS : 1251—1973 जिंक फास्फाइड, तकनीकी, की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 1251—1958 जिंक फास्फाइड, तकनीकी की विशिष्टि	1973-06-30 को निर्धारित
6.	IS : 1367 (भाग 12)—1981 चूड़ीदार इस्पात कीलकों की तकनीकी पूर्ति शर्तें भाग 12 चूड़ीदार कीलकों पर फोस्फेट लेपन (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 1367—1967 चूड़ीदार कीलकों की तकनीकी पूर्ति शर्त (प्रथम पुनरीक्षण)	—
7.	IS : 1448 (भाग 107)—1982 पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियां (भाग : 107) स्नेहन तेलों का अवक्षेपणांक	—	—
8.	IS : 1448(भाग : 108)—1982 पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियां (भाग : 108) ठंडे क्रैंकिंग सिम्युलेटर के प्रयोग द्वारा कम तापमान में इंजन-तेलों की स्पष्ट गाढ़ापन	—	—
9.	IS : 2296—1982 प्रदूषण अधीन अंतर भू-सुरातल जल की छूट सीमाएं (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 2296—1974 प्रदूषण अधीन अंतर भू-धरातल जल की छूट सीमाएं	—
10.	IS : 2397—1972 वैफरों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 2397—1963 वैफरों की विशिष्टि	1973-03-31 को निर्धारित
11.	IS : 2404—1972 माल्ट सत्व की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 2404—1963 माल्ट तत्व की विशिष्टि	1972-04-30 को निर्धारित
12.	IS : 2790—1981, 23.3, 22, 21, 18, 14; 12 और 9 कैरट का सोना बनाने के मार्गदर्शी सिद्धांत (प्रथम (पुनरीक्षण)	IS : 2790—1964 14, 12 और 9 कैरट का सोना बनाने के मार्गदर्शी सिद्धांत	—
13.	IS : 3581—1982 हरे कहवे का श्रेणीकरण (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 3581—1974 हरे कहवे का श्रेणीकरण (प्रथम पुनरीक्षण)	—
14.	IS : 3993—1982 उपकरण ट्रे की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 3993—1967 उपकरण ट्रे की विशिष्टि	—
15.	IS : 3997—1982 चोट मलहम, की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 3997—1967 चोट मलहम की विशिष्टि	—
16.	IS : 3998—1982 औषध कणों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 3998—1967 औषध कणों की विशिष्टि	—
17.	IS : 4825—1982 ठोस-तना वाले काँचस्थ द्रव सन्दर्भ थर्मामीटरों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 4825—1968 प्रयोगशाला एवं सन्दर्भ थर्मामीटरों की विशिष्टि	—

1	2	3	4
18.	IS : 5592—1981 मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 5592—1969 मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल की विशिष्टि	—
19.	IS : 6716—1981 बेन्जोइक अम्ल, तकनीकी, की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 6716—1972 बेन्जोइक अम्ल, तकनीकी, की विशिष्टि	—
20.	IS : 6785—1982 अस्थि छेदन क्रिया के लिये अस्थि प्लेट बेनराइट की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 6785—1973 अस्थि छेदन क्रिया के लिये अस्थि प्लेट बेनराइट की विशिष्टि	—
21.	IS : 7013–1981 रेडियो डायल लैंपों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 7013–1973 रेडियो डायल लैंप स्क्रूयूलों की विशिष्टि	—
22.	IS : 7331–1981 आस्पार जल निकास कार्यों के निरीक्षण और अनुरक्षण की रीति संहिता (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 7331–1974 आर-पार जल निकास कार्यों के निरीक्षण और अनुरक्षण की रीति संहिता	—
23.	IS : 8812 (भाग 2)–1982 एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्रधातुओं को जोड़ने के लिये सख्त टांका-मसालों के रासायनिक विश्लेषण की पद्धतियां	—	—
24.	IS : 9819 (भाग 2)–1982 दूरदर्शन चित्र ट्यूबों के साथ प्रयुक्त लाइन निर्गत ट्रांस्फार्मरों की विशिष्टि भाग 2 टाइप लॉट 470 मिमी, 510 मिमी, 590 मिमी और 610 मिमी दूरदर्शन चित्र ट्यूबों के लिये हैं।	—	—
25.	SI : 9829 (भाग 2)–1981 धातु के अस्थि पेचों की विशिष्टि; भाग 2 असमभित चूड़ी, सतत् फिटिंग (गोलाकार) वाले पेंच	—	—
26.	IS : 9860 (भाग 1)–1981 मछली पकड़ने के हुकों की विशिष्टि, भाग 1 कांटेदार हुक।		
27.	IS : 9863–1980 मुर्गी पालन के लिए पोषण संबंधी अपेक्षायें	—	—
28.	IS : 9873 (भाग 1)–1981 खिलौनों संबंधी सुरक्षा-अपेक्षायें; भाग 1 यांत्रिक एवं भौतिक गुणधर्म	—	—
29.	IS : 9878–1981 बिजली की यात्री एवं माल लिफ्टों के लिये सुरक्षा गियरों और गति-नियन्त्रकों की विशिष्टि	—	—
30.	IS : 9888–1981 तार, छड़ और नलिका खींचने की डाई के लिये सख्त धातु (कार्बाइड) के सिंटरित प्लेटों के माप	—	—
31.	IS : 9900(भाग 22)–1981 उच्च दाब पारद वाष्प लैम्पों की विशिष्टि, भाग 2 मानक लैंप दस्त-यंत्र	—	—

1	2	3	4
32.	IS : 9909–1981 विद्युत-हीन मुलम्मा के लिये सक्सिनिक अम्ल की विशिष्टि	—	—
33.	IS : 9917–1981 कैल्सियम से बने ताप स्थायी ग्रीज की विशिष्टि	—	—
34.	IS : 10021–1981 द्रवचालित संस्थापनों के लिये विद्युमन तंत्र के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त	—	—
35.	IS : 10028 (भाग 3)–1981 ट्रांसफार्मरों के चयन संस्थापन और अनुरक्षण की रीति संहिता	—	—
36.	IS : 10070–1982 मोटे मिलावों के अपघर्षण परीक्षण की मशीन की विशिष्टि	—	—
37.	IS : 10074–1982 मिट्टी की हल्की और भारी कुटाई के परीक्षण के लिये कुटाई और सांचा संयोजन की विशिष्टि	—	—
38.	IS : 10097–1982 धातु काटने वाले औजारों की पैकेजबन्दी की रीति संहिता	—	—
39.	IS : 10098–1982 तापन कार्यों के लिये विद्युत अवरक्त उत्सर्जकों की सामान्य अपेक्षायें	—	—
40.	IS : 10104 (भाग 1)–1981 टांका लगाने की सुइयों, की विशिष्टि; भाग 1 बक—1/4, 3/8, 1/2 और 5/8 सर्किल या सीधी	—	—
41.	IS : 10107–1982 कीट नियन्त्रण उपस्कर के लिये द्रव फुहार-गन की विशिष्टि	—	—
42.	IS : 10108–1982 स्थिर पिस्टन वाले पतली भिती के सैम्पलर द्वारा मिट्टी का नमूना लेने की रीति संहिता	—	—
43.	IS : 10109–1981 तेल हाथ स्टोव, आफसेट बर्नर टाइप, की विशिष्टि	—	—
44.	IS : 10113–1981 फोटोग्राफी प्रकाशमिति के लिये इमल्शन अशांकन की अनुशंसित रीति	—	—
45.	IS : 10114–1982 इनैमल कृत और वार्निश लगे कांच रेशा आवृत तांबे के आयताकार तारों की विशिष्टि	—	—
46.	IS : 10116–1982 बोरिक अम्ल की विशिष्टि	—	—
47.	IS : 10117–1982 जंगरोधी इस्पात वस्तुओं की निष्क्रियता की रीति सहिता	—	—
48.	IS : 10124 (भाग 9)–1982 पेय जल पूर्ति के लिये निर्मित पीवीसी फिटिंगों की विशिष्ट, भाग 960° बैंडों की विशिष्ट अपेक्षायें	—	—

1	2	3	4
49.	IS : 10124 (भाग 11)–1982 पेय जल पूर्ति के लिये निर्मित पीवीसी फिटिंगों की विशिष्टि; भाग 11 30° बैंडों की विशिष्ट अपेक्षाएं	—	—
50.	IS : 10124 (भाग 12)–1982 पेय जल पूर्ति के लिये निर्मित पीवीसी फिटिंगों की विशिष्टि– भाग 12 221/2° बैंडों की विशिष्ट अपेक्षायें	—	—
51.	IS : 10124 (भाग 13)–1982 पेय-जल पूर्ति के लिये निर्मित पीवीसी फिटिंगों की विशिष्टि; भाग 13 111/° बैंडों की विशिष्ट अपेक्षायें	—	—
52.	IS : 10124–1982 नोल्स पिन की विशिष्टि	—	—

इन भारतीय मानकों की प्रतियां, भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 में तथा अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, मोहाली, पटना और त्रिवेन्द्रम स्थित इसके शाखा कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

[सं. सीएमडी/13 : 2]

New Delhi, the 24th April, 1985

S. O. 2147:—In pursuance of sub-rule (2) of the Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1982-05-31 :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standards Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Remarks, if any
1	2	3	4
1.	IS : 228(Pt XIII)—1982 Methods for Chemical Analysis of steels Part XIII Determination of Arsenic	—	—
2.	IS : 995—1982 Specification for Table knives, dessert knives and fruit knives (Second Revision)	IS : 995—1964 Specification for table knives, dessert knives and fruit knives (revised)	—
3.	IS : 1018—1982 Specification for padlock,s brazs lever type, machine made (second revision)	IS : 1018—1961 Specification for M type brass padlocks (revised)	—
4.	IS : 1223 (Part II)—1972 Specification for apparatus for determination of milk fat by Gorber Method Part II Pipettes and automatic measures (first revision)	IS : 1223—1958 Specification for Eappartus for the determination of fat in whole milk, evaporated (unsaturated) milk, separated milk, skim milk, butter milk and cream by the Carber Method.	Established on 1973-05-31
5.	IS : 1251—1973 Specification for Zinc phosphide, technical (first revision)	IS : 1251—1958 Specification for Zinc phosphide, technical	Established on 1973-06-30
6.	IS : 1367 (Part XII)—1981 Technical supply conditions for threaded steel fastners Part XII Phosphate coatings on threaded fastners (second revision)	IS : 1367—1967 Technical supply conditions for threaded fasteners (first revision)	—
7.	IS : 1448 (P : 107)—1982 Methods of test for petroleum and its products (P : 107) Precipitation number of lubricating oils.	—	—

1	2	3	4
8.	IS : 1448 (P : 108) 1982 Methods of test for petroleum and its products (P : 108) Apparant viscosity of engine oils at low temperature using the cold-cranking simulator	—	—
9.	IS : 2296—1982 Tolerance limits for inland surface waters subject to pollution (second revision)	IS : 2296—1974 Tolerance limts for inland surface waters subject to pollution (first revision)	—
10.	IS 2397—1972 Specification for wafers (first revision)	IS : 2397—1963 Specification for wafers	Established on 1973-03-31
11.	IS : 2404—1972 Specification for malt extract (first revision)	IS : 2404—1963 Specification for malt extract	Established on 1972-4-30
12.	IS : 2790 -1981 Guidelines for manufacture of 23.3, 22, 21, 18, 14, 12 and 9 carat gold (first revision)	IS : 2790—1964 Guidelines for manufacture of 14, 12 and 9 carat gold	—
13.	IS : 3581—1982 Grading for green coffee (second revision)	IS : 3581—1974 Grading for green coffee (first revision)	—
14.	IS : 3993—1982 Specification for trays, instruments (first revision)	IS : 3993—1967 Specification for trays, instrument	—
15.	IS : 3997—1982 Specification for jars ointment (first revision)	IS : 3997—1967 Specification for jars ointment	—
16.	IS : 3998—1982 Specification for cups, medicine (first revision)	IS : 3998—1967 Specification for cups, medicine	—
17.	IS : 4825—1982 Specification for liquid-in-glass solid-stem reference thermometers (first revision)	IS : 4825—1968 Specification for laboratory and reference thermometers	—
18.	IS : 5592—1981 Specification for monochloroacetic acid (first revision)	IS : 5592—1969 Specification for monochloroacetic acid	—
19.	IS : 6716—1981 Specification for benzoic acid, tehcnical (first revision)	IS : 6716—1972 Specification for benzoic acid, technical	—
20.	IS : 6785—1982 Specification for plate, bone, wainwright, osteotomy (first revision)	IS : 6785—1973 Specification for plate, bone, wainwright, osteotomy	—
21.	IS : 7013—1981 Specification for radio dial lamps (first revision)	IS : 7013—1973 Specification for schedule for radio dial lamps	—
22.	IS : 7331—1981 Code of practice for inspection and maintenance of cross drainage works (first revision)	IS : 7331—1974 Code of practice for inspection and maintenance of cross drainage works.	—
23.	IS : 8812 (Part II)—1982 Methods of chemical analysis of hard solders for jointing aluminium and aluminium alloys Part II Determination of aluminium	—	—
24.	IS : 9819 (Part II)—1982 Specification for line output transformers used with TV picture tubes Part II Type lot is for 470mm, 510mm, 590mm, and 610mm picture tubes	—	—
25.	IS : 9829 (Part II)—1981 Specification for mesal bone screws Part II Screws with asymmetric thread, constant fitting (spherical)	—	—

1	2	3	4
26.	IS : 9860 (Part I)—1981 Specification for fishing hooks Part I Barbed hooks	—	—
27.	IS : 9863—1980 Nutrient requirements for poultry	—	—
28.	IS : 9873 (Part I)—1981 Safety requirements for types Part I Mechanical and physical properties	—	—
29.	IS : 9878—1981 Specification for safety gears and governors for electric passenger and goods lifts	—	—
30.	IS : 9888—1981 Dimensions for sintered pellets of hard metal (carbide) for wire, bar and tube drawing dies	—	—
31.	IS : 9900 (Part II)—1981 Specification for high pressure mercury vapour lamps Part II Standard lamp data sheets	—	—
32.	IS : 9909—1981 Specification for Succinic acid for electroless plating	—	—
33.	IS : 9917—1981 Specification for calcium base heat stable grease	—	—
34.	IS : 10021—1981 Guidelines for deicing system for hydraulic installations	—	—
35.	IS : 10028(Part III)—1981 Code of practice for selection, installation and maintenance of transformers Part III Maintenance	—	—
36.	IS : 10070—1982 Specification for machine for abrasion testing of coarse aggregates	—	—
37.	IS : 10074—1982 Specification for compaction mould assembly for light and heavy compaction test for soils	—	—
38.	IS : 10097—1982 Code of practice for the packaging of metal cutting tools	—	—
39.	IS : 10098—1982 General requirements for electric infra-red emitters for heating purposes	—	—
40.	IS : 10104 (Part I)—1981 Specification for needles, suture Part I Curved—1/4, 3/8, 1/2 and 5/8 circle or straight	—	—
41.	IS: 10107—1982 Specification for hydraulic spray gun for pest control equipment	—	—
42.	IS : 10108—1982 Code of practice for for sampling of soils by thin wall sampler with stationary piston	—	—
43.	IS : 10109—1981 Specification for oil pressure stoves, offset burner type	—	—
44.	IS : 10113—82 Recommended practice for calibration of emulsion for photographic photometry	—	—
45.	IS : 10144—1982 Specification for enamelled and varnish bonded glass fibre covered rectangular copper wires	—	—
46.	IS : 10116—1982 Specification for Boric acid	—	—
47.	IS : 10117—1982 Code of practice for passivation of stainless steel articles	—	—

1	2	3	4
48.	IS : 10124 (Part IX)—1982 Specification for fabricated PVC fittings for postable water supplies Part IX Specific requirements for 60 bends	—	—
49	IS : 10124 (Part XI)—1982 Specification for fabricated PVC fittings for potable water supplies Part XI Specific requirements for 30 bends	—	—
50.	IS : 10124 (Part XII)—1982 Specification for fabricated PVC fittings for potable water supplies Part XII Specific requirements for 22-1/2. bends	—	—
51.	IS : 10124 (PartXIII)—1982 Specification for fabricated PVC fittings for potable water supplies Part XIII Specific requirements for 11-1/4. bends	—	—
52.	IS : 10128—1982 Specification for pin. knowles	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhawan, 9 Bahadu Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices as Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubeneshwar, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Mohali, Patna and Trivendrum.

[No. CMD/13 : 2]

का. आ. 2148 :—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम और विनियम, 1955 के विनियम 3 के उपनियम (2) तथा विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन मानकों के ब्यौरे दिये गये हैं, वे 1982-04-30 को निर्धारित किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	निर्धारित भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा रद्द हुए भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	अन्य विवरण
1	2	3	4
1.	IS : 584—1981 सामान्य कार्यों के लिए फंटियर नमूने की चप्पलों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 584—1964 सामान्य कार्यों के लिए, फंटियर नमूने की चप्पलों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	—
2.	IS : 635—1982 रबड़ के तेल, और विलायक प्रतिरोधी होज की विशिष्टि (तृतीय पुनरीक्षण)	1. IS : 635—1968 बुने वस्त्र के प्रबलन वाले रबड़ के तेल और विलायक प्रतिरोधी होज की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण) और 2. IS : 3418—1968 गूथे वस्त्र के प्रबलन वाले रबड़ के तेल और विलायक प्रतिरोधी होज की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	—
3.	IS : 639—1982 स्वर्ण पत्ती की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 639—1965 स्वर्ण पत्ती के विशिष्टि (पुनरीक्षित)	—
4.	IS : 990—1982 स्टेनलेस इस्पात की चम्मचों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 990—1964 स्टेनलेस इस्पात की चम्मचों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	—

1	2	3	4
5.	*IS : 1067–1981 सजावट और सुरक्षात्मक कार्यों के लिये चांदी के विद्युत-लेपन की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 1067–1968 सजावट और सुरक्षात्मक कार्यों के लिये चांदी के विद्युत-लेपन की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	1982-02-38 को निर्धारित *भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये IS : 1067–1981 1982-10-01 से लागू होगा
6.	*IS : 1258–1979 बायोनेट लैंप-होल्डरों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 1258–1967 बायोनेट लैंप-होल्डरों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	1980-07-31 को निर्धारित *भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये IS : 1258–1979 1983-01-16 से लागू होगा
7.	IS : 1448 (पी : 29)–1982 पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियां भाग 29 जेट वाष्पन द्वारा ईंधनों में विद्यमान गोंद (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS 1448 (पी : 29)–1970 पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियां भाग 29 जेट वाष्पन द्वारा ईंधनों में विद्यमान गोंद (प्रथम पुनरीक्षण)	—
8.	IS : 1493 (भाग 1)–1981 लोह अयस्कों के रासायनिक विश्लेषण पद्धतियां भाग 1 सामान्य घटक ज्ञात करना (प्रथम पुनरीक्षण')	IS : 1493–1959 लोह अयस्कों के रासायनिक विश्लेषण की पद्धतियां	—
9.	IS: 1664–1981 पशुओं के चारे के अनुपूरण के लिये खनिज मिश्रणों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 1664–1968 पशुओं के चारे के अनुपूरण के लिये खनिज मिश्रणों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	1982-01-31 को निर्धारित *भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये, IS : 1664–1981 1982-11-01 से लागू होगा
10.	IS : 1885 (भाग 56)–1981 विद्युत-तकनीकी शब्दावली भाग 56 सूक्ष्मतरंग अवयव और पुर्जे	IS : 1885 (भाग 13/खंड 1)–1968 विद्युत तकनीकी की शब्दावली, भाग 13 दूर-संचार प्रेषण लाइन और तरंग मार्ग-दर्शिकाएं, खंड 1 सामान्य प्रेषण लाइन, और 2. IS : 1885 (भाग 13/अनुभाग 2)–1967 विद्युत तकनीकी शब्दावली, भाग 13 दूरसंचार प्रेषण लाइनें और तरंग मार्ग दर्शिकाएं, खंड 2 सूक्ष्म तरंग प्रेषण लाइन और तरंग मार्गदर्शिकाएं	1982-03-31 को निर्धारित
11.	IS : 2028–1981 खुला जबड़ा रिंचों (पाना) की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 2028–1968 खुला जबडा पाना (प्रथम पुनरीक्षण)	—
12.	IS : 2248–1981 निर्माण कार्य के लिए मिट्टी उत्पादों संबंधी शब्दावली (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 2248–1969 संरचना मिट्टी उत्पादों संबंधी शब्दावली	—
13.	IS : 2269–1981 षटकोणी साकेट हैड कप पेचों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 2269–1967 षटकोणी हैडकप पचों का विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	1982-13-31 को
14.	IS : 2482–1982 रबड़ के जल घुषण होज (हल्के काम के लिये) की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 2482–1963 रबड़ के जल घुषण होज (हल्के काम के लिये) की विशिष्टि	—

1	2	3	4
15.	IS : 2490 (भाग 1)–1981 औद्योगिक मलनिस्स्रावों के लिये सहन-सीमाएं भाग 1 सामान्य सीमाएं (द्वितीय पुनरीक्षण)	1. IS : 2490 (भाग 1)–1974 भूमध्य पानी में डाले जाने वाले औद्योगिक मल-निस्स्रावों के लिये सहन-सीमाएं, भाग 1 सामान्य सीमाएं (प्रथम पुनरीक्षण);	—
		2. IS : 3306–1974 सार्वजनिक मल जल नलों में डाले जाने वाले औद्योगिक मल-निस्स्रावों के लिये सहन-सीमाएं (प्रथम पुनरीक्षण)	—
		3. IS : 3307–1977 सिंचाई कार्यों के लिये भूमि पर डाले जाने वाले औद्योगिक मल निस्स्रावों की सहन-सीमाएं (प्रथम पुनरीक्षण)	—
		4. IS : 7968–1978 समुद्रतटीय क्षेत्रों में डालें जाने वाले औद्योगिक मल निस्स्रावों के लिये सहन-सीमाएं	—
16.	IS : 2523–1982 ऊनी होज टॉप की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 2523–1963 वोर्स्टेड होज टॉप की विशिष्टि	—
17.	*IS : 2713 (भाग 1 से 3)–1980 शिरोपरि पावर लाइनों के लिये नलिकाकार इस्पात के खंभों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 2713–1969 शिरोपरि पावर लाइनों के लिये नलिकाकार इस्पात के खंभों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	*भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये IS : 2713 (भाग 1 से 3)–1980 1980-12-16 से लागू होगा।
18.	IS : 3095–1981 स्वर्ण सामग्रियों में इस्तेमाल के लिये टांकों के मसाले के निर्माण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 3095–1965 स्वर्ण-पात्रों में इस्तेमाल के लिये टांकों के मसाले के निर्माण संबंधी मार्ग-दर्शी सिद्धान्त	—
19.	IS : 3104 (भाग –1982 द्रवघनत्वमापी की विशिष्टि, भाग 1 अपेक्षायें (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 3104–1965 द्रवघनत्वमापी की विशिष्टि	—
20.	IS : 3110–1982 चांदी की पन्नी की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 3110–1965 चांदी की पन्नी की विशिष्टि	—
21.	IS : 3545–1982 मास काटने के गंडासों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 3545–1966 मांस काटने के गंडासों की विशिष्टि	—
22.	IS : 4299–1982 जिग की फीट विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 4299–1967 जिग फीट के माप	—
23.	IS : 4410 (भाग 16/खंड 2)–1981 नदी घाटी परियोजनाओं संबंधी शब्दावली; भाग 16 गेट और वाल्व; खंड 2 वाल्व	—	—
24.	IS : 5000 (ओडी 36)–1981 अर्धचालक युक्तियों के माप युक्ति रूपरेखा 36	—	—

1	2	3	4
25.*	IS : 5082–1981 बिजली के कामों के लिये पिटवां एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्रधातुओं की सरिया छड़ें, तालियो और सैक्सन (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 5082–1969 बिजली के कामों के लिये पिटे एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्रधातुओं की सरिया छड़ें, नलियां और सेक्शन	*भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये IS: 5082–1981 1982-10-01 से लागू होग
26.	IS : 5137–1982 सीमेंट के पतले मसाले की भराई के लिये रबड़ होज की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	(1) IS : 5137–1969 सीमेंट के पतले मसाले की भराई के लिये बुने वस्त्र के प्रबलन वाले रबड़ के होज की विशिष्टि (2) IS : 5166–1969 सीमेंट के पतले मसाले की भराई के लिये गुंथे वस्त्र के प्रबलन वाले रबड़ की होज की विशिष्टि	--
27.	IS : 5665–1982 सोल्डर पहिये की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 5665–1970 सोल्डर पहिये की विशिष्टि	
28.	IS : 5770–1982 सपाट अग्र भाग वाले चपटे फलक, टंगस्टन कार्बाइड की नोक वाले कोयला काटने के औजार, मशरूम की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 5770–1970 सपाट अग्र भाग वाले चपटे फलक, टंगस्टन कार्बाइड की नोक वाले कोयला काटने के औजार, मशरूम की विशिष्टि	--
29.	IS : 6061 (भाग 3)–1981 कड़ियों और पूरक ब्लाकों से फर्श और छत निर्माण की रीति संहिता भाग 3–मिट्टी की पूर्व ढलित खोखली ब्लाक कड़ियों और खोखले पूरक ब्लाकों से	--	--
30.	IS : 6094–1981 पटकोणी सर्किट सेट पेचों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 6094–1971 पटकोणी सर्किट ग्रब पेचों की विशिष्टि	1982-03-31 को निर्धारित
31.	IS : 6313 (भाग 2)–1981 इमारतों में दीमक विरोधी उपायों की रीति संहिता भाग 2—निर्माण पूर्व रासायनिक उपचार उपाय (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 6313–भाग 2–1971 इमारतों में दीमक निरोध की रीति संहिता भाग 2–निर्माण पूर्व रासायनिक उपचार उपाय	
32.	IS : 6595–1980 कृषि कार्यों के लिये साफ, ठंडे ताजा पानी के लिये क्षैतिज अपकेन्द्री पम्पों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS . 6595–1972 कृषि कार्यों के लिये साफ, साफ ठंडे ताजा पानी के लिये क्षैतिज अपकेन्द्री पम्पों की विशिष्टि	1980-09-30 को निर्धारित *भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये IS : 6595–1980 1982-05-16 से लागू होगा ।
33.	*IS : 6901–1981 वैल्डिंग, कटिंग और तत्संबंधित प्रक्रियाओं में काम आने वाले गैस सिलिंडरों के लिये दाब रेगुलेटरों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 6901–1973 वैल्डिंग, कटिंग और तत्संबंधित प्रक्रियाओं में काम आने वाले गैस सिलिंडरों के लिये दाब रेगुलेटरों की विशिष्टि	1982-02-28 को निर्धारित *भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना के प्रयोजनों के लिये IS : 6901–1981 1982-10-01 से लागू होगा
34.	IS : 6992–1982 मस्तिष्क संस्तम्भ कुर्सी, घरेलू माडल, की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 6992–1973 मस्तिष्क संस्तम्भ कुर्सी, घरेलू माडल की विशिष्टि	--

1	2	3	4	5	6
35.	IS : 7178–1982 स्वतः चूड़ीकाट पेचों की तकनीकी पूर्ति शर्तें (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 7178–1974 स्वतः चूड़ीकाट पेचों के यांत्रिक गुण	--		
36.	IS : 7270–1981--80 सें. से 40 सें. तक के तापमानों पर ताप रोधी सामग्रियों के औद्योगिक उपयोग और फिनिशिंग की रीति संहिता (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 7270–1974--80 सें. और 40 सें. के मध्य ताप रोधी सामग्रियों के औद्योगिक उपयोग और फिनिशिंग की रीति संहिता	1982-03-31 को निर्धारित		
37.	IS : 7417–1982 रोग नियंत्रण उपस्करों के लिये द्रवचालित फुहारा टोंटियों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 7417–(भाग 1)–1974 रोग नियंत्रण उपस्करों के लिये द्रवचालित फुवारा टोंटियों की विशिष्टि भाग 1 शंकु और पंखा टाइप	--		
38.	IS : 9001 (भाग 8)–1982 पर्यावरणीय परीक्षण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत, भाग 8 मुहर बंदी परीक्षण	--	--		
39.	IS: 9335 (भाग 2)–1981 बिजली के कार्यों के लिये सेलुलोज कागज की विशिष्टि, भाग 2 परीक्षण पद्धतियां	IS : 2188–1962 बिजली के कार्यों के लिये कागज की परीक्षण पद्धतियां			
40.	IS: 9828–1981 सुवाह्य वातिल सैंडरों की विशिष्टि	--	--		
41.	IS : 9828 (भाग 1)–1981 मेटल बॉन पेंच, असममित की विशिष्टि, भाग 1 चूड़ीदार पेंच, परिवर्ती फिटिंगों के लिये (गोलाकार)	--	--		
42.	IS : 9837–1981 समुद्री तेल के अपकेन्द्री शोधकों की परीक्षण संहिता	--	--		
43.	IS : 9873 (भाग 2)–1981 खिलौनों की सुरक्षा अपेक्षायें, भाग 2 विष संबंधी	--	--		
44.	IS : 9893–1981 पूर्व ढलित कंक्रीट सरदल और देहली की विशिष्टि	--	--		
45.	IS : 9908–1981 फार्मिक अम्ल की विशिष्टि	--	1982-03-31 को स्थापित		
46.	IS : 9934–1981 कृषि-ट्रैक्टर चालक की सुरक्षा और आराम की मार्ग दर्शिका	--	--		
47.	IS : 9935–1981 पावर हलों की परीक्षण संहिता	--	--		
48.	IS : 9957–1981 उन्दी तेल की विशिष्टि	--	--		
49.	IS : 9960-1981 धारित्र संसेचक के रूप में इस्तेमाल के लिये बिजली ग्रेड अरंडी के तेल की विशिष्टि	—			

1	2	3	4
50.	IS: 9992–1981 तरल कीटनाशकों के लिये गोल और आयताकार टीन के डिब्बों की विशिष्टि	—	1982-03-31 को निर्धारित
51.	IS : 9993–1981 तेल निकालने के लिये धूपा गिरी का श्रेणीकरण	—	—
52.	: IS 10000 (भाग 4)–1980 अन्त-र्दहन इंजनों की परीक्षण पद्धतियां, भाग 4 पावर, दक्षता ईंधन खपत और चिकनाई तेल की खपत बताना	—	—
53.	IS : 10006–1981 तेल निकालने के लिये नाहोर की गिरी का श्रेणीकरण	—	—
54.	IS : 10042–1981 कंकर-पत्थर निक्षेप वाली नीवों के लिये स्थल-जांच की रीति संहिता	—	—
55.	IS : 10043–1981 स्कूटरों और मोटर साइकिलों के लिये नियन्त्रण संकेतकों और सूचकों के प्रतीक चिन्ह	—	—
56.	IS : 10051–1981 डुबाऊ मोटरों के 105 सें. चालन के लिये पीवीसी रोधित वाइंडिंग तारों की विशिष्टि	—	—
57.	IS : 10064–1982 कीट नियन्त्रण उपस्करों के लिये द्रवचालित फुहारा टोंटी की परीक्षण पद्धतियां	—	1982-03-31 को निर्धारित
58.	IS: 10072–1982 प्लास्टिक के बीकरों की विशिष्टि	—	—
59.	IS : 10075–1981 प्रतिरोध-प्रवर्तन वाले प्रेरण चालित निर्वात संपीडक के प्रवर्तन रिले और अधिकार प्रोटेक्टर की विशिष्टि	—	—
60.	IS : 10088–1981 दन्त कर्षक की विशिष्टि	—	—
61.	IS : 10091–1981 ढलाई घरों में इस्तेमाल के लिये लोह आक्साइड चूर्ण की विशिष्टि	—	—
62.	IS : 10093–1982 कीट नियन्त्रण उपस्करों के लिये हस्तचालित कट-आफ युक्तियों की परीक्षण पद्धतियां	—	—
63.	IS : 10094–1981 विस्तारित पॉली-स्टरीन सामग्री के प्रयोग द्वारा नमूने बनाने की रीति संहिता	—	—

1	2	3	4
64.	IS : 10096(भाग 3)–1982 रेडियल गेटों और उनके हाइस्टों के निरीक्षण, परीक्षण और रख-रखाव के सिफारिशें, भाग 3 स्थापन पश्चात्	—	—
65.	IS : 10100–1982 बुने हुए कपड़ों के सिकुड़न प्रतिरोध (अथवा सिकुड़न-पूर्व) अपेक्षाओं की विशिष्टि	—	—
66.	IS : 10106 (भाग 1)–1982 पैकेज-बन्दी संहिता भाग 1 पैकेजबंदी चयन को प्रभावित करने वाले	—	—
67.	IS : 10110-1982 कृत्रिम अंगों के लिये टेबल-स्पून नुमा अन्तक युक्तियों की विशिष्टि	—	—
68.	IS : 10111–1982 कृत्रिम अंगों के लिये टेबल फार्कनुमा अन्तक युक्तियों की विशिष्टि	—	—
69.	IS : 10121 (भाग 1)–1982 मेटल बॉन पेचों की विशिष्टि-यांन्त्रिक अपेक्षायें और परीक्षण पद्धतियां भाग 1 असम-मित चूड़ी परिवर्ती फिटिंग (गोला-कार) वाले और स्टेनलेस इस्पात के पेंच	—	—

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में तथा अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, मोहाली, पटना और त्रिवेन्द्रम स्थित इसके शाखा कार्यालयों में बिक्री के लिये उपलब्ध हैं ।

[सं. सीएमडी/13 : 2]

ए. एस. भीमा, अपर महानिदेशक (मार्क्स)

S.O. 2148.—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1982-04-30 :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standards Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Remarks, if any
1	2	3	4
1.	IS : 584—1981 Specification for *chaplis*, frontier pattern for general purposes *(second revision)*	IS : 584—1964 Specification for *chaplis*, frontier pattern for general purposes *(revised)*	—
2.	IS : 635—1982 Specification for oil and solvent resistant hose of rubber *(Third revision)*	IS : 635—1968 Specification for oil and solvent resistant hose of rubber with woven textile reinforcement. *(second revision)* and (ii) IS : 3418—1968 Specification for oil and solvent resistant hose of rubber with braided textile reinforcement. *(first revision)*	—

1	2	3	4
3.	IS . 639—1982 Specification for gold leaf. (*second revision*)	IS : 639—1965 Specification for gold leaf (*revised*)	—
4	IS · 990—1982 Specification for spoons, stainless steel. (*second revision*)	IS : 990—1964 Specification for spoons, stainless steel. (*revised*)	–
5.	IS 1067—1981 Specification for electroplated coatings of silver for decorative and protective purposes. (*second revision*)	IS · 1067—1968 Specification for electroplated coatings of silver for decorative and protective purposes (*first revision*)	Established on 1982-02-28 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme, IS : 1067—1981 shall come into force with effect from 1982-10-01
6	*IS : 1258—1979 Specification for Bayonet Lampholders (*second revision*)	IS : 1258—1967 Specification for bayonet lampholders. (*first revision*)	Established on 1980-07-31. *For purposes of ISI Certification Marks Scheme, IS : 1258—1979 shall come into force with effect from 1983-01-16.
7	IS · 1448 (P : 29)—1982 Methods of test for petroleum and its products P : Existent gum in fuels by jet evaporation. (*second revision*)	IS . 1448 (P · 29)—1970 Methods of test for petroleum and its products : (P : 29) Existent gum in fuels by jet evaporation (*first revision*)	—
8.	IS : 1493 (Pt I)—1981 Methods of chemical analysis of iron ores Part I Determination of common constituents. (*first revision*)	IS : 1493—1959 Methods of Chemical analysis of iron ores	
9	*IS · 1664—1981 Specification for mineral mixtures for supplementing cattle feeds (*second revision*)	IS · 1664 –1968 Specification for mineral mixtures for supplementing cattle feeds (*first revision*)	Established on 1982-01-31 *For the purposes of ISI Certification Marks Scheme, IS 1664-1981 shall come into force with effect from 1982-11 01
10	IS : 1885 (Pt LVI)—1981 Electrotechnical vocabulary Part LVI Microwave components and accessories	(i) IS 1885 (Pt XIII/Sec 1)—1968 Electrotechinical vocabulary · Part XIII Telecommunication transmission lines and waveguides, Section 1 General transmission lines and; (ii) IS . 1885 (Pt XIII/Sec 2)—1967 Electrotechnical vocabulary · Part XIII Telecommunication transmission lines and waveguides · Section 2 Microwaves transmission lines and waveguides	Established on 1982-03-31
11.	IS · 2028—1981 specification for open jaw wrenches (spanners) (*second revision*)	IS 2028—1968 Specification for open jaw spanners. (*first revision*)	—
12	IS : 2248—1981 Glossary of terms relating to clay products for building (*first revision*)	IS 2248—1969 Glossary of terms relating to structural clay products	—
13.	IS · 2269—1981 specification for Hexagon socket head cap screws (*second revision*)	IS . 2269—1967 Specification for hexagon socket head cap screws. (*first revision*)	Established on 1982-03-31
14	IS : 2482—1982 Specification for water suction hose of rubber, light duty. (*first revision*)	IS : 2482—1963 Specification for water suction hose of rubber, light duty	
15.	IS . 2490 (Pt I)—1981 Tolerance limits for industrial effluents Part I General limits. (*second revision*)	(i) IS . 2490 (Pt I)—1974 Tolerance limits for industrial effluents discharged into inland surface waters · Part 1 General limits. (*first revision*) ; (ii) IS · 3306—1974 Tolerance limits for industrial effluents discharged into public sewers (*first revision*), (iii) IS : 3307—1977 Tolerance limits for industrial effluents discharged on land for irrigation pusposes (*first revision*); and (iv) IS · 7968—1976 Tolerance limits for industrial effluents discharged into marine coastal areas.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	IS : 2523-1982 Specification for wool hose tops first (revision)	IS : 2523-1963 Specification for worsted hose tops.	—
17.	*IS : 2713 (Pt I to III)—1980 Specification for tububular steel poles for overhead power lines second revision)	IS : 2713-1969 Specification for tubular steel poles for overhead power lines (first revision)	*For purposes of ISI Certification Mark Scheme, IS : 2713 (Pt I to III) 1980 shall come into force with effect from 1980-12-16
18.	IS : 3095-1981 Guidelines for the manufacture of solders for use in goldware (first-revision)	IS : 3095-1965 Guidelines for the manufacture of oslders for use in goldware.	
19.	IS : 3104 (pt I)—1982 Specification for density hydrometers : Part I Requirements (first revision)	IS : 3104-1965 Specification for density hydrometers.	—
20.	IS : 3110-1982 Specification for silver leaf (first revision)	IS : 3110-1965 Specification for silver leaf.	—
21.	IS : 3545-1982 Specification for meat choppers first revision)	IS : 3545-1966 Specification for meat Choppers	—
22.	IS : 4299-1982 Specification for jig feet (first revision)	IS : 4299-1967 Dimensions for jig feet.	—
23.	IS : 4410 (Pt XVI)/Sec 2)—1981 Glossary of terms relating to river valley project Part XVI Gates and valves Section 2 valves	—	—
24.	IS : 5000 (OD 36)—1981 Dimensions of semiconductor devices device outline 36	—	—
25.	*IS : 5082-1981 Specification for wrought aluminium and aluminium alloys bars, rods, tubes and sections for electrical purposes (first revision)	IS : 5082-1969 Specification for wrought aluminium and aluminium alloys, bars, rods, tubes and sections for electrical purposes.	*For purposes of ISI Certification Marks Scheme IS : 5082-1981 shall come into force with effect from 1982-10-01
26.	IS : 5137-1982 Specification for rubber hose for cement g routing (first revision)	(i) IS : 5137-1969 Specification for cement g routing hose of rubber with woven textile reinforcement. (ii) IS : 5166-1969 Specification for cement grouting hose of rubber with braided textile reinfor cement.	-
27.	IS : 5665-1982 Specification for shoulder wheel (first revision)	IS : 5665-1970 Specification for shoulder wheel.	—
28.	IS : 5770-1982 Specification for coal cutting tools mushroom, flat-faced tungsten carbide tipped (first revision)	IS : 5770-1970 Specification for coal cutting tools, mushrooms, flat-faced, tungsten carbide tipped.	—
29.	IS : 6061 (Pt III)—1981 Code of practice for construction of floor and roof with joists and filler blocks Part III With precast hollow clay block joists and hollow clay filler blocks.	—	
30.	IS : 6094-1981 Specification for hexagon socket set screws (first revision)	IS : 6094-1071 Specification for hexagon socket grub screws.	Established on 1982-03-31
31.	IS : 6313 (Pt II)—1981 Code of practice for anti-termite measures in building Part II Pre-constructional chemical treatment measures (first revision)	IS : 6313 (Pt II)—1971 Code of practice for anti-termite measures in building : Part II Pre-constructional chemical treatment measures.	—

1	2	3	4
32.	*IS : 6595—1980 Specification for horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes. (*first revision*)	IS : 6595—1972 Specification for horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes.	Established on 1980-09-30 For purposes of ISI Certification Marks Scheme: IS : 6595—1980 shall come into force with effect from 1982-05-16
33.	*IS : 6901—1981 Specification for pressure regulators or gas cylinders used in welding cutting and related processes. (*first revision*)	IS : 6901—1973 Specification for pressure regulators for gas cylinders used in welding, cutting and related processes.	Established on 1982-02-28 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 6901—1981 shall come into force with effect from 1982-10-01
34.	IS : 6992—1982 Specification for cerebral palsy chair, domestic model. (*first revision*)	IS : 6992—1973 Specification for cerebral palsy chair domestic model.	—
35.	IS : 7178—1982 Technical supply conditions for tapping screws. (*first revision*)	IS : 7178—1974 Mechanical properties of tapping screws.	—
36.	IS : 7270—1981 Code of practice for industrial application and finishing of thermal insulating meterials at temperatures from —80°C to 40°C. (*first revision*)	IS : 7270—1974 Code of practice for application and finishing of thermal insulating materials between —80°C to 40°C.	Established on 1982-03-31
37.	IS : 7417—1982 Specification for hydraulic spray nozzles for pest control equipment. (*first revision*)	IS : 7417 (Pt I)—1974 Specification for hydraulic spray nozzles for pest control equipment : Part I cone and fan type	—
38.	IS : 9001 (Pt VIII)—1982 Guidance for environmental testing Part-VIII Sealing test.	—	—
39.	IS : 9335 (Pt II)—1981 Specification for cellulosic papers for electrical purposes Part II Methods of test.	IS : 2188—1962 Methods of test for paper for electrical purposes.	—
40.	IS : 9828—1981 Specification for portable pneumatic sanders..	—	—
41.	IS : 9829 (Pt I)—1981 Specification for metal bone screws asymmetric Part 1 Screws with thread, variable fitting (spherical)	—	—
42.	IS : 9837—1981 Code for testing for marine centrifugal oil purifiers.	—	—
43.	IS : 9873 (Pt II)—1981 Safety requirements for toys Part II Toxicological requirements.	—	—
44.	IS : 9893—1981 Specification for precast concrete lintels and sills.	—	—
45.	IS : 9908—1981 Specification for formic acid.	—	Established on 1982-03-31.
46.	IS : 9934—1981 Guide for safety and comfort of operator of agricultural tractor.	—	—
47.	IS : 9935—1981 Test code for power tillers.	—	—
48.	IS : 9957—1981 Specification for *Undi* oil.	—	—
49.	IS : 9960—1981 Specification for electrical grade caster oil for use as capacitor impregnant.	—	—
50.	IS : 9992—1981 Specification for round and rectangular tinplate cans for liquid pesticides.	—	Established on 1982-03-31
51.	IS : 9993—1981 Grading for *DIIUPA* kernels for oil milling.	—	—
52.	IS : 10000 (Pt IV)—1980 Methods of tests for internal combustion engines : Part IV Declaration of power ,efficiency, fuel consumption and lubricating oil consumption.	—	—

1	2	3	4
53	IS : 10006—1981 Grading for *Nahor* kernels for oil milling.	—	Established on 1982-03-31.
54.	IS : 10042—1981 Code of practice for site investigations for foundation in gravel-boulder deposit.	—	—
55.	IS : 10043—1981 Symbols for controls, indicators and telltales for scooters and motorcycles.	—	—
56.	IS : 10051—1981 Specification for PVC insulated winding wires for submersible motors for 105°C operation.	—	—
57.	IS : 10064—1982 Methods of tests for hydraulic spray nozzle for pest control equipment.	—	—
58.	IS : 10072—1982 Specification for Plastic Beakers	—	—
59.	IS : 10075—1981 Specification for start relay and overload protector for resistance start induction run hermetic compressor.	—	—
60.	IS : 10088—1981 Specification for retractor, dental.	—	—
61.	IS : 10091—1981 Specification for iron oxide powder for use in foundries.	—	—
62.	IS : 10093—1983 Methods of tests for hand-operated cut-opp device for pest control equipment.	—	—
63.	IS :10094—1981 Code of practice for pattern making by using expanded polystyrene material.	—	—
64.	IS : 10096 (Pt III)—1982 Recommendations for inspection, testing and maintenance of radial gates and their hoists Part III After erection.	—	—
65.	IS : 10100—1982 Specification for shrink-resistance (or preshrunk) requirements of woven fabrics.	—	—
66.	IS : 10106 (Pt I)—1982 Packaging code Part I Factors affecting the selection of packaging.	—	—
67.	IS : 10110—1982 Specification for table spoon terminal device for artificial limbs.	—	—
68.	IS : 10111—1982 Specification for table fork terminal device for artificial limbs.	—	—
69.	IS : 10121 (Pt I)—1982 Specification for metal bone screws—mechanical requirements and methods of test Part I Screws with asymmetrical thread, variable fitting (spherical), stainless steel.	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal Bhubaneshwar, Bombay, Calcutta, Hyderabad Jaipur, Kanpur, Madras, Mohali, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 2]

A. S. CHEEMA, Addl. Director General, (/Marks)

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1985

का० आ० 2149.—भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (1910 का 9) की धारा 36-क की उपधारा 2(क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष, श्री एम० के० सम्बामूर्ति को श्री ए० एन० सिंह के स्थान पर केन्द्रीय विद्युत बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है।

[संख्या-25/6/85-डी (एस. ई. बी.)]

जी० एल० जैरथ, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

(Department of Power)

New Delhi, the 29th April, 1985

S.O. 2149.—In pursuance of sub-section 2(t) of Section 36A of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910) the Central Government is pleased to nominate Shri M. K. Sambamurti, Chairman, Central Electricity Authority, as Chairman of the Central Electricity Board vice Shri A. N. Singh.

[No. 25/6/85-D (SEB)]

G. L. JERATH, Desk Officer

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

का० आ० 2150.—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का०आ० 2097 दिनांक 15 जुलाई, 1978 का अधिक्रमण करते हुए अन्तराज्यीय परिवहन आयोग का निम्नलिखित रूप में पुनर्गठन करती है:—

(1)	संयुक्त सचिव नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन के प्रभारी)	अध्यक्ष
(2)	मुख्य इंजीनियर (सड़क) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष)	सदस्य
(3)	निदेशक (सड़क परिवहन) नौवहन और परिवहन मंत्रालय	सदस्य
(4)	संयुक्त निदेशक (यातायात और वाणिज्यिक) रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	सदस्य
(5)	सचिव, अन्तराज्यीय परिवहन आयोग	सदस्य

[फा० सं० टी० आई० टी०/1/85]

प्रदीप सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th April, 1985

S.O. 2150.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63A of the Motor Vehicles Act, 1939, (4 of 1939) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2097, dated the 15th July, 1978, the Central Government hereby reconstitutes the Inter-State Transport Commission, as follows :—

(1)	Joint Secretary, Ministry of Shipping and Transport (Incharge of Road Transport)	Chairman
(2)	Chief Engineer (Roads) Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing)	Member
(3)	Director (Transport Research) Ministry of Shipping and Transport	Member
(4)	Joint Director (Traffic and Commercial), Railway Board, Ministry of Railways	Member
(5)	Secretary, Inter State Transport Commission.	Member

[File No. TIT/1/85]

PRADEEP SINGH, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1985

का० आ० 2150.—चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 9 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री डी० वेंकटेश्वर राव आई. ए. एस (कर्नाटक 77) को 20.4.85 के अपरान्ह से अगले आदेश तक अपर प्रादेशिक अधिकारी केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हैदराबाद के पद पर स्थानापन्न रूप से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करती है।

[फा० सं० 802/34/83-एफ-(सी)]

के. एम. वेंकटरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th April, 1985

S.O. 2151.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with rule 9 of the Cinematograph (Certification), Rules, 1983, the Central Government is pleased to appoint Shri D Venkateswara Rao, IAS (KTK : 77) to officiate as Additional Regional Officer, Central Board of Film Certification, Hyderabad, on deputation basis with effect from 20-4-85 A. N. until further orders.

[F. No. 802/34/83-F(C)]

K. S VENKATARAMAN, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1985

का०आ० 2152.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का IX अधिनियम) की धारा 82 बी द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 6.6.1981 को पूर्वाह्नि रेलवे में बाघमती नदी पर 416 डाउन पैसेंजर गाड़ी की दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न सभी दावों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री पी० एन० हरकौली, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपर तदर्थ दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है। उनका मुख्यालय सहरसा में होगा।

[सं० 85/ई(ओ) II/1/4]

ए० एन० बाचू, सचिव

रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAY

(Railway Board)

New Delhi, the 30th April, 1985

S.O. 2152.—In exercise of the powers conferred by Section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shri P. N. Harkauli retired Judge as Additional Ad-hoc Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of the accident to 416 DN Passenger train on Baghmati River on North Eastern Railway on 6-6-1981. His Headquarters will be at Saharsa.

[No. 85|E (O) II|1|4]

A. N. WANCHOO, Secy. Railway Board & ex-officio Joint Secretary to the Government of India

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 3 मई, 1985

का०आ० 2153.—स्थायी आदेश संख्या 627, संख्या दिनांक 8 मार्च, 1860 द्वारा लागू किए गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने वेंगाड़/कुथुपरम्बा/पच्चपालोड परिगम्य टेलीफोन केन्द्र में दिनांक से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-9/85-पी० एच० बी०]

अजराजसिंह, सहायक निदेशक (पीएचबी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T BOARD)

New Delhi, the 3rd May, 1985

S.O. 2153.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specified 16-5-1985 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Vengad/Kuthuparambal/Pacha-Palode/Peringamala Telephone Exchange Kerala Circle.

[No. 5-9[85-PHB]

B. R. SINGH, Asstt. Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1985

का.आ. 2154.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि मैसर्स विवेक एसोसिएटस-ए-25, हौज खास, नई दिल्ली 16 और शाखा टेबाको स्ट्रीट, मुरादाबाद (उ.प्र.). नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/154/85-एसएस-2]

New Delhi, the 27th April, 1985

S.O. 2154.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vivek Associates, A-25, Hauz Khas, New Delhi-16 including branch at Tabacco Street, Moradabad, Uttar Pradesh have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/154/85-SS-II]

का०आ. 2155.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गीसनस इंजीनियरिंग कम्पनी सी/4, जी.आई.डी.सी. इंडस्ट्रियल टाउनशिप, नरौदा-30 जिला अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(153)/85-एसएस-2]

S.O. 2155.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Geesons Engineering Company, C/4, G.I.D.C. Industrial Township Naroda-30 District, Ahmedabad, Gujarat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/153/85-SS-II]

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1985

का. आ. 2156.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 मई, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात :—

क्रमांक	राजस्व गांव का नाम	हद बस्त संख्या
1.	बसई	50
2.	नरसिंहपुर जिला गुड़गांव के	102

[संख्या एस-38013/7/85-एस. एस.-1]

(DEPARTMENT OF LABOUR)

New Delhi, the 30th April, 1985

S. O. 2156.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of The Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st May, 1985 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the state of Haryana namely :—

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Had Bast No
1.	Basai	50
2.	Narsinghpur in the District of Gurgaon	102

[No. S-38013/7/85-SS-I]

का. आ. 2157.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 मई, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात :—

केन्द्र : (मद्रास के उपनगर)

(i) चेंगलपट्टु जिले के चेंगलपट्टु तालुक मे उरापक्कम और मेलाकोटटुर (मेलाकोटटाइयुर) राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।

(ii) चेंगलपटटु जिले के सेदापेट तालुक में ताम्बरम, इरुम्बुलियर, मुडिचूर और नेरकुण्ड्राम, पालिलवकारानाई, मेदावक्कम और उल्लागरम राजस्व ग्रामों अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।

(iii) चेंगलपटटु जिले के सेदापेटतालुक मे इंजामबक्कम नीलांगराई, पालावक्कम, कानागम काराप्पक्कम राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।

[संख्या एस-38013/8/85-एस-एस-1]

S.O. 2157.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st May, 1985 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu, namely :—

CENTRE :

(Madras Suburbs) :

(i) Areas comprising Urpakkam and Melakottur (Melakottalyur) Revenue Villages in Chengalpattur Taluk in Chengalpattu District;

(ii) Areas comprising Tambaram, Erumbuliyur, Mudichur and Nerkundram, Pallikkaranai, Madavakkam and Ullagaram Revenue Villages in Saidapet Taluk in Chengalpattu District; and

(iii) Areas comprising Enjambakkam, Nellangarai, Palavakkam, Kanagam, Karappakkam Revenue Villages in Saidapat Taluk in Chengalpattu District.

[No. S-38013/8/85-SS. I]

का० आ० 2158.—मैसर्स पलानी इन्डाबर काटन एंड सिन्थेटिक स्पिनरस लिमिटेड, 236/1, दली रोड, उडामलपेट- 642126 जिला कोम्बेटुर (टी एन/16099) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदाय के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि, कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होती तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का नियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसकी हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/109/85-एसएस-4]

S.O. 2158.—Whereas Messrs. Palani Andavar Cotton and Synthetic Spinners Limited 236|1, Dhally Road, Udamalpet-642126, Coimbatore Distt. (TN|16099), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter refered to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, Submissions of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014|109|85-SS-IV]

का. आ. 2159.—मैसर्स अल. जी. बालाकृष्णन एंड ब्रोस लि., गणपति पोस्ट कोम्बेटोर-641006. (टोएन 3818) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा है ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/106/85-एसएस-4]

S.O. 2159.—Whereas Messrs I. G Balakrishnan and Brothers Limited, Ganapathy Post Coimbatore-641006 (TN) 3818), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submissions of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under te said Act, is employer in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits

to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/106/85-SS-IV]

का० आ० 2160.—मैसर्स इल्मी इक्यूपमेंट लि. इंडिया हाऊस तिरची रोड, कोम्बेटूर (टीएन/3512) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और इसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को

अवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/105/85 एसएस-4]

S.O. 2160.—Whereas Messrs Elgi Equipments Limited, India House, Trichy Road, Coimbatore-641018 (TN/3512), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submissions of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employer in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/105/85-SS-IV]

का.आ. 2161.—मैसर्स ई.डब्ल्यू.ए.सी. एलौयस लिमिटेड, साकी विहार रोड, पोवाई, बम्बई-72 (महाराष्ट्र/12039) (जिसे इसमें इस के पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952] (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदों मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा मे उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/102/85-एसएस-4]

S.O. 2161.—Whereas Messrs EWAC Alloys Limited, Saki Vihar Road, Powai, Bombay-72 (MH|12309), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (9 of 1952), hereinafter referred to as the said (Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and maintain such accounts

and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expense involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submissions of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employer in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premiums in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/102/85 SS IV]

का आ 2162—मैसर्स कारवल्वस लिमिटेड प्लोट नं 6, पीनया इंडस्ट्रीयल एरिया, पीनया, बंगलौर—560058 (कर्नाटक/6314) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/101/85-एस०एस० 4]

S.O. 2162.—Whereas Messrs Karalves imited, Plot No. 6 Peenya Industrial Area, Peenya, Bangalore-560058 (KN/6314), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conefrred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expesnes involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the empolyee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case

within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/10/85-SS-IV]

का.आ.2163.—मैसर्स ट्रक्टर इंजीनियर्स लिमिटेड, साकि विहार रोड, पो.आ.बाक्स 8913, पोवई, बम्बई—400072 (एमएच/745) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तत्संबंधी उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन

बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/111/85-एस एस-4]

S.O. 2163.—Whereas Messrs Tractor Engineers Limited Saki Vihar Road, Post Office Box 8913 Powai, Bombay-400072 (MH/745) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, ddirect under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employsee' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Gorup Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased members entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/111/85-SS-IV]

का०आ. 2164.—मैसर्स दि मेटूर केमिकल एंड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, मेटूर डैम आरएस 636402 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/97/85-एसएस-4]

S.O. 2164.—Whereas Messrs The Mettur Chemical and Industrial Corporation Limited, Mettur Dam R.S.-636402, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia-transfer of account, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 .Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S 35014/97/85-SS-IV]

का.आ. 2165.—मैसर्स पेनर (इंडिया) लिमिटेड, 56-डी, मिर्जागालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-16 (पश्चिम बंगाल/5113) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा, स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप

से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एफ-35014/96/85-एसएस-4]

S.O. 2165.—Whereas Messrs Fenner (India) Limited, 56-D, Mirza Galib Street, Calcutta-16 (WB/5113), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maitain such accounts and proyide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be under without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S.35014/96/85-SS-IV]

का. आ. 2166.—मैसर्स मोटर इंडस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, होसर रोड, अड्डुगोडी, बंगलौर (कर्नाटक/120) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों आ वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में दिए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/95/85-एसएस-4]

S.O. 2166.—Whereas Messrs Motor Industrial Company Limited, Hosur Road, Adugodi, Bangalore-(KN/120), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less then the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, shall be made without the prior approval of the heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S 35014/95/85-SS-IV]

का.आ. 2167.—मैसर्स किर्लोस्कर ब्रादर्स लिमिटेड उद्योग भवन, तिलक रोड, पूना-9(महाराष्ट्र/320) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (3क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड(क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण,निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आदेशक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन भूत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/94/85-एसएस-4]

S.O. 2167.—Whereas Messrs Kirloskar Brothers Limited, Udyog Bhavan, Tilak Road, Poona-9 (Maharashtra) (MH| 320), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sums assured to the nominees/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/94/85-SS-IV]

का.आ. 2168.—मैसर्स कार हाऊस, कनसोलीडेटिड प्रोडक्टस (प्रा.) लिमिटेड, 15/28, कृष्णास्वामी मुडालियर रोड, कोइम्बटूर-641002(टीएन/16426) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त स्कीम' कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सख्या एस-35014/85/85-एसएस-4]

S.O. 2168.—Whereas Messrs Car House Consolidated Products Private Limited, 15|28, Krishnaswamy Mudaliar Road, Coimbatore-641002 (TN/1626), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter refrered to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hearinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maitain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legalheirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sums assured to the nominees/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014|85|85-SS-IV]

का० आ० 2169—मैसर्स आनन्द सेनीटेशनज, 8/160, ट्रीचो रोड, सिंगानल्लूर, कोइम्बटूर-641005 (टीएन/16983) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त स्थापन' कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसकेपश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त स्कीम' कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक, बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/84/85-एसएस-4]

S.O. 2169.—Whereas Messrs Anand Sanitations, 81/60, Trichy Road, Singanallore, Coimbatore-641005, (TN/16983), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection; as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that, would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Comissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment to not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sums assured to the nominees/legal heirs of the deceased member entitled for it and, in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/84/85-SS-IV]

का० आ० 2170.—मैसर्स अपर राजस्थान सेल्स एंड सर्विसीज (प्रा०) लिमिटेड, बी-2, जैयन्ती मार्किट, एम० आई० रोड जयपुर (र० ज०/3489) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण

प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य-निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विविध वारिसों को बीमाकृत रकम की संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35011/91/85-एसएस-I]

S.O. 2170.—Whereas Messrs Upper Rajasthan Sales and Service Private Limited, B-2 Jayanti Market M.I. Road, Jaipur (RJ 3489) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendmtnt of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium, etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it end in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/91/85-SS-IV]

का.आ. 2171.—मैसर्स मैसूर क्रिस्टल ग्लास इंडस्ट्रीज, टेमरी रोड, नागावारा, बंगलौर-45 (के.एन./4697) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इस इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 जिसे उसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमिय का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों का संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस–35014/90/85–एसएस-4]

S.O. 2171.—Whereas Messrs Mysore Crystal Glass Industries, Tannery Road, Nagavara, Bangalore-4 (KN|4697) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas as employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|Legal heirs of the deceased member entitled for it end in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/90/85-SS-IV]

का. आ. 2172.—मैसर्स दी गोथामी सॉल्वेंट आईल (प्रा.) लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 7 पाइडीपाडु टानकु (ए.पी.)—5808) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/89/85-एसएस-4]

S.O. 2172.—Whereas Messrs The Gowthami Solvent Oils Private Limited, P.B. No. 7, Pydiparru, Tanuku, (AP/5808), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendmtnt of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/84/85-SS-IV]

का.आ. 2173—मैसर्स रेवती तम्बाकू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, 7, सुन्दरनगर, हैदराबाद (एपी/6013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा

कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होगा, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/108/85 एस एस 4]

S.O. 2173.—Whereas Messrs. Revathi Tobacco Company Pravate Limited, 7, Saroonagar, Hyderabad (AP|6013), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features there of, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014|108|85-SS-IV]

का.आ. 2174.—मैसर्स कन्सोलिडेटिड कॉफि लिमिटेड पोली बेटा–571215 कोटांगु (केएन/270) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते

है, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/110/85-एसएस-4]

S.O. 2174.—Whereas Messrs Consolidate Coffee Limited, Polibetta-571215, Kodagu (KN 270), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government, and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if in the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/110/85-SS-IV]

का. आ. 2175—मैसर्स कंसोलिडेटेड कॉफी लिमिटेड, पोलिबेट्टा-571215, कोडागु (के एन 270) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तत्काल उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहित बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हों।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उन रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिकवारिस/ नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/103/85-एस एस-4]

S.O. 2175.—Whereas Messrs A. P. S. R. T. Employees' Co-operative Credit Society Limited, Satyanarayana Reddy Marg, Azamabad, Hyderabad (AP|6479), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/ Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/103/85-SS-IV]

का. आ. 2176.—मैसर्स श्री अमम्बिका इंडस्ट्रीज एंड ली जिंग लिमिटेड 15-4-188, ओसमानशाही, हैदराबाद (ए पी/13446) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य विधि पर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती हैं ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियां का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाये है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/107/85-एसएस-4]

S.O. 2176.—Whereas Messrs Shri Ambica Industries and Leasing Limited-15-4-198, Osmanshahi, Hyderabad (AP/13446) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee| Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014|107|75-SS-IV]

का.आ. 2177.—मैसर्स फैटटो इलजी प्राइवेट लिमिटेड इंडिया हाउस, पोस्ट बाक्स नं. 3718, तिरची रोड, कोम्बेटोर (टीएन/5479) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/104/85-एस एस-4

S.O. 2177.—Whereas Messrs Festo Elgi Private Limited, India House P. B. No. 3718, Trichy Road, Coimbatore-641018 (TN|5479), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be brone by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurnce Scheme, if on the death of an employee the amount payble under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014|104|85-SS-IV]

नई दिल्ली, 1 मई, 1985

का. आ. 2178.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एस. के. टैक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, प्लाट नं. 46, ए. पी. आई. आई. सी., काटेदान, हैदरबाद, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु-

संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/150/85-एस एस-2]

New Delhi, the 1st May, 1985

S.O. 2178.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. K. Textiles Industries, Plot No. 46, A.P.I.I.C., Kattedan, Hyderabad, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/150/85-SS-II]

का. आ. 2179.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रिनोल्ड म्युजिकल्स 15, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-700016 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35017/45/85-एस. एस-2]

S.O. 2179.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Reynold Musicals 15, Mirza Ghalib, Street, Calcutta-700016 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/45/85-SS-II]

का. आ. 2180.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कजारिया इंडस्ट्रीज पी. ओ. बीक्स नं. 2020, 14 और 15, ओल्ड कोर्ट हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[स. एस.-35017/46/85-एस एस.-2]

S.O. 2180.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kajaria Industries, Post Office Box No 2020, 14 and 15, Old Court House Street, Calcutta 700001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/46/85-SS-II]

का. आ. 2181.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्ट्रीप इंडिया 16, मोंडाल टेम्पल लेन, पी. ब्लाक न्यू आलीपुर, कलकत्ता-53, और सेल्स आफिस 171/37, राय बहादुर रोड, कलकत्ता-34 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबध उक्त स्थापन को लागू करती ।

[स एस-35017/47//85-एस एस-2]

S.O 2181.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Strip India 16, Mondal Temple Lane, P-Block, New Alipore, Calcutta-53, and sales office at 171/37, Rai Bahadur Road, Calcutta-34, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/47/85-SS-II]

का. आ. 2182.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शालीमार फूड प्रोडक्टस पी/185, चांदमारी रोड, हावड़ा-9 और हैड आफिस 46/सी, चौरजी रोड-1, कलकत्ता-71 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35017/48/85-एस एस-2]

S.O. 2182.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shalimar Food Products, P/185, Chandmari Road, Howrah-9, and Head Office at 46/C, Chowringhee Road-1, Calcutta-71, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/48/85-SS-II]

का. आ. 2183.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मैक्को कोच बुल्डर्स, 39, मेतुपालायम रोड, (नियर सी टी सी मैन), कोइम्बटूर-43, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/155/85-एस एस-2]

S.O. 2183.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mekco Coach Builders, 39, Mettupalayam Road, Near C.T.C. Main, Coimbatore-43, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/155/85-SS-II]

का. आ. 2184.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री शानमुघा टाकीज, गधवी कोटाई, प्रधुकोटाई डिस्ट्रिक्ट पिन-613301 तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/151/85-एस एस-2]

S.O. 2184.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shanmugha Talkies. Gandharva Kottai, Podukkottai District, Pin-613301, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/151/85-SS-II]

का. आ. 2185.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि मैसर्स आयेट्रैक इंडस्ट्री नं. 4, सरदार पटेल रोड, अदयार, मद्रास-600113 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/152/85-एस एस-2]

S.O. 2185.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Autotrac Industries, No. 4, Sardhar Patel Road, Adyar, Madras-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/152/85-SS-II]

का. आ. 2186.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेरिन एंड केमिकल सर्विसिज 111-बी, हाजरा रोड, कलकत्ता-26 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35017/43/85-एस एस-2]

S.O. 2186.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Marine and Chemical Services, 111-B, Hazra Road, Calcutta-700026, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/43/85-SS-II]

का. आ. 2187.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शान्तना म्यूजिकल 2, कोकबर्न लेन, कलकता-700016 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35017/44/85-एस एस-2]

S.O. 2187.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Santana Musical 2, Cockburn Lane, Calcutta-700016, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/44/85-SS-II]

का. आ. 2188.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि वेबल कम्प्युटर लि., 225-ई आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकता-20 और शाखा 18-ए पार्क स्ट्रीट, कलकता-71 में स्थित स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35017/49/85-एस एस-2]

S.O. 2188.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Webel Computer Limited, 225-E, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Calcutta-20 and its branch at 18-A, Park Street, Calcutta-700071, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/49/85-SS-II]

का. आ. 2189.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साक्थी इंडस्ट्रीज, 99-ए, जी. एस. टी. रोड, पालावरम, मद्रास-43 और नं. 5 वालूवार पेटाई-1 स्ट्रीट, पालावरम मद्रास-43, तमिलनाडु स्थित फैक्टरी सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/169/85-एस एस-2]

S.O. 2189.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sakthi Industries, 99A, G.S.T. Road, Pallevaram, Madras-43 including its factory at No. 5, Valluvar Pettai I Street, Pallavaram, Madras-43, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/169/85-SS-II]

का. आ. 2190.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि मैसर्स नेशनल इंजीनियरींग सर्विस 1-8-668, अजामाबाद, हैदराबाद-500020 आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/156/85-एस एस-2]

S.O. 2190.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs National Engineering Service, 1-8-668, Azamabad, Hyderabad-500020, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/156/85-SS-II]

का. आ. 2191.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हेलपेज इंडिया बी-102 हिमालय हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली और शाखायें (1) बम्बई, (2) कलकत्ता (3) मद्रास, (4) नागपुर (5) हैदराबाद (6) कोचीन, (7) बंगलौर, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/157/85 एस एस-2]

S.O. 2191.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Helpage India B-102, Himalaya House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-1 including Branches at (1) Bombay (2) Calcutta (3) Madras (4) Nagpur (5) Hyderabad (6) Cochin and (7) Bangalore, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/157/85-SS-II]

का. आ. 2192.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि क्रिसटल इंडस्ट्रीज, जी. टी. रोड बाईपास नियर पठानकोट चौक, जालंधर सिटी, पंजाब नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/158/85-एस एस-2]

S.O. 2192.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Crystal Industries, G.T. Road, Bye-Pass, Near Pathankot Chowk, Jalandhar City, Punjab have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/158/85-SS-II]

का.आ. 2193.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चित्रघर सिनेमा, डाकघर-राधा किशोरपुर, उदयपुर, साउथ त्रिपुरा, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/159/85-एसएस-2]

S.O. 2193.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chitraghar Cinema, P.O. Radha Kishorepur, Udaipur, South Tripura, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/159/85-SS-II]

का.आ. 2194.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कृष्णा रीफ्रेक्टरीज, इंडस्ट्रियल एस्टेट, चंदूलाल बरादरी, हैदराबाद-500264, आन्ध्र प्रदेश, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/160/85-एसएस-2]

S.O. 2184.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Krishna Refractories, Industrial Estate, Chandulal Bradari, Hyderabad-500264, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/160/85-SS-II]

का. आ. 2195.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि आसाम पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, नामरूप, पो.आ. पबर्तपुर, पिन-786623, आसाम, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस- 35019/161/85-एस एस-2]

SO. 2195.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Assam Petro Chemicals Ltd, Namrup, P.O. Parbatpur Pin-786623, Assam, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/161/85-SS-II]

का. आ. 2196—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सत्तार सेनीटरी स्टोर्स, 11, वेनियर स्ट्रीट, मद्रास-1, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस- 35019/162/85-एस. एस-2]

S.O. 2196.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sattar Sanitary Stores, 11, Vanniar Street, Madras-I Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/162/85-SS-II]

का. आ. 2197.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामासरवाना मोड्न राईस मिल, उकाडाई, आरियामंगलम, त्रिचि-10, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस- 35019/163/85-एस. एस-2]

S.O. 2197.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ramasaravana Modern Rice Mill, Ukkadai, Ariyamangalam, Trichy-10 Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/163/85-SS-II]

का. आ. 2198.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेल्टवैल क्रसिबल्स, पाडुर विलेज, केलामबकम, पोस्ट आफिस चिंगलेपूत, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/164/85-एस एस-2]

S.O. 2198.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Meltwel Crucibles, Padur Village, Kelambakkam P.O. Chingleput District, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/164/85-SS-II]

का. आ. 2199—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अलागिरी टैक्सटाईल, 185, रंगाई गोदर स्ट्रीट कोम्बोटूर-1, तामिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं एस—35019/165/85-एस. एस-2]

S.O. 2199.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Alagiri Textiles, 185, Rangai Gowder Street, Coimbatore-1, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employes' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/165/85-SS-II]

का. आ. 2200—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी होली क्रोस, मेट्रीकुलेशन स्कूल, 44, चेलापिलाईयार कोईल स्ट्रीट, मद्रास-14, नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/166/85-एस. एस-2]

S.O. 2200.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Holy Cross Matriculation School, 44, Chellapillaiyar Koil Street Madras-600014, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/166/85-SS-II]

का. आ. 2201.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेंकटारमन एंड कम्पनी, शेयर ब्रोकर्स, 78, डा. रंगाचारी रोड, मेलापौर, मद्रास-600004., तमिलनाडु. नाम स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस 35019/167/85-एस. एस-2]

S.O. 2201.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Venkataramen and Co., Share Brokers, 78, Dr. Rangachari Road, Mylapore, Madras-600004, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/167/85-SS-II]

का. आ. 2202—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री मुरूगान आर्ट क्राफटस, 32-बी, और 32-सी सन्तुर रोड, सिवाकाशी, तमिलनाडु. नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/168/85-ए.एस-2]

S.O. 2202.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Murugan Arts Craft, 32-B & 32-C, Sattur Road, Sivakasi, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/168/85-SS-II]

नई दिल्ली, 3 मई, 1985

का. आ. 2203—केन्द्रीय सरकार, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 53) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2203, दिनांक 30 जुलाई, 1980 का अधिक्रमण करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में किसी ऐसे स्थापन की बाबत, जिसमें धुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य कार्यों का प्रदर्शन करने के लिए व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है:

सारणी

क्रम.	अधिकारी	सीमाएं
1	2	3
1.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली	सम्पूर्ण भारत
2.	संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली।	
3.	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली।	
4.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली।	
5.	सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली।	
6.	श्रम प्रवर्तन अधिनिकारी (केन्द्रीय) नई दिल्ला।	
7.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कल्याण सलाहकार, नई दिल्ली।	

1	2	3
8.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मुम्बई	महाराष्ट्र राज्य और गोवा, दमण और दीप तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
9.	मुम्बई क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
10.	मुम्बई क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	
11.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता	पश्चिम बंगाल राज्य बर्दमान, बीरभूम, बांकुरा और पुरूलियी, के जिलों को छोड़कर) सिक्किम और अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह ।
12.	कलकत्ता क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
13.	कलकत्ता क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	
14.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मद्रास	तमिलनाड और केरल राज्य और पांडिचेरी और लक्ष्द्वीप के संघ राज्य क्षेत्र ।
15.	मद्रास क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
16.	मद्रास क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	
17.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर	मध्य प्रदेश राज्य
18.	जबलपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
19.	जबलपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	
20.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त केन्द्रीय, कानपुर	उत्तर प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली ।
21.	कानपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
22.	कानपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	
23.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद	बिहार राज्य]
24.	धनबाद क्षेत्र में सभी सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	
25.	धनबाद क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)/ कनिष्ठ श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय)	
26.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश राज्य
27.	हैदराबाद क्षेत्र में सभी सहायक श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय)	
28.	हैदराबाद क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	
29.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर	राजस्थान और गुजरात राज्य ।
30.	अजमेर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
31.	अजमेर क्षेत्र मे सभी सहायक श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	
32.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), आसनसोल	पश्चिम बंगाल राज्य के बर्दवान बीरभूम, बांकुरा और पुरूलिया जिले ।
33.	आसनसोल क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
34.	आसनसोल क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	
35.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य
36.	भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
37.	भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	
38.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), चण्डीगढ़	हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर राज्य व संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ ।
39.	चण्डीगढ़ क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
40.	चण्डीगढ़ क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	
41.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), गोहाटी	असम, नागालेंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर राज्य औ अरूणाचल प्रदेश तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र ।
42.	गोहाटी क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
43.	गोहाटी क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	
44.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलौर	कर्नाटक राज्य
45.	बंगलौर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
46.	बंगलौर क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	

[एस.-36013/1/84-एस. एस.-I]

ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd May, 1985

S.O. 2203.—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No.S.O. 2203, dated the 30th July, 1980, the Central Government hereby appoints the officers, mentioned in column (2) of the Table below to be Inspectors for the purpose of the said Act, in relation to any establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performance in respect of the areas specified in corresponding entries in column 3 of the said Table:—

TABLE

S.No.	Officers	Limits
(1)	(2)	(3)
1.	Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.	Whole of India
2.	Joint Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.	
3.	Deputy Chief Labour Commissioners (Central), New Delhi.	
4.	Regional Labour Commissioners (Central), New Delhi.	
5.	Assistant Labour Commissioners (Central), New Delhi.	
6.	Labour Enforcement Officers (Central), New Delhi.	
7.	Welfare Adviser to the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.	

(1)	(2)	(3)
8.	Regional Labour Commissioners (Central), Bombay.	State of Maharashtra and the Union Territories of Goa, Daman and Diu and Dadra & Nagar Haveli.
9.	Assistant Labour Commissioners (Central) in the Bombay region.	
10.	All Labour Enforcement Officers (Central), in the Bombay region.	
11.	Regional Labour Commissioner (Central), Calcutta.	State of West Bengal (excluding Districts of Burdwan, Birbhum Bankura, Purulia) Sikkim and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
12.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Calcutta region.	
13.	All Labour Enforcement Officers (Central) in the Calcutta region.	
14.	Regional Labour Commissioners (Central) Madras.	State of Tamil Nadu Kerala and Union Territories of Pondicherry and Lakshwadeep.
15.	All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Madras region.	
16.	All Labour enforcement Officers (Central) in the Madras region.	
17.	Regional Labour Commissioners (Central), Jabalpur.	State of Madhya Pradesh.
18.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Jabalpur Region.	
19.	All Labour Enforcement Officers (Central) in the Jabalpur region.	
20.	Regional Labour Commissioner, (Central), Kanpur.	State of Uttar Pradesh and the Union Territory of Delhi.
21.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Kanpur Region.	
22.	All Labour Enforcement Officers, (Central) in the Kanpur region.	
23.	Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad.	State of Bihar
24.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Dhanbad region.	
25.	All Labour Enforcement officers (Central)/Junior Labour Inspectors (Central) in the Dhanbad region .	
26.	Regional Labour Commissioner (Central), Hyderabad.	State of Andhra Pradesh.
27.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Hyderabad region.	
28.	All the Labour Enforcement Officers (Central) in the Hyderabad region.	
29.	Regional Labour Commissioners (Central), Ajmer.	State of Rajasthan and Gujarat.
30.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Ajmer region.	
31	All Labour Enforcement Officers (Central) in the Ajmer region.	
32.	Regional Labour Commissioner (Central), Asansol.	District of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
33.	All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Asansol region.	
34.	All Labour Enforcement officers (Central) in the Asansol region.	
35.	Regional Labour Commissioner (Central), Bhubaneshwar.	State of Orissa.
36.	All Assissant Labour Commissioners (Central), in the Bhubaneswar region	
37.	All Labour Enforcement Officers (Central) in the Bhubaneswar region.	
38.	Regional Labour Commissioners (Central), Chandigarh.	States of Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Jammu & Kashmir and the Union Territory of Chandigarh.
39.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Chandigarh region.	
40.	All Labour Enforcement Officers (Central) in the Chandigarh region	
41.	Regional Labour Commissioner (Central), Gauhati.	States of Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Manipur and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.
42.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Gauhati region.	
43.	All Labour Enforcement Officers (Central) in the Gauhati region.	
44.	Regional Labour Commissioners (Central), Bangalore.	State of Karnataka.
45.	All Assistant Labour Commissioners (Central), Bangalore region.	
46.	All Labour Enforcement Officers (Central) in the Bangalore region.	

[No. S-35013/1/84-SS.I]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1985

का. आ. 2204.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कादरास ऐरिया मैसर्ज बी सी सी एल, धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 20-4-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th April, 1985

S.O. 2204.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Katras Area, M|s. Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th April, 1985.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 89 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Katras Area, M|s. BCCL, Dhanbad and their workmen.

APPEARANCE :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri B. Lal, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 17th April, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(38)/84-D.IV(B), dated, the 10th December, 1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Katras Area, M/s. BCCL, Dhanbad in not regularising Shri R. K. Prasad, Clerk as Legal Assistant as has been done in the cases of other personnel is justified ? If not, to what relief is the concerned workman is entitled?"

The case of the workman is that the concerned workman Shri R. K. Prasad has been working in the capacity of Legal Assistant since 12-3-1982 in Katras Area of M/s. B.C.C.L. He had taken over charge of Legal Assistant of Katras Area by the order of Senior Personnel Officer from Shri M. K. Choubey who was formerly working as Legal Assistant in Katras Area and was transferred to Koyala Bhawan on 12--82. Shri M. K. Choubey, Legal Assistant was in Special Grade. After taking over the charge from Shri M. K. Choubey, the concerned workman was attending Court, assisting the Advocate of the Company on legal matters, appeared and assisted in conciliation proceedings and arbitration proceedings on behalf of the management besides doing other work as legal Assistant. He also used to prepare the briefs of labour cases, collect documents from the collieries and with those documents he used to discuss with the lawyers of the company and used to prepare the notes of cases. In connection with his work he used to go to Dhanbad Court and also at Ranchi Bench of the Patna High Court. He was doing most of these jobs independently. The job of Legal Assistant is in the technical and supervisory Grade-A in the Cadre scheme, the minimum qualifications for which is matriculate. The concerned workman has regularly been working as Legal Assistant since the date of his joining on 12-3-1982. The concerned workman and the union represented before the management for his regularisation in the grade of Legal Assistant. The management wanted to regularise the concerned workman in Grade-A special which was not accepted by him as the job of Legal Assistant is in Technical and Supervisory Grade-A. When the concerned workman was not regularised an industrial dispute was raised by his union. The concerned workman had also preferred claim of difference of wages with retrospective effect from 12-3-1982 which remain pending for consideration. In case of regularisation from Grade-I to Special Grade as per nature of job it is not necessary that the same be considered by departmental promotion committee. On the above facts the concerned workman has claimed regularisation in Technical and Supervisory Grade-A from 12-3-1982.

The case of the management is that the concerned workman Shri R. K. Prasad is a Clerk attached to the Personnel department. The clerks attached to the Personnel Department are placed in Grade-II, Grade-I and Special Grade depending upon the seniority-cum-merit on the basis of promotion according to the cadre scheme or on the basis of regularisation. The Personnel department looks after the labour cases, industrial relation, recruitment organisation etc. and the clerks attached to the officer of the Personnel department is to perform the clerical duties relating to the Officer to whom he is attached. The Labour cases of the concerned area are dealt with by the Senior Personnel Officer or Dy. Personnel Manager. The concerned workman was doing clerical duties relating to the Labour cases and other incidental matters. The clerks attached to the Senior Personnel Officer or Dy. Personnel Manager who are incharge of Labour cases and industrial matters are placed in Clerical Grade-I in most of the area. All the clerks in Grade-I in the entire area are grouped together and a common seniority list is prepared. The promotion to clerical grade special are made on the basis of the recommendations of the departmental promotion committee (hereinafter referred to as D.P.C.) The D.P.C recommends the names of the candidates for promotion from clerical Grade-I to Special Grade on the basis of Seniority-cum-merit. The concerned workman was not recommended for his promotion from Grade-I to Special Grade and is still in Grade-I The concerned workman is performing clerical duties of keeping and maintaining the files relating to the labour disputes and labour cases. He attends the Tribunal and Labour Courts along with the officer incharge of the labour matters. The concerned workman hands over the files and documents etc. to the lawyer handling the cases and does duties incidental to or connected with the labour cases. There is no prescribed designation of Legal Assistant in the collieries or in the area office. All the persons doing clerical duties and attached to the personnel department are called P.Os. clerks. The posts of Legal Assistants exist in the legal department at the headquarters only and not in the area. The Legal department at the headquarters handles civil, criminal, revenue cases and all cases in the High Court and the Supreme Court where the Legal Assistants are given independent charge of civil, criminal and revenue cases and they are required to prepare comments, study documents, put legal notes and brief the lawyers incharge of the cases. The duties performed by the Legal Assistants of the headquarters are of higher responsibilities and are Law Graduates having experience of law courts as lawyer. The concerned workman was not promoted to the post of Legal Assistant and the Senior Personnel Officer had no authority to promote him or to describe him as Legal Assistant. The concerned workman cannot be said to be a Legal Assistant only because he took over the charge from Shri M. K. Choubey and came in possession over the files which were formerly in possession of Shri Choubey. The concerned workman did not perform the duties of a Legal Assistant and he was always performing the Clerical jobs relating to personnel department. The concerned workman has rightly been placed in Clerical Grade-I. The concerned workman had demanded for his promotion to special grade through note sheets of the superior officers but the management had not accepted the recommendation as the case of the concerned workman had no foundation. In proper cases workmen are regularised on higher grades but in other cases the workmen are promoted to higher grades on the recommendation of the D.P.C. The demand of the concerned workman for regularisation as Legal Assistant in special grade or in technical and supervisory grade-A is not justified.

The point for decision in this case is whether the concerned workman is justified in his demand for regularisation as Legal Assistant.

The management have examined two witnesses and the workmen have examined the concerned workman to prove their respective cases. The management have prodcued documents which have been marked Ext. M-1 to M-5 and the concerned workman has produced documents which have been marked Ext. W-1 to W-17.

From the case of the parties it will appear that the reference is in respect of the regularisation of the concerned workman and not regarding his promotion. It means, therefore, that the concerned workman is working as Legal Assistant and as such he claims to be regularised as Legal Assistant. The points for consideration therefore is whether the concerned workman is doing the job of Legal Assistant. The case of the management is that there is no post of Legal Assistant in the area and that the concerned workman was attached to the Sr. Personnel Officer or Dy. Personnel Manager in the Area doing clerical duties relating to labour cases and other incidental matters. The case of the concerned workman on the other hand is that he had taken over charge from Shri M. K. Choubey, Legal Assistant as such he is entitled to be regularised as Legal Assistant since the taking over of his charge from 12-3-1982. It will appear from the W. S. of the parties that a workman is regularised to the higher posts if he is working in the said higher post for some period and there is no dispute regarding the fact that a workman of a lower grade cannot be regularised. in the higher grade in which he was actually wroking. The concerned workman has filed Ext. W-8 dated 3-5-1982 to show that Shri Udayan De and three others were regularised in Clerical Grade Special with effect from 1-5-82 Ext. W-9 dated 30-6-82 W-10 dated 10-8-83 and Ext. W.11 dated 26-11-83 are other documents to show that a workman of the lower category working in the higher category can be regularised. There is no need to discuss these documents in detail as it is admitted by the management that they have been regularised persons of the lower category to the higher category in which they are working without reference to the D.P.C. Thus there is no controversy regarding the fact that a workman of the lower category cannot be regularised in the higher category in which he has been working without referring to the D.P.C.

Now let us examine the evidence on the fact whether the concerned workman is working as a Legal Assistant. No

job description of a Legal Assistant is provided in any of the papers of the management. Ext. M-3 dated 20-6-/7 is the Cadre scheme of the Ministerial staff and in its Annexure-C the nature of job/duties in different ministerial grade is stated The nature of job of special grade clerk is of highly skilled nature of clerical job requiring trust and sense of responsibilities and it further gives details of the job of the special grade. Then there is the nature of job/ duties of the supervisory grade and from the same it will appear that the post of Legal Assistant is covered in the supervisory grade along with the Sr. P.A. Office Superintendent, Accountant and Senior Stores Supervisor. It will therefore appear from Ext. M 3 that the job of Legal A sistant is of supervisory grade. The minimum educational qualifications and experience has been prescribed for different posts for departmental promotion in annexure B of Ext. M-3. It will appear from this annexure B that the minimum qualifications for the Supervisory clerk is a passed matriculate/S.S.L.C. or any equivalent examination from any recognised board of examination and he must have two years experience in the next below grade It is clear, therefore, that the post of Legal Assistant which is of supervisory grade requires a minimum qualifications of passed matric or equivalent examination and also he must have two years experience in the next below grade. From Ext. M-3 therefore it will appear that a Legal Assistant of the supervisory grade must have a minimum educational qualifications of having passed matriculation examination and also have two years experience in special grade clerk which is the next below grade to supervisory grade.

According to the management the minimum qualification for a Legal Assistant for direct recruitment is a Law Graduate with three years experience at-bar and that for appointment from the department he must be a Law Graduate. The management has not produced any rule or circular of recruitment of Legal Assistant and the evidence is based on oral deposition. Ext. M-1 is a notice dated 22/24-2-83 issued by the Dy. Personnel Manager which shows that an advertisement was made to fill up the post of Legal Inspector in clerical Grade (Special) in the pay scale of Rs. 610-35-920-40-1160 per month and that the minimum qualification for a permanent clerical staff was a Law Degree. On the basis of Ext. M-1 it is stated that for appointment of Law Assistant from the departmental candidates, the minimum qualification is a Law Graduate. I do not think that the submission is well founded. Firstly, this advertisement Ext. M-1 is in respect of appointment of Legal Inspector in which the minimum qualification was a Law Graduate from the departmental candidates. There is nothing except in the evidence of MW-1 to show that the post of Legal Inspector is the same as that of Legal Assistant. It will further appear that even for the Legal Inspector the management was giving him clerical grade special and not technical and Supervisory grade.

MW-1 Shri U. K. Mishra is presently working as Law Officer. He was first appointed as Legal Assistant in 1973. He has stated that a Law Graduate with three years experience at the bar is the minimum qualification, for the appointment as Legal Assistant and that for internal candidates he must possess a Law Degree but I have already stated that there is no rule or circular in support of the said evidence. He has stated that he had first joined as Legal Assistant in special grade and thereafter he was promoted in 1976 in Technical and Supervisory Grade-I although his designation continued as Legal Assistant. He has stated about the job of Legal Assistant and has stated that a Legal Assistant has to prepare comments to enable the Advocates to prepare the statements, rejoinders etc. briefs the lawyers in respect of the cases in the Court and has also to search for the rulings and submit it to the lawyers. He has also stated about the job of Law Clerks and has stated that the Law Clerks are authorised to take certified copies from the Labour Courts/ Tribunals and the AIC (C) and that the Law Clerks are sent with the files to the Lawyers. He has stated that the Personnel department looks after the cases relating to the labour matters of their area whereas the labour matters of the headquarters are dealt with by Law Officers of the Headquarters and that there are Legal Assistant in the Headquarters and not in the area Office He has himself stated in the cross-examination that there is no job description or circular in respect of the Legal Assistant relating to their qualifications. He has admitted that according to the ministerial cadre scheme the minimum qualification for technical and supervisory grade is matriculate and that the Legal Assistant according to the cadre scheme comes under Supervisory grade. Thus, his evidence only supports the facts which I have already discussed in reference to the discussion of the cadre scheme Ext. M-3.

MW-2 Shri M. K. Sharma, Dy. Personnel Manager has stated that the concerned workman is attached to work as P.Os. Clerk in the area office (Area No. IV) and that he is working as a Clerk in the Personnel department attached to the officer of the Personnel department incharge of labour matters and labour cases. He has stated that the post of Legal Assistant is in the headquarters and not in the area office. He has further stated that Shri M. K. Choubey was a Legal Assistant in Katras Areas since before he had joined there in 1983. According to him Shri M. K. Choubey was taken over employee and was a Law Graduate. He has also stated that as the designation of Shri Choubey was of Law Assistant during the private management his designation continued after the take over. He has also stated that the concerned workman has not been promoted from Grade-I to special grade clerk and that P.O. Clerks are of clerical Grade-I and also of a special grade. He has further stated, that the post of Legal Assistant is covered under the supervisory grade and the promotion in the said grade is from clerical side. There is one document Ext. W-1 under the signature of MW-2 in which the concerned workman has been described as Legal Assistant MW-2 has stated that Ext. W-1 bears his signature and adds that he did not know the exact designation of the concerned workman as he had joined on 22-8-1983 and as such he has described him as Legal Assistant. MW-2 has given explanation in his evidence as to why he had described the concerned workman as Legal Assistant. The designation of workman alone is not of importance and the importance is as to what work the concerned workman was doing. I have discussed above the evidence of MW-1 and MW-2 who have stated about the job being performed by the concerned workman. The concerned workman as WW-1 has stated that from 12-3-82 he is working as Legal Assistant in place of Shri M. K. Choubey who was formerly working as Legal Assistant. He has stated that as Legal Assistant he has to prepare the briefs if labour cases, collects documents from the colliery and with those documents he has to discuss with the lawyers of the company and thereafter to prepare note cases. He has further stated that he also looks after the criminal cases and in connection with cases he goes to Dhanbad Court and also at Ranchi bench of Patna High Court. He has admitted that he is a matriculate. In cross-examination he has stated that he was regularised in Clerical Grade-II when he was working as P O's Clerk and that in June 1977 he was promoted in Clerical Grade-I and was working in the personnel department in the area and that till 12-3-82 he was doing the same work of clerk in the area office. He has stated that the Dy. Personnel Manager and Senior Personnel Officer were deputed to deal with all labour matters and the concerned workman was attached to the said office. He has admitted that he had not received any office order promoting him or appointing him as Legal Assistant. He has also admitted that his promotion was not made in accordance with the cardc scheme from Grade-I to special grade. In proof of the job being performed by the concerned workman, some documents have been referred to by the learned advocate appearing on his behalf, Ext. W-1 dated 5-9-83 and W-2 dated 4-11-83 are two documents by which the concerned workman was authorised to obtain certified copies from Courts. Thus these two documents do not show any job of a Legal Assistant, Ext. W-5 and W-6 are the notes which also do not indicated any job of Legal Assistant which was required to be done by the concerned workman through Ext. W-5 and W-6. The jobs entrusted to the concerned workman vide Ext. W-1, W-2, W-5 and W-6 are of a clerk Ext W-4 dated 7-9-83 is the note of the concerned workman This also does not show that the concerned workman had done any specific job of the Legal Assistant or any job which is said to be the job of Legal Assistant in the evidence of WW-1. Ext W-7 dated 20 8-82 is a note of the Personnel Manager for regularisation of the concerned workman to Clerical Grade special. It is stated in Ext. W-7 that the concerned workman who is Grade-I clerk attached to the Personnel section of the area has been representing that as per nature of his job he should be

regularised in clerical grade special. It is stated that the concerned workman has been working in the personnel section since 9 years and that he has been performing all the clerical jobs satisfactorily. It is further stated that with the transfer of Shri M. K. Choubey to Headquarters who was in clerical Grade Special, the matter regarding attachment of the concerned workman with the Senior P. O. was discussed and it was decided that the concerned workman would take charge from Shri M. K. Choubey and since then the concerned workman has been performing the job of special grade satisfactorily and it further shows that the concerned workman has been performing the job of Legal matters satisfactorily and has to deal with many confidential files with regard to the conciliation, industrial tribunal, labour courts etc. Since more than 6 months and as such the Personnel Manager had recommended for his regularisation in clerical grade special. This recommendation, of course, has not been yet approved. Ext. W-7 which has been used by the concerned workman does not denote any of the special jobs of the Legal Assistant as has been stated by him in his evidence. Ext. W-16 dated 27-2-82 is the note of Shri S. K. Singh, Senior Personnel Officer. It shows that the Senior Personnel officer had submitted to the P.M.|G.M. Katras area that the transfer of Shri M. K. Choubey, Legal Assistant special grade may be stayed till a suitable substitute is arranged to handle his files in his charge. The Senior Personnel Officer suggested that the concerned workman who was in Clerical Grade-I be engaged with him in place of Shri M. K. Choubey. This document does not indicate the jobs which were being actually performed by the concerned workman was asked to take over charge of the files and the documents from Shri M. K. Choubey, Legal Assistant who was going to join in Koyala Bhawan on 12-3-82. This Ext. W-17 only directed the concerned workman to take over charge of files and documents from Shri M. K. Choubey and it does not show that the concerned workman had been authorised to do all the jobs of Legal Assistants which were being performed by Shri M. K. Choubey. It is a different matter to take over charge of files and documents from Shri Choubey and it will be a different matter as to what duties were performed by the concerned warkman.

The reference in this case was made on 10-12-84 and a copy of it had been forwarded to the union of the concerned workman. The document Ext. W-13 dated 21-2-85 is a note by the concerned workman was created after the management had filed his W. S. in the present reference. Thus this document has been created during the pendency of the hearing of reference. Ext. W-13 will show that the concerned workman was directed by Shri M. K. Sharma AM(T) Katras Area to meet the Manager (Legal) on 21-2-85 and discussed the matter with him and he was advised to ask Mr. Sharma to see Mr. S. B. Sinha, Advocate, High Court Patna Ranchi Bench at his residence. It has been filed to show that the concerned workman used to have a discussion with the Manager (Legal). Even if it is accepted that the concerned workman was having discussion in legal matters with Senior Officers, it will appear that he was not discussing independently but was discussion under the direction of Shri G. K. Sharma and as such this document cannot be used to show that the concerned workman was doing the job of Legal Assistant. Ext. W-14 is another note in the writing of the concerned workman dated 13-2-85. It is stated that the concerned workman had been verbally directed by Shri Sharma A.M. (T) Katras Area to deal with Case No. Criminal revision 166 of 1984 (R) with the advocate Shri S. B. Sinha at Ranchi and in connection with that case the concerned workman had gone to Ranchi and had contacted the Advocate on 9-2-85 in his chamber and in the high Court. It does not show that the concerned workman had done any job of Legal Assistant i.e. it does not show that the concerned workman had instructed about the facts or law in connection with that case. It will further appear that this was a document created by the concerned workman himself during the pendency of the reference and as such I do not like to put reliance on Ext. W-13 and W-14 in proof of the fact that the concerned workman had done any job of Legal Assistant. The concerned workman has produced one Ext. W-15 dated 2-2-85 which is a bill submitted by Shri R. S. Murthy, Advocate to the General Manager, Katras Area and it has been tried to be shown from para 6(A) that the Learned advocate had charged consultation fees for having a conference with the concerned workman on 9-1-85. I do not intend to place much reliance on this Ext. as it does not show as to what job was actually performed by the concerned workman. No doubt the learned Advocate has charged for conference with the concerned workman but that in itself is no proof that the concerned workman had done any job of Legal Assistant.

The documents produced on behalf of the concerned workman do not indicate the actual job performed by the concerned workman so as to come to a conclusion that the concerned workman was doing the job of Legal Assistant as stated by him in his evidence or in the evidence of the management witnesses. In my opinion the evidence in the case do not establish that the concerned workman was either authorised to perform the job of Legal Assistant or that he was actually performing the job of Legal Assistant.

Another point has been indicated on behalf of the management and it has also been dwelt upon by the workman. Ext. M-2 and M-4 dated 10-2-83 and 18-2-81 respectively are seniority list of Grade-I clerks. It will appear from Ext. M-4 in Sl. No. 61 that the concerned workman Shri R. K. Prasad was appointed on 14-10-71 and was working in Grade-I clerk from 29-6-77 in the area. It will further show in Sl. No. 63 that Udayan De was appointed on 20-10-73 and was working in Clerical Grade-I from 29-6-77. It has been submitted on behalf of the concerned workman that he was senior to Udayan De in Clerical Grade-I although they are working in the said grade from the same date. Ext. W-8 shows that Shri Udayan De was regularised in clerical grade special with effect from 1-5-82. It has been submitted that Shri Udayan De being junior to the concerned workman has been regularised in clerical special grade whereas the concerned workman who is senior to him has not been yet be regularised in Clerical special grade. It is true that the concerned workman has not yet been regularised in Clerical special grade but it will appear from Ext. W-7 that the matter of his regularisation is under consideration of the management and I hope that the management will pass the order of his regularisation in Clerical special grade at least with effect from the date of the regularisation of Udayan De

It will appear from annexure B to Ext. M-3 that for promotion to the post of supervisory clerk a workman must have two years experience in the next below grade and this means that the workman must work in the said lower grade special grade clerk for over two years. The concerned workman has not yet been regularised in clerical special grade and as such even if his case is considered for promotion he cannot be promoted to the technical and supervisory grade as he has not two years experience in Clerical grade special which is must for promotion to the technical and supervisory grade.

In view of the discussion of the entire oral and documents evidence, I hold that the concerned workman although described somewhere as Legal Assistant was not actually performing the duties of a Legal Assistant nor he was authorised or appointed to work as Legal Assistant. From the overall impression of the evidence or record it will appear that the concerned workman was doing the job of a clerk. Admittedly, he is in clerical Grade-I and as his junior has been regularised in clerical special grade and the matter of his regularisation as special grade Clerk is pending before the management, I hold that the concerned workman should be regularised in Clerical special grade at least from 1-5-82 and his seniority in the grade should be maintained.

In view of the above I hold that the action of the management of Katras Area of M|s. B. C. C. Ltd., Dhanbad in not regularising Shri R. K. Prasad as Legal Assistant is justified. I direct the management to regularise the concerned workman in Clerical special grade as indicated above.

This is my Award.

[No. L-24012(38)|84-D. IV(B)]

I. N. SINHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1985

का. आ. 2205.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार वैस्टर्न कोलफील्डज लिमिटेड, ईस्ट डोंगार जिलसे

कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23 अप्रैल, 1985 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 30th April, 1985

NOTIFICATION

S.O. 2205.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of East Dongar Chickly Colliery of Western Coalfields Limited, Pench Area and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd April, 1985.

ANNEXURE 'A'

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(52) of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Coalfields Ltd, Punch Area, in relation to the East Dongar Chickly Colliery, P. O. Parasia Distt. Chhindwa and their workmen represented through the Chhindwara Zila Koyla Khan Karamchari Sangh, P. O. Parasia, District Chhindwara (M. P.).

APPEARANCES :

For Union.—Shri S. S. Sharma.

For Management.—Shri S. M. Singh, Dy. Chief Personnel Manager.

INDUSTRY : Coal. DISTRICT : Chhindwara (M.P.).

AWARD

Dated April 19th 1985

The Central Government in exercise of its powers under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act referred the following dispute for adjudication, vide Notification No. L-22011(90)/82-D. III(B), dated 19th September, 1983 :—

"Whether the action of the management of Western Coalfields Limited, Pench Area in relation to their East Donger Chickly Colliery in paying category IV wages to the following workmen, who are deployed on the job Drillers/Dressers and Stone Cutters is justified ? If not, to what relief the concerned workmen are entitled ?".

ANNEXURE

Sl. No.	Name of the workmen
1.	Shri Saini
2.	Shri Balakram
3.	Shri Sheikh Kalloo
4.	Shri Narayan
5.	Shri Sobha
6.	Shri Darshan
7.	Shri Ram Prashad
8.	Shri Atarlal
9	Shri Sher Ali
10.	Shri Bedga
11	Shri Gaindy
12.	Shri Sumora
13.	Shri Sheikh Chhotey
14.	Shri Amilal
15.	Shri Bushra
16.	Shri Rajan
17.	Shri Rajaram
18.	Shri Mohngu.

2. Eighteen workmen at the relevant time were employed as Stone Cutters in the East Donger Chickly Colliery of M/s. Western Coalfields Ltd., Pench Area, P. O. Parasia, District Chhindwara and were paid category IV wages. They were permanent employees. As Stone Cutters they were required to do the work of cutting dains in the floor strata, making water sumps, driving stone drifts, making shot holes in stone in preparation for blasting etc. These were the normal duties of the Stone Cutters. The workers claim that the management was taking from the work and duties of Coal Dressers and Drillers. The duties of Coal Dressers are dressing the roof sides and floor of a coal piller or gallary generallly after shots have been fired in order to render the working place safe to work in. In short they work in the coal bearing areas and do the dressing of coal. The Drillers are required to operate a power driven drill to make holes in coal and other strata for blasting and other purposes. They also carry trailing cables, drilling rods, bits, etc.

3 The workmen in their statement have narrated number of duties of the Coal Dressers and Drillers that they were doing besides stone cutting. This is also their evidence. Now the dispute is that since they are asked to do the duties of coal Dressers and Drillers they must be given some extra amount and they must be given the higher grade. The demand seems to be wholly misconceived.

4. The job description given in the Central Wage Board Award for Coal Mining Industry warrants such workmen to be placed in Category IV. There is no dispute that the workers in question are already placed in Cat. IV and are getting the wages of Cat. IV. The Coal Cutters and Drillers also are placed in Cat. IV Therefore the above workmen at no time are doing such work as is done by a workman of higher category than Cat. IV. Now if during the same period of hours instead of the job of stone cutting which is more arduous than that of coal cutting the workman are asked to do the work of coal dressing and drilling I do not see how they are entitled to higher wages. According to the job description of the workmen. Take them as Coal Cutters or Drillers or Stone Cutters in no case they are entitled to a category more than Cat. IV. Therefore they are not entitled to any higher wages. In the view I have taken above I need not decide any other point, preliminary or otherwise.

ORDER.—The claim made by the above workman is not sustainable They are all rightly being paid the Cat. IV wages. They are not entitled to any relief. However, in the peculiar circumstances of the case there shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer
[No. 22011/90/82-D. III(B)/V]

नई दिल्ली, 1 मई, 1985

का. आ. 2206.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ईस्ट कादरास कोलियरी मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 27-4-85 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 1st May, 1985

S.O. 2206.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of East Katras Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th April, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD.

Reference No. 79 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of East Katras Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.

On behalf of the workmen : Shri J. P. Singh, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 22nd April, 1985.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(49)|84-D. IV(B) dated the 18th October, 1984.

THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of East Katras Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Limited will not providing job to Sri Misri Bhuiya dependant of Shri Kantu Bhuiya who died while in service is justified ? If not, what relief the workman is entitled ?"

The case of the workmen is that late Kantu Bhuiya was working as Wagon loader in East Katras Colliery of M|s. B. C.C. Ltd. On 1-6-79 when deceased Kantu Bhuiya was loading coal into wagons he fell down from the wooden stairs and received head injury He was examined by the colliery doctor and was ultimately sent to Central Hospital Dhanbad where he died on 3-6-79 due to cerebral vascular Death certificate was granted from the Central Hospital, Dhanbad. Mishri Bhuiya is the only son and dependent of deceased Kantu Bhuiya surviving after the death of Kantu Bhuiya. Misri Bhuia approached the Colliery management several times for his appointment in place of his father late Kantu Bhuia in accordance with para 10.4.2 of NCWA-II according to which one of the son dependent of the deceased workman dying in harness is entitled to employment in place of the deceased The colliery management gave assurance but shelved the matter indefinitely. Thereafter Misri Bhuia approached Daljit Mazdoor Singh, the Union of his father for taking necessary steps for securing appointment of Misri Bhuia in place of his deceased father The said union held meeting with the management regarding the appointment of Misri Bhuiya in place of his deceased father but the management did not give any employment to him. Thereafter the said union raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad and on failure of the conciliation, the present reference has been made The management in their W.S. before the conciliation officer had taken a plea that since deceased Kantu Bhuiya was a casual employee of the colliery, his dependant cannot get any advantage under NCWA-II. It is submitted on behalf of the workmen that para 10.4.2 of NCWA-II makes no distinction between a permanent employee or a casual employee in the matter of appointment of a dependant of the deceased employee. It is praved that Misri Bhuiya may be given employment with effect from the date of death of his father.

The case of the management is that the matter referred to Tribunal does not fall within the scope of Section 2(k) of the I D Act and that no industrial dispute was raised with the management by the sponsoring union or the claimant. Misri Bhuiya is not a workman and as such no industrial dispute can exist as between him and the management. Misri Bhuiya had not made any application to the management for providing him any employment on any ground. The claim of Misri Bhuiya is not covered under the provision of NCWA-II and the same cannot be enforced through adjudication under the I.D. Act. Late Kantu Bhuiya was employed by the management as a casual wagon loader. He had not completed 240 days attendance during any continuous period of 12 months and as such he cannot have the status of a regular workman under the management. As a casual worker himself has no right for regular employment, Misri Bhuiya cannot have a right for employment under the management. The claim of Misri Bhuiya and the sponsoring union are untenable and illegal and is liable to be rejected.

The management filed a rejoinder in respect of the W.S of the workmen wherein it is stated that Kantu Bhuia did sot receive any read injury while he was loading coal into wagon and it is stated that Kantu Bhuiya had fallen sick from 1-1-79 when he was not on duty and was given treatment in the East Katras Colliery dispensary and thereafter referred to Regional Hospital of Coal Mines Welfare Organisation at Tilatand near Katras for further treatment. Late Kantu Bhuiya had not reported for work on 1-1-79. The union has mainpulated in getting a false and fabricated death certificate of Kantu Bhuiya. The management further denied that Misri Bhuiva was a dependent of late Kantu Bhuiya. It was asserted that late Kantu Bhuiya had no children.

The point for consideration is whether Misri Bhuiya is entitled for employment as dependant of late Kantu Bhuiya who died while in service,

The management have examined three witnesses in support of their case. The union has examined Misri Bhuiya who has claimed for employment, and one Sukur Bhuiya in support of the case of the workmen. The management have produced documents which have been marked Ext. M-1 to Ext. M-5 and the workmen have produced documents which have been marked as Ext. W-1 to W-5.

The claim of the workmen for employment of Misri Bhuiya is based under clause 10.4.2 of NCWA-II. It would be better to refer clause 10.4.1 of NCWA-II where provisions of employment to dependants is stated It provides "Employment would be provided to one dependant of workers disabled permanently and those who meet with death while in service. This provision will be implemented as follows : Para 10.4.2 :—Employment of one dependant of the worker who dies while in service." It will thus appear from the above provision in NCWA-II that employment has to be given to one dependant of the deceased worker who dies while in service or those workers who are disabled permanently. The question therefore is whether Kantu Bhuiya had died while in service Misri Bhuiya or the union can claim employment of a dependent only when Kantu Bhuiya died while in service I will, therefore, discuss the evidence regarding the fact whether Kantu Bhuiya died while in service.

It is the admitted case of the parties that Kantu Bhuiya was working as a wagon loader in East Katras Colliery of BCCL Ext. W-3 is the comment of the management before the ALC(C), Dhanbad dated 17-5-84 wherein it is stated that late Kantu Bhuia was a casual wagon loader at East Katras Colliery who died on 3-6-79 It further appears from Ext. W-3 that as there was no provision in NCWA-II for providing employment to the dependant of casual employee after his death and accordingly the case of the dependant of late Kantu Bhuia was not considered by the management It was also stated that late Kantu Bhuiya during his service, had never completed 240 days attendance in a year. Thus the objection of the management at the first stage before the ALC(C) Dhanbad when the dispute was raised by the union was that employment to Misri Bhuiya could not be

given as Kantu Bhuiya was a casual employee. There is no mention of the fact that Kantu Bhuia was not the father of Misri Bhuia and that Kantu Bhuia was not in service at the time of his death. Even in the W.S. filed on behalf of the management there is no denial of the fact that Misri Bhuia was not the son of Kantu Bhuia or that Kantu Bhuia was not in service at the time of his death. Thus the W.S. of the management almost had the plea which was first taken before the ALC(C), Dhanbad. It is only in the rejoinder of the management dated 10-1-85 that the case has further been developed denying that Misri Bhuia was the son of late Kantu Bhuia. But even in this rejoinder of the management there is no mention of the fact that Kantu Bhuia was not in the employment at the time of his death. It is only in the evidence of MW-2 that the case of the management has been further developed wherein it is stated that Kantu Bhuia worked till 25-5-79 and that he had not come to work on 1-6-79. I have stated the above facts just to show how the management was improving their own case from stage to stage and had not placed their entire card of plea at the first stage when the industrial dispute was raised before the ALC(C) and this fact itself shows that the management was developing stores from stage to stage so that Misri Bhuia may not succeed in his claim. The management has filed Bonus Register Ext. M-1 to M-1/7, Attendance Register Ext. M-2, Register of Sickness Ext. M-3, and Register of Accident Ext. M-4, which all show that Kantu Bhuia was in service of the management. From Ext. M-3 it will appear that on 1-6-79 Kantu Bhuia had received injuries and as such he was treated in the colliery hospital and thereafter he was referred for treatment to Regional Hospital. The relevant entry in Ext. M-3 Sl. No. 9011 dated 1-6-79 showing Kantu Bhuia as Wagon Loader and diagnosis was unconscious. Ext. W-5 is a certificate of death granted by Central Hospital, Dhanbad dt. 3-6-79 which shows that Kantu Bhuia loader of East Katras Colliery who was admitted in the said hospital on 1-6-79 died on 3-6-79 at 9.40 P.M. due to cerebral vascula due to accident. Ext. M-2 is the attendance register which shows that Kantu Bhuia was a Wagon Loader in East Katras Colliery where his attendance was marked. Sl. No. 30 for the period 16-5-79 to 15-6-79 of the Attendance Register shows that Kantu Bhuia had been marked present till 25-5-79 and that thereafter his attendance has not been marked. From all these documents it is clear that Kantu Bhuia was working as Loader in East Katras Colliery till before the period of his death. Even MW-2 has accepted that Kantu Bhuia had worked till 25-5-79. The case of the workmen is that on 1-6-79 while Kantu Bhuia was loading coal in the wagon he fell down unconscious having received injuries in his head and it is quite possible as he had received injuries and was sent to the hospital, his attendance was not marked on 1-6-79 in the attendance Register. WW-2 who is a co-worker of Kantu Bhuia has stated that Kantu Bhuia had fallen down while loading wagon and had received injuries on his head. He had seen the injury as he was working in the same gang consisting of 13 persons in which Kantu Bhuia was working. Thus there is the specific evidence of WW-2 to show that Kantu Bhuia had received injury by a fall while loading wagons. Admittedly, MW-1 and MW-2 were not present in the colliery. Considering the entire evidence on the point I hold that Kantu Bhiya died on 3-6-79 while in service as Wagon loader in East Katras Colliery.

The next question to be considered is whether Misri Bhuia is a son of late Kantu Bhuia. In the W.S. filed on behalf of the management it has not been stated that Misri Bhuia was not the son of Kantu Bhuia. The management had filed its comments before the ALC(C), Dhanbad on 17-5-1984 when industrial dispute was raised by the Union of behalf of the concerned workman. The said comment is Ext. W-3. It is nowhere stated that Misri Bhuia was not the son of Kantu Bhuia in the said comment and the only plea on which the employment was being denied was on the ground that there was no provision in NCWA II for providing employment to the dependent of casual employee. If Misri Bhuia had not been the son of Kantu Bhuia the management would have stated the said fact in its comment Ext. W-3 and also in the W.S. Ext. W-1 is a note of discussion between Shri Karu Ram, General Secretary, Dalit Mazdoor Sangh and the management dated 30-9-83. Item No. VII of the said note of discussion is in respect of the employment to the dependant of Kantu Bhuia. The decision against the said point was that the employment to the dependant of casual wagon loader respect of the employment to the dependant of Kantu Bhuia. 240 days in the year 1978. It is not stated by the management that Misri Bhuia was not the son of Kantu Bhuia when employment was demanded by the union in respect of the dependant of Kantu Bhuia. Ext. W-2 dated 29-3-84 is the petition through which Karu Ram, General Secretary, Dalit Mazdoor Sangh had raised the industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad in respect of Misri Bhuiya dependant of Late Kantu Bhuiya. Ext. W-3 was in reply to the said industrial dispute raised in Ext. W-2 and if Misri Bhuia was not the son of Kantu Bhuia the management must have denied about the fact of Misri Bhuia being the son of Kantu Bhuia. Ext. W-4 dated 25-5-82 is the earlier petition made by Shri Karu Ram, Vice President of Bihar Rajya Mushar Sewa Sangh in which also a demand was earlier made for the employment of Misri Bhuia son of Kantu Bhuia under the provisions of NCWA-II as the widow of Kantu Bhuia had represented before the said union that the management was not giving employment to her son Misri Bhuia. The management has not produced any document to show that Misri Bhuia is not the son of Kantu Bhuia. MW-1 has not stated anything about Misri Bhuia. MW-2 has stated that Kantu Bhuia has no son or daughter. MW-2 did not know the village home of Kantu Bhuia and had not gone to his residence in Bhandaridi where he was residing while working as Wagon Loader. MW-2 had no occasion to go to the village home and residence of Kantu Bhuia and as such it was not possible for him to specifically state that Kantu Bhuia had no son or daughter. MW-3 has stated that Kantu Bhuiya had no issue and he had enquired about this. He has further stated that there was a discussion between Karu Ram and the management at the area level and it was decided that the record be shown to Shri Karu Ram and the record was shown to him. In cross-examination he had stated that Kantu Bhuia had died before he had joined in East Katras Colliery. He had not seen the wife of Kantu Bhuia. He has further stated that he had gone to enquire at the residence of Kantu Bhuia after the present reference was made to this Tribunal and had found the house of Kantu Bhuia vacant and was not locked. Even if his evidence is believed it may be that Misri Bhuia was not present in the said house at the time of his visit and as such the evidence of MW-3 cannot be used to show that Kantu Bhuia had no son. He has stated about the minutes of discussion between Karu Ram and the management and the same has been marked as Ext. W-1. Thus the oral evidence adduced on behalf of the management does not establish the fact that Misri Bhuia was not the son of Kantu Bhuia on the contrary Misri Bhuia WW-1 has stated on oath that he is the son of Kantu Bhuia. WW-2 Sukur Bhuia is a co-villager of Kantu Bhuia and was working with Kantu Bhuia in East Katras Colliery. He has stated that Misri Bhuia is the son of Kantu Bhuia and that after the death of Knatu Bhuiya he had gone to village home to inform about the death of Kantu Bhuia to Misri Bhuia and that thereafter Misri Bhuia came to Katras and performed Shradh of Kantu Bhuia. This witness appears to be very competent witness being a co-villager and co-worker of Kantu Bhuia and there is no reason to disbelieve his evidence. On the above evidence it will appear that there is positive evidence adduced on behalf of the workman that Misri Bhuia is the son of Kantu Bhuia. The oral evidence adduced on behalf of the management is not at all of any competent witness to deny the relationship of Misri Bhuia with Kantu Bhuia. The management had not in the earlier stages before the ALC(C) and in their W.S. denied that Misri Bhuia is not the son of Kantu Bhuia. I hold that this plea of denial of relationship taken on behalf of the management in their rejoinder to the W.S. of the workmen cannot be believed. There is no provision for filling of rejoinder by the management under the new rules because the W.S is filed by the management only after he receives the WS of the workmen and W.S of the management itself contains the rejoinder to the W.S. of the workmen. In this view of the matter the plea taken in the rejoinder filed on behalf of the management cannot be said to be the specific case of the management. Considering all the above matters I hold that Misri Bhuia is the son of Kantu Bhuia.

The main plea of the management in not providing employment to Misri Bhuia is that late Kantu Bhuia was him-

self a casual wagon loader having not completed 240 days of attendance in a year and as such the provision under NCWA-II were not available to Misri Bhuia. From evidence on record it appears that late Kantu Bhuia was a casual wagon loader. The Bonus Register Ext. M-1 to M-1/7 shows that Kantu Bhuia had not completed 240 days of attendance in any particular year. However, the evidence of Mw-1 and the Bonus Register Ext. M-1 to M-1/7 will show that Kantu Bhuia was working as a wagon loader since 1971 and it appears that he could not complete 240 days attendance in a year because continuous work was not given to him by the management. The fact that he was working as wagon loader since 1971 indicates that he was almost permanently employed to work as wagon loader on casual basis. It is true that Misri Bhuia cannot claim to have better footing of employment than that of his father Kantu Bhuia who was himself a casual wagon loader. Misri Bhuia at best can claim employment in place of his father Kantu Bhuia as Casual wagon loader. The provision under para 10.4.2 of NCWA-II does not specially distinguish between a casual worker and a permanent worker. What it contemplates is that employment of one dependant of the workman who dies while in service is to be provided. The management cannot of its own accord draw a line of distinction by suggesting that as late Kantu Bhuia was a casual wagon loader employment cannot be given to his depedant. MW-3 has stated income cross-examination that employment of a dependant of a deceased workman is give nunder the provisions of 10.4.1 of NCWA-II. He has further stated that there is an instruction in writing in BCCL which was issued after NCWA-II. He was deposing on the issue whether there is any instruction or circular issued by BCCL by which a dependant of a casual workman was not to be provided with employment. Although MW-3 has stated that there was some instruction, the management has not filed and it appears that this evidence has been introduced just to have a defence for a denial of employment to the concerned workman. In my opinion, had there been any such instruction the management must have filed the same. What is of importance under para 10.4.1 is whether late Kantu Bhuia was workman of BCCL and this fact is not denied "workmen under section 2(s) of the I.D. Act has been denied to mean person employed in any injury to any skilled or unskilled manual work for hire or reward and as such late Kantu Bhuia will come under the definition of workmen and the son of Kantu Bhuia may claim employment on the death of Kantu Bhuia while he was in service being a dependant of late Kantu Bhuiya.

It has been submitted on behalf of the management that present dispute is not an industrial dispute in as much as Misri Bhuia is not a workman. In my opinion the present dispute undoubtedly is an industrial dispute within the meaning of the I.D. Act. Industrial dispute has been defined in Section 2(k) of the I.D. Act which means any dispute or difference between employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labour of any person. Where the workmen raise a dispute against their employer, tre person regarding whose employment terms of employment or conditions of labour the dispute is raised, need not be, strictly speaking "Workman" within the meaning of the I.D. Act, but must be one in whose employment terms of employment or conditions of labour the workman as a class have a direct or substantial interest. The definition of the expression "Industrial Disputes" is wide enough to cover a dispute raised by the employer's, workmen in regard to the non-employment of others who may not be his workmen at the material time. The word "Any person" in the definition of the Industrial dispute is not limited to workmen as such and must therefore receive most general meaning. The workmen for example can raise a dispute that a class of employee not within the definition of 'workmen' should be recruited by promition from workman and when such dispute is raised the workmen raise the dispute about terms of their own employment though incidently the terms of employment of those who are not workmen are involved. The union of workmen of BCCL have direct and substantial interest in the question wrether dependant of an emplovee who dies in harness is entitled to get emplovment and such question may arise in their cases also when some of them die while working and their dependant should get employment and as such this is a question in which all workmen of the management have a direct and substantial interest. In view of the above I hold that the matter which has been taken up by the union in respect of employment of Misri Bhuiya san industrial dispute contemplated under Section 2(k) of the I.D. Act.

I have already referred to the documents which show that industrial dispute had been raised on behalf of the union and that the demand was made to the management for the employment of Misri Bhuia in place of his deceased father and thereafter an industrial dispute was raised before the ALC(C) Dhanbad. There is evidence to the effect that the union which has raised the industrial dispute was the union of late Kantu Bhuia.

In view of the facts, evidence and the point of law discussed above, I hold that the action of the management of East Katras Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. in not providing job to Misri Bhuiya, dependant of Kantu Bhuiya who died while in service, was not justified. I further hold that the management should give employment to Misri Bhuia under the provision of NCWA-II in place of his father late Kantu Bhuia who died while in service of the management as casual wagon loader with immediate effect.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-24012(49)/84-D.IV(B)]

नई दिल्ली, 3 मई, 1985

का. आ. 2207.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2 मई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd May, 1985

S.O. 2207.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd May, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No I.D 30/84

PARTIES :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India.

AND

Their Workman—Jagdish Kumar.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri N. K. Zakhmi.

For the Workman—Shri Hardayal Singh.

INDUSTRY: Food Corporation of India STATE Punjab

AWARD

Dated the 29th of April, 1985

The Central Govt. Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, vide their Order No. L-42012(8)/83-D. IV(B)/D.V. dated the 7th of July, 1984

referred the following industrial disputes to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the termination of services of Sh. Jagdish Kumar unskiled worker by the management of the Food Corporation of India, Chandigarh w.e.f. 17|1|1983 is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled and from what date ?"

2. Brief facts of the case, according to the petitioner| workman, are that he had been working as a daily-wage worker @Rs. 12 per diem with the Respdt. Corporation since 24-1-1981 and that his services were terminated on 17-1-1983 without any notice, charge sheet of enquiry. He, therefore, agitated against his termination and insisted for his re-instatement with full back wages and continuity of service, but the Respdt. Management was found unresponsive despite the intervention of the ALC(C) at the Conciliation stage and hence the reference.

3. Resisting the proceedings, the Management pleaded that the petitioner was employed by them as a daily-wage casual worker to supplement the Watch and Word staff on the Open Storage Complex and was disengaged on 31-12-1982 when he voluntarily resigned on the representation that he had secured a better job at some other place. To be precise, without denying the petitioner's disengagement they projected that it was a case of voluntary resignation. In the same sequence the allegations of any animus or motivation were vehamently controverted.

4. Shortly after the receipt of the reference a similar dispute between the same Management and one Sh. Pal Singh was also referred by the Central Govt. to this Tribunal for adjudication per their Order No. L-42012(6)|83. IV(B)|D.V. dated the 19th of Sept. 1984. Since common questions of fact and law were involved in both these cases, therefore, at the recorded request of the parties they were consolidated and tried together in the instant case to avoid multiplicity of proceedings, and apprehension of conflicting findings besides any unnecessary financial strains to them. So obviously, both these cases shall stand decided together by this common Award.

5. Keeping in view the comprehensive nature of the terms of reference, the parties were called upon to adduce evidence in support of their respective versions without going through the drill of formal issues. Thus both the petitioners examined themselves whereas the Management produced their Asstt. Depot Manager Sh. N. S. Ahuja alongwith a few documents including the relevant Attendance register.

6. I have carefully gone through the entire available data and heard the parties. On behalf of the Management my attention was drawn towards para No. 3 of the Affidavits Exts. W1 and W2 of the petitioners Pal Singh and Jagdish Kumar respectively wherein while denying the validity of the resignation both of them conceded having signed the same; albiet, they would have one believe that they were made to affix their signature under the relevant resignation—endorsement by the Supervising staff on the pretext of marking attendance. But significantly enough during their cross-examination both the petitioners denied even having signed the Resignation—endorsement.

7. Copy of the said endorsement has been filed on records as Ex. N1 and the original was also made available for inspection by the Tribunal as well as the Opposite prty Similarly the entire sheet from the Attendance register for the month for December 1982, which contained the aforesaid Endorsement along with the signatures of the petitioners was got photographed and filed as Ex. M4. The original, written in Gurmukhi script, reads as below:—

"Asi apni marji nal 31-12-1982 on band PCI Kurali vich nokari karan ton inkari karde han kyonki sahnu hor kam mil gaya ha."

'Pal Singh and Jagdish Singh'.

8. It was thus argued that having chosen a green pasture of some better employment, the petitioners abandoned their jobs with the FCI. on their own notion and now on second thoughts they cannot be permitted to retrace their steps by hurling allegations of impropriety or malice on the part of the Management. In the same sequence it was urged that since the petitioners were engaged as mere casual labourers without any formal orders of appointment, therefore, there could be no occasion to insist on their formal letters of resignation; and that otherwise also since the resignation had already been accepted and acted upon, therefore, any lack of formalities therein would not vitiate its validity. Th s ld. counsel then referred me to the receipts Ex. M9 and M10 to show that the wages up to December 1982 have also been paid to both the petitioners in full and final settlement of their dues.

9. Inspite of seeming attraction the submissions failed to carry conviction with me. The pertinent po nt is that the learned counsel appears to have taken a myopic view of some convenient, but isolated, features of the case whereas it is in the totality of the situation that we have to determine the validity of the resignation. Of course the petitioners do appear to have played smart by denying their signatures on the resignation—endorsement in the Attendance register, though by necessary implication it was conceded in their claim-statement yet that by itself does not discredit their cause.

10. To come to the grips with the crucial aspect of the issue, a careful scrutiny of page No. 22 of the Attendance register, pertaining to the petitioners for the month of December 1982 would be essential. Besides some other data it also contains the impugned Registration-endorsement whose contents have already been reproduced here-in-before and need not be repeated; but what is significant is that on the right hand side of the sheet, there is an Office Order of the even date recorded by the Depot Incharge and attested by his senior Officer which reads as below :

"The services of Sh. Pal Singh and Sh. Jagdish Kumar may be discontinued as per note submitted by the above C|L. Further the continuous service of said C|L comes to be 82 days and 80 days at a length and as per Dist. Office Order services should not be allowed to continue for more than 89 days. Hence recommended for discontinuation."

11. For ready hand reference of the Tribunal, and at the request of the petitioners the Management was made to file a photostat copy of this sheet per Ex. M-4; it shows the resignation-endorsements at point 'A' and the aforesaid Office Order at point 'B'. A combined reading thereof would leave no manner of doubt that the Office Order had preceded the incident of resignation, because had it been otherwise there must have a reference to the incident of resignation. On the other hand the Office Order further exposed a sort of convention or practice in the Corporation frowning upon the continuation of some body's work as a casual labourer for more than 89 days at a stretch. And precisely, it was in pursuance of such policy that the petitioners' disengagement was recommended and they were forced into owning the impugned endorsement of resignation.

12. One may not insist upon the necessity of formal letters of resignation by the petitioners since there was no regular Order of appointment either, any the attendance register was the only document establishing their tenure under the Corporation. But all the same one can not loose sight of the fact that there was only one common resignation endorsement under which they were made to affix their signatures. Be that as it may, in the totality of the situation I do not feel inclined to accept the proposition that they had voluntarily abandoned their job. On the other hand it rather appears that they were made to resign so as to keep in line with the Managements policy against regular employment of casual workforce. And so far as the receipts Ex. M9 and M10 are concerned, they show nothing except that payment of wages for the period from October to December 1982 was ultimately cleared off.

13. The second part of the issue was as to whether the disengagement took place w.e.f. 17-1-1983 or earlier. There is no evidence on record to show that either of the petitioners had discharged any duty for Corporation at any place or stage after 31-12-1982; meaning thereby that the act of termination, irrespective of its merits, had already been completed on 31-12-1982.

14. No other point was raised before me and, thus, to conclude with my aforesaid discussion, I hold that the Management acted illegally on the assumption of voluntary resignations. As a natural consequence, I return my Award in the petitioners' favour with a direction to the Management to reinstate them retrospectively w.e.f. 1-1-1983 alongwith all the attendant service benefits except in the context of back wages which would be restricted to 50 per cent of the dues in view of the peculiar circumstances of the case.

29-4-1985.

I. P. VASHISHTH, Presiding Officer.

Chandigarh

[No. L-42012(8)/83-DIV(B)/DV]

नई दिल्ली, 29 अप्रैल 1985

का.आ. 2208.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सनाय-यमन अरब गणराज्य में भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव श्री डी. आर. राजू को सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां प्रयोग करने और उन नियोजकों को, जो किसी भारतीय नागरिक को उस देश में रोजगार देने के प्रयोजनार्थ भारतीय नागरिक नहीं है; परमिट जारी करने का अधिकार देती है ।

[फा. सं. ए-22020/1/85-उत्प्रवास-II]

ए. के. टण्डन, उत्प्रवास
महा संरक्षक और संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th April, 1985

S.O. 2208.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri D. R. Raju Second Secretary of Indian Embassy Sana'a-Yeman Arab Republic to exercise the powers of Competent Authority and to issue permits to the employers who are not citizens of India for the purpose of recruiting any citizen of India for Employment in that country.

[F. No. A-22020/1/85-Emig. II]

A. K. TANDON, Protector General of Emigrants and Jt. Secy.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1985

का. आ. 2209.—बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उप-नियम (2) के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :—

1 श्रम मंत्री, महाराष्ट्र	अध्यक्ष
2. कल्याण आयुक्त, 142, रामदास पेठ, नागपुर	उपाध्यक्ष (पदेन)
3. श्री केवलचन्द जैन, सदस्य विधान परिषद्, गोन्दिया, जिला भन्डारा	सदस्य
4 श्रमायुक्त, बम्बई	सदस्य (पदेन)
5. श्री के. बी. शारदा, प्रबन्ध निदेशक, सिन्नर बिडी उद्योग लि. सिन्नर, जिला नासिक, महाराष्ट्र	नियोजकों के प्रतिनिधि
6. श्री नेमीकुमार केशरीमल पोरवाल प्रेसीडेंट, वेस्टर्न महाराष्ट्र, बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, काम्पटी, जिला नागपुर महाराष्ट्र	
7. श्री एस.एम. रामटेक, जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र राज्य बीड़ी मजदूर संघ, काम्पटी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
8. श्री राम मल्लायया आदिगोपाल, प्रेजीडेंट अहमदनगर सिटी इंदिरा प्रणित बीड़ी कामगार संघ, 4237, पपाया गल्ली, अहमदनगर, महाराष्ट्र	
9. श्रीमती रेणकाबाई बदधया, प्रेजीडेंट, राष्ट्रीय बीड़ी मजदूर संघ, 408, सरवार पेठ, शोलापुर, महाराराष्ट्र	महिला प्रतिनिधि
10. कल्याण आयुक्त, नागपुर	सचिव

2. केन्द्रीय सरकार, उक्त नियमों के नियम 16 के अधीन उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नागपुर नियत करती है ।

[यू०-19012/13/84-कल्याण-II]

New Delhi, the 23rd April, 1985

S O No. 2209.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976, (62 of 1976) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby re-constitutes an Advisory Committee for the State of Maharashtra consisting of the following members, namely :—

1 Minister of Labour Maharashtra State	—Chairman
2 Welfare Commissioner, 142, Ramdas Peth, Badkas Bungalow, Nagpur	Vice-Chairman (ex-officio)
3 Shri Kevalchand Jain, Member Legislative Council, Gondia, District Bhandara	—Member
4 The Commissioner of Labour, Bombay	—Member (ex-officio)
5. Shri K B Sarda, Managing Director, Sinnar Beedi Udyog Ltd., Sinner, District Nasik.	Employers' representatives
6. Shri Nemikumar Kesrimal Porwal President, Western Maharashtra Beedi Manufacturing Association, Kamptee District Nagpur.	
7. Shri S.M Ramteke, General Secretary Maharashtra Rajya Beedi Mazdoor Sangh, Kamptee, District Nagpur.	Employee's representatives.
8. Shri Ram Mallayya Adigopal, President, Ahmednagar City Indira, Pranit Beedi Kumgar Sangh, 4237, Papaya Galli, Ahmednagar	
9. Shrimati Renukabai Wadhya, President, Rashtriya Beedi Mazdoor Sangh, 108, Sakhar Peth, Solapur, Maharashtra	Women representative
10. Welfare Administrator, Nagpur.	Secretary.

2. Under rule 16 of the said rules, the Central Government hereby fixes Nagpur to be the headquarters of the said Advisory Committee.

[No. U-19012/13/84-W.II]

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1985

का. आ. 2210.—बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उप नियम (2) के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए एक सलाहकार समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं, अर्थात् :—

1. श्रम मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद ।	अध्यक्ष
2. कल्याण आयुक्त, डी-सं. 1-7-145/प्लाट सं.—6, श्री निवासनगर कालोनी, सुभाष टाकीज के सामने हैदराबाद-500048.	उपाध्यक्ष (पदेन)
3. संयुक्त श्रमायुक्त-II, श्रमायुक्त का कार्यालय, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।	सदस्य
4. श्री के. वी. नारायण राव, विधान सभा सदस्य, सीरपुर ।	सदस्य
5. श्री मणीलाल बी. उपाध्याय, बीडी मैन्युफैक्चरर्स एण्ड तम्बाकू मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, निजामाबाद	नियोजकों के प्रतिनिधि
6. श्री ए० जे० मोहम्मद अली, साझेदार, ए. जे. मोहम्मद अली एण्ड सन्स, डायमण्ड बीडी फैक्टरी वारंगल ।	
7. श्री के. आनन्द रेड्डी, प्रेजीडेंट निजामाबाद बीडी मजदूर संघ, निजामाबाद-503001	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
8. श्री के० कृष्णा मूर्ति प्रेजीडेन्ट बीडी एण्ड सिगार वर्कर्स यूनियन वारंगल ।	
9. श्रीमती बी० सुशीला, उपाध्यक्ष, बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स यूनियन, वारंगल ।	महिला प्रतिनिधि
10. कल्याण प्रशासक, काशीबेड़ु	सचिव

2. उक्त नियमों के नियत 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार हैदराबाद को उपरोक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नियत करती है ।

[संख्या यू. 19012/3/83-कल्याण-II]

रवि दत्त मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 30th April, 1985

S O 2210 – In exercise of the powers conferred by section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976, (62 of 1976) read with sub-rule ( ) of rule 3 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby reconstitutes an Advisory Committee for the State of Andhra Pradesh consisting of the following members, namely —

1	Labour Minister, Govt of Andhra Pradesh, Hyderabad	Chairman
2	Welfare Commissioner, D No 1-7-145/Plot No 6, Srinivasnagar Colony, Opp Subhash Talkies Hyderabad-500048	Vice-Chairman (Ex-Officio)
3.	Joint Commissioner of Labour II, Office of Labour Commissioner, Hyderabad, Andhra Pradesh	Member
4	Shri K V Narayana Rao, M L A, Sirpur	Member
5	Shri Manilal B Upadyaya, Beedi Manufacturers and Tobacco Merchants Association, Nizamabad	Employers' representatives
6	Shri A J Mohammed Ali Partner, A. J Mohammed Ali & Sons, Diamond Beedi Factory, Warangal	
7	Shri K Ananth Reddy, President, Nizamabad Beedi Mazdoor Sangh, Nizamabad-503001	Employees' representatives
8	Shri K Krishna Murty, President, Beedi & Cigar Workers Union, Warangal-506002	
9.	Smt B Sushila, Vice President, Beedi & Cigar Workers Union Warangal	Women representative
10	Welfare Administrator, Kalichedu	Secretary

2 The Central Government in exercise of the powers conferred by rule 16 of the said rules, hereby fixes Hyderabad a the headquarter of the said Advisory Committee

[No U-19012/3/83-W II]
R D Mishra, Under Secy

नई दिल्ली, 1 मई 1985

का० आ० 2211 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-4-85 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या-एल० 12012/129/82-डी २(ए)]

New Delhi, the 1st May, 1985

S O. 2211 —In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th April, 1985

ANNEXURE

BEFORE SHRI R B SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

In the matter of Dispute between —

Shri Hari Om, C|o Shri V K Gupta, 2|363 Namnair Agra

AND

The Management of the Statet Bank of India, through its Regional Manager, State Bank of India Lauris Hotel, Agra

Shri V K Gupta, representative for the Workman

Shri S S Sharma representative for the Management Bank

AWARD

The Central Government Ministry of Labour vide its order dt 8-4-83, No L-12012|129|82-D II(A), referred the following dispute for adjudication

"Whether the action of the management of State Bank of India in relation to its Aligarh Branch, in ignoring Shri Hari Om Massenger for promotion to the Post of Clerk is justified ? If not to what relief is the workman concerned is entitled ?"

The facts of the case are simple The workman is a substaff of the management bank with qualification as Matriculation Under rules qualified persons are given four chances to appear in promotional test subject to the reservation and the fourth chance is to be availed only after a gap of year from the IIIrd unsuccessful attempt The IIIrd chance availed by the workman was on 5th Oct, 80 in which he too failed The 4th test was held on 31st Dec 81 i e after completion of one year from 5th October, 80, but the management did not allow the workman to appear in the examination on the pretext that he was debarred from appearing in the IVth chance of test having failed in three previous chances, which action according to the workman was arbi

trary, malafide and illegal and hence the workman should be declared successful with retrospective date.

The management in their written statement asserted their stand that the workman had failed to qualify in any of the 1st three chances given to him. He was entitled to the fourth chance only after a gap of one chance from the date of his last unsuccessful attempt. The fourth chance in the case of workman was due in 1982 which too he availed but failed to ualify the same. Because the whole dispute boils down to the interpretation of the rule regarding sub staff promotion to the clerk cadre. The workman has filed the photo copy of the page 191 of chapter 17th defying the promotional opportunity for the members of Award Staff referring para 489. It lays promotional avenues for the members of sub staff. Rule 44 deals with qualification etc. and rule 489; deals with for the number of chance in the following words:

"The members of sub staff are given four chance in all, inclusive of the chance availed by them since 1-1-72 to appear in the written test. 4th chance will be given after a gap of one year from IIIrd unsuccessful attempt."

The workmen has also filed special circular letter No. 22|123 dt. 5th July 1978. In this circular after incorporating rule 489 at serial I a clarification was added in the following words :

"In other words those who appeared for third chance on 11 Dec., 77 will not be allowed to avail the 4th chance in the ensuing test".

The management has filed two circular special letters one No. 22|92 dt. 13-7-81 and the other 22|129 dt. 25-8-83. In the letter dt. 13th July, 81 it was after incorporating rule 489 a clarification was added in the following words :—

'In other words those attempt for third chance on 5th October, 80, will not be allowed to avail of the fourth chance in the ensuing test.'

In the other letter dt 25th August 83, it was also mentioned as follows :

"It may made clear that an employee who had already availed himself of three chances can be allowed for the fourth chance after gap of one chance. In other words those who appeared for the third chance on 26-12-82 will not be allowed to avail the fourth chance in the ensuing test."

No doubt para 489 of the reference book on the staff matters speaks of allowing the fourth chance after a gap of one year from the third unsuccessful attempt. The management has as earlier as July 78 made it clear that the intention of gap of one year was gap of one chance or attempt of one examination and not 365 days and it was with that intent that special circular letter No. 22|123 dt. 5-7-78 was issued.

That the letter was enough guide line for the workman and having failed in three previous test counting from 5-10-80 when he failed for the third time must be enough guide line that he was not entitled to appear for the fourth chance which was to come and ultimately was held on 21-12-81 though after a lapse of one year.

161 GI/85—14

Thus in view of the clarification given in the letter of 5-7-78, the management was fully justified in not allowing the workman to appear in the test held on 21-12-81.

I accordingly give my award that the action of the management of State Bank Of India in relation to its Aligarh Branch in ignoring Shri Hari Om Messenger for the promotion to the post of clerk is justified.

I, therefore, give my award accordingly.

Sd|-

(R. B. SRIVASTAVA), Presiding Officer

Let six copies of this AWARD be sent to the Government for Publication.

Sd/-

(R. B. SRIVASTAVA), Presiding Officer

[No. L-12012,129|82-DII(A)]

का. आ. 2212.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-4-85 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2212.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Goverament on the 19th April, 1985.

ANNEXURE

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I. D. No. 204 of 1983

In the matter of dispute between :

Shri Suresh Kumar Sachdeva Typist, C|o Shri V K. Gupta, 2|363, Nambiar, Agra.

AND

The Chief Regional Manager, State Bank of India, Laurles Hotel M. G. Road, Agra

Sri V. K. Gupta representative—for the workman and Shri S. S. Sharma, representative—for the bank management.

AWARD

The Central Government Ministry of Labour vide order No. L-12012/258/82-D. II (A) dt. 28th June 83 has referred the following dispute for adjudication:

"Whether the action of the management of State Bank of India in relation to their Agra Branch in terminating the service of Shri Suresh Kumar Sachdeva, Typist| clerk from 22-2-74 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?

It is common ground that the workman Shri Suresh Kumar Sachdeva, was appointed on 24-5-73 and was terminated on 22-2-74. It is however disputed that the appointment was not against regular and permanent vacancies but it was purely a temporary appointment on temporary basis. An appointment letter for one month was initially issued to him which was extended from time to time. A photo copy of those appointment letters and extension letters have been filed by the management. It is further not disputed that when services of the workman was terminated he had completed 266 days of work in span of one year counting from the date of termination. It is further admitted that no notice, notice pay or retrenchment compensation was paid to the workman. The management has however, stated that to give workman the benefit of his temporary services he was called for test and interview held specifically for his category of employees. The workman in consequence of passing that test and interview was given appointment with effect from 7-4-84 fresh.

The workman has called the termination illegal as his services were terminated without notice, notice pay or retrenchment compensation or without following the provisions of LAST COME FIRST GO laid down under sec. 25(G) of the I.D. Act.

The workman had appeared in the examination conducted by the bank on 3rd October, 82 without prejudiced to his right and claim then pending before the Assistant Labour Commissioner (Central) Agra. Despite objection before the test the bank management under pressure and threats got signed declaration that in case he was appointed he will not claim past benefits consequently after passing the test and interview the workman was appointed on 7-4-83, but he was not given the benefit of his past services and back wages and continuity of the service. The workman prayed that he be in regular appointment of the bank from the date of his initial appointment and should be paid full back wages and be treated in continuous service.

The management bank has moved a miscelleneous application offering concessions to the workman. It is averred that the management has reconsidered the matter in its entirety and has come to an agreement with the All India State Bank Of India Staff Federation at Central Office Level. The workman is also a member of the association which is affiliated to the federation according to the understanding reached between the workman and the management, the management offers to pay all arrears of salary and allowances to the workman w.e.f. 16-1-76 i.e. the date on which the judgment in Sundermoney's case was announced by the Supreme Court subject to fulfilment of conditions.

Further this concession was not to mean that the workman will enjoy the benefit of continuity of service for the period he has not worked with the bank for the purposes of seniority.

My attention was also drawn during the course of argument to the agreement between the State Bank Of India and All India State Bank of India Staff Federation dt 22nd August. 77 wherein it was agree; "That each of the concerned tempporary employees will be paid back wages together with such increments as would have been admissible to him as temporary employee in the bank service for the period upto the date of reinstatement from the date of judgment namely 16-1-76 and from the date of last termination if it is later than 16-1-76. Further clause 4 of the agreement lays down as following :

"The concerned temporary employee will not be eligible for any special benefits including seniority in service as flowing from the reinstatement in service other than what are normally provided for in the terms and conditions of the service of temporary employee in the bank." AND

Clase V runs as follows :

"All dispute raised by any affiliate of the Federation or any individual employee or any body else in regards to the benefits of back wages seniority in service increments or other benefits flowing from reinstatement have been settled by virtue of this agreement for being recorded by any authority like any Tribunal Court conciliation officer or any other authority before whom disputes may be pending and all such disputes shall no longer subsist and be deemed to have been withdrawn"

In the said agreement there is no agreed period during which the settlement remained to operation and in the absence of such period agreement outlived its utility after expiry of six months under sec. 19(2) of the I. D. Act.

Further the government in its wisdom referred the dispute for adjudication ignoring any such agreement. Lastely the all India Federation of Beneficiary Employees of Bank, in fudiciary capacity vis-a-vis workman of other banks have no right jupordise the interest of the workman or bind them against the legal benefits accruing and to that extent the agreement being not in interest of the workman and against law of the land would be illegal and not binding.

Sec. 2(00) of the I.D. Act defines "retrenchment which includes termination for any reason whatsoever unless falls in any of the accepted categories."

Sec. 25-B(2) defines the conditions of service. It is not disputed that the workman was terminated/retrenched w.e.f. 22-2--74 when he had put in more than 240 days of work during the span of one year counting backwards from 22-2-74. It is further not disputed that no retrenchment dues, notice or notice pay was given to him as required under sec. 25(F) of the I. D. Act, hence in view of the law laid in State Bank Of India V|s M. Sundermoney' 1976 S. C. Cases (L&S) page 132;

The retranchment would be illegal ab-initio and the workman will be entitled to be put back from where he left i. e. reinstated with all full back wages.

In Mohan Lal V|s Bharat Electronics Limited, 1981 S.C. Cases (L&S) page 478, it was held as follows :

"We hold that the termination of the service of the appelliant was ab-initio void and inoperative and the declaration is made that he continued to be in service with all consequential benefits namely back wages in full and other benefits, if any."

In B. N. Gupta V|s State of West Bengal, Civil Revision No. 11826|W|76 dt. 21st August, 73. In this case it was observed;

"It is provided that the petitioner be reinstated forthwith and will be paid full back wages from the date of appointment| reinstatement till the reinstatement minus any sum paid to the petitioner under the proper receipt in the meantime."

In view of the discussions made above and law laid down, I give my award that the action of the management of State Bank of India, Agra under the control of the Chief Regional Manager, Agra in terminating the services of Shri Suresh Kumar Sachdeva typist|clerk w.e.f. 22-2-74 is not justified. Shri Suresh Kumar Sachdeva will be deemed to be in continuous service thereafter, and will be entitled to full back wages from 22-2-74 till the date of his reappointment i.e. 7-4-83. He will be entitled to the continuity of service and other past benefits.

I, therefore, give my Award accordingly.

Sd|—

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

Let 6 copies of this award be sent to the Govt for publication.

Sd/-

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. 12012|258|82. DII(A)]

का. आ. 2213.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-4-85 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2213.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of LIC of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th April, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA: PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 29/84

In the matter of dispute between Shri Ashok Kumar, Chowkidar Represented by L. I. C. IVth Class Employees Association (Regd.) 25, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.

Versus

M/s Life Insurance Corporation of India Through Sr. Divisional Manager, 25, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.

APPEARANCES:

Shri Vijay Kumar Jaiswal Advocate with workman.

Shri Ravider Sethi Advocate for the Management.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour on 19-3-84 vide Order No. L-17012/14/83-D.IV(A) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India, New Delhi in relation to their Divisional Office at Kasturba Gandhi Marg, New Delhi in imposing the penalty of 'Reduction to a lower stage in time scale by two steps'upon Shri Ashok Kumar, Chowkidar, with effect from 1-12-1978 is disproportionate to the misconduct committed by him? If so, to what relief is the workman concerned entitled?".

2. The following charges were framed against the workman Ashok Kumar Chowkidar vide chargesheet dated 28-8-76 issued by the Sr. Divisional Manager Delhi Division Office :

1. On 13th August, 1976, you stayed in the office beyond the duty hours i.e. after 10.00 P. M. and put a cross mark at 10.05P.M. in the Attendance Register against the relative column of Shri Narain Bahadur, while you had no authority to do so. This unauthorised action of yours is not only prejudicial to good conduct but is also detrimental to the interests of Corporation.

2. When pointed out by Shri Ganga Singh, Bhagwan Singh and Moolchand Chowkidars, not to mark late before the expiry of the grace period of ten minutes, you even started quarrelling with them and went to the exent of attacking Shri Ganga Singh Chowkidar with an iron rod with the intention of causing grievous hurt to a fellow worker. You have thus also committed as not of grave indiscipline.

3. The Enquiry Officer held that the first charge was not proved because the action of the workman in making late cross of Narain Bhadur on 13-8-76 was in accordance with accepted prevailing custom or practice and so, cannot be termed as unauthorised action. In respect of the second charge the Enquiry Officer held that the evidence before him established that the workman did not actually hit Shri Ganga Singh or any other Chowkidar present at the time of incident with an iron rod. If he had picked up an iron rod so also did Ganga Singh. If the workman used abusive thing so also did Shri Ganga Singh. His conclusion was that the Management's case in support of the second charge was not proved conclusively, and that the only language established in the enquiry was that the workman concerned had abused or exchange hot words with Ganga Singh and had picked up an iron rod for whatever purpose it might be and this action on the part of the workman was uncalled for and not expected from an employee of the Corporation.

4. The only question to be decided whether the punishment of reduction by two steps in the time scale imposed on the workman is excessive or appropriate to the misconduct proved in the enquiry.

5. It is argued for the workman that the only thing established in the enquiry was that there was exchange of hot words with Ganga Singh and picking up iron rod by the workman. The plea on behalf of Ashok Kumar is that Ganga Singh used hot words first and that when Ganga Singh picked up iron rod Ashok who was one against three also picked up iron rod in self-defence and the Management's case of Ashok Kumar picking up iron rod with intention to cause grievous hurt to Ganga Singh had not been proved.

6. The Ld.counsel for the Life Insurance Corporation argues that the punishment awarded was adequate and proper and should not be interfered with when the workman picked up the iron rod in the office and exchanged hot words with Ganga Singh.

7. In my opinion the plea raised on behalf of Ashok Kumar has forced. He has not been proved to be the one who used hot words first. His action in marking attendance late has been held to be proper and in accordance with the procedure. He had no reason whatsoever to start a quarrel and if three other start a quarrel against him for his doing what is right, he could have used hot words by way of exchange and could have picked up an iron rod in self-defence when Ganga Singh did so.

8. Under the circumstances aforesaid the punishment imposed on him is excessive and is reduced to stoppage of one annual increment without cummulative effect and the Management is required to give relief to the workman and take it that the only punishment imposed on his is stoppage of one annual increment without cummulative effect. The Award is made accordingly.

It is further ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

April 18, 1985.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. 17012/14/83/D-IV(A)]

नई दिल्ली, 3 मई, 1985

का. आ. 2214:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार केनरा बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23 अप्रैल 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd May, 1985

S.O. 2214.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Canara Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd April, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 217/83

In the matter in dispute between :

Shri Kishan Singh, c/o Sri A. P. Sharma, Advocate, Vunio Building, Collectorate Road, Agra.

Versus

Canara Bank, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri H. C. Dhall for the Management.

Shri K. T. Anantraman for the workman.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour on 28-6-83 vide Order No. L-12012|194|82-D.II(A) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Canara Bank, Agra in relation to its Lohamandi Branch, Agra in terminating the services of Sri Kishan Singh, Clerk with effect from 29-1-1979 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. Shri Kisban Singh was appointed as Clerk in the Canara Bank on 19-6-74 and was continued on 19-12-74. The Savings Bank Ledger pertaining to account No. 3166 of Shri R. K. Samadhia was found to have interpulation and the workman was called upon to give explanation. His explanation was found unsatisfactory and the Management charge-sheeted him and apponted Shri Krishna Murty as an Enquiry Officer. Shri Krishna Murty found the workman guilty in the enquiry and recommended his dismissal from service but the Disciplinary Authority did not accept that recommendation for his punishment and simply ordered his dischargo from service w.e.f. 29-1-1979.

3. The workman has claimed that section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 applied to him because the discharge was nothing put retrenchment within the meaning if section 2(00) of the Industrial Disputes Act, 47 and he was not paid retrenchment compensation. He has also challenged the domestic enquiry as sham and mockery and against the principles of natural justice and the report of the Enquiry Officer to be biased presumptuous and perverse. His case is that he is entitled to reinstatement in service with full back-wages. The Management was said to have no powers to initiate enquiry into what was an offence under Penal Code without waiting for police action for the period prescribed under the Bank Awards and Settlements.

4. The Managemsent contested the claim of the workman and asserted that the workman was responsible for manipulation in the Saving Bank Ledger in the Saving Bank Account No. 3166 of Shri R. K. Samadhia from whom he had borrowed money and additional money was paid to the workman by '11' being written to the left side of the "30" in the ledger to make it '1130' in the Saving Bank Ledger No. 13 to allow that Account Holder to draw more money than was in deposit with the bank, the punishment imposed upon the workman was said to be in accordance with the bank regulations and it was said to be not a case of retrenchment at all. The enquiry was said to be fair and the enquiry Officer's findings free and balanced. He had committed a criminal offence under the Indian Penal Code but the Management took a lenient view in the matter and did not report the matter to the police.

5 The following preliminary issues were framed and have been tried without oral evidence having been led by the parties.

(a) Whether domestic enquiry is violative of the principles of natural justice as alleged ?

(b) Whether Order of discharge amounts to "Retrenchment" ? If so to what effect ?

(c) Whether disciplinary proceedings are void abinitio ?

The main issue, however, remained as in terms of reference.

6. I have heard the representatives of the parties.

7. In so far as the plea of the workman relating to failure to prosecute in criminal court is concerned, there is a decision of Delhi High Court in Cvil Writ No. 1088 of 1969 on 12th November, 1970 in workmen of Indian Overseas Bank Vs. Indian Overseas Bank and another reported in 1973(1) LLJ. 316 where Hon'ble Mr. Justice Rajinder Sachar of Delhi High Court ruled that there was no force in the contention that the Management must first either prosecute the workmen or get im prosecuted and it is only when they have not prosecuted or put on trial within a year of commission of offence that the Management can proceed against them under para 581 (3) of the Sastry Award. It was ruled that the Management had the option to proceed against the employee either in a criminal court or departmentally.

8. The objection that the discharge of the workman amounts to retrenchment under Industrial Disputes Act, 1947, however, has force.

9. Delhi High Court in Management of State Bank of India Vs J. D Jain and another reported in 1979 Lab. I. C. 1041 ruled that a bank employee discharged from service in terms of para 521 (5) (e) of the Sastry Award cannot be said to have been punished and the meaning was that his misconduct was condoned and he was merely discharged and such discharge would not fall within the ambit of Disciplinary action as stipulated by the term dismissal and there was no case for the Labour Court to examine the matter under section 11-A of the I.D. Act, 47 by reference to modification of punishment awarded to the workman.

10. This very judgment is relied upon by the Management to hold that no relief can be given to the workman as in the case aforesaid. But it is to be noted that this judgment does not examine the impact of section 25-F of the I.D. Act, 47 on the order of discharge.

11. The Management has relied upon the judgment of Bombay High Court in Shri R. K. Mehta Vs. Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal No. I Writ Petition No. 1300 of 1979 decided on 4-9-79 by the Bombay High Court to urge that retrenchment means merely discharge of surplus labour and discharge for loss of confidence could not be included in the expression for any reason whatsoever and termination that score would not amount to retrenchment.

12. The view of the Bombay High Court is incorrect and now the settled law is that any termination of service is retrenchment if it is not covered by the exceptions in section 2(oo) of the I.D. Act, 47 and section 25-F violation would make the order of termination void ab initio giving rise to the right of the workman to be reinstated in service with full back-wages. It was so ruled in L. Robert D'Souza Vs. Executive Engineer, Southern Railway, 1982 I S. C. 854 as under :—

"The expression 'termination of service for any reason whatsoever' in the definition of the expression 'retrenchment in section 2(00) of the I. D. Act covers every kind of termination of service except those not expressly included in Section 25-F or not expressly provided for by other provisions of the Act such as Sections 25-FF and 25-FFF. Once the case does not fall in any of the excepted categories, the termination of service even if it be according to automatic discharge from service under agreement would nonetheless be retrenchment within the meaning of expression in Section 2(00) So that if the name of the workman is struck off the rolls that itself would constitute retrenchment. Therefore, the termination of service for unauthorised absence from duty in this case would be 'retrenchment' within the meaning of Section 2(00) and so the pre-conditions to a valid retrenchment set out in Section 25-F must be satisfied."

13. As regards the plea that discharge from service is punishment under the Canara Bank Regulations 4(H), the same must be accepted as having been modified and over ruled by the Sastry Award and the Bipartite Settlement applicable to the Banking Industry and the ruling of Delhi High Court in respect of Sastry Award para 521 has already been referred to above.

14. Accordingly it is a case where the order of discharge by the Management must be taken to be a simple order of dischange and not a punishment and the provisions of section 25-F of the I.D. Act, 47 were applicable but were not complied with by the Management making their order of termination of service of workman Kishan Singh void ab initio. It is, therefore, held that the order of the Canara Bank, Agra terminating services of Kishan Singh, clerk w e f. 29-1-79 are void ab initio and the workman is ordered to be reinstated in service with full back-wages and conti-

nuity in services. There shall however, be no orders as to costs.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the central government for necessary action at their end.

April, 17, 1985.

O. P. SINGHA, Presiding Officer
[No. L-12012/194/82-D. II A]

का. आ. 2215.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-4-85 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2215.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th April 1985

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I.D. No. 183 of 1977

In the matter of dispute between :

Shri R. N. Srivastava C/o. Dy General Secretary State Bank of India Staff Association, C/o. State Bank of India, H.O. The Mall, Kanpur.

...Workman

AND

The Chief Manager, State Bank of India, Head Office, The Mall, Kanpur ... Management

AWARD

The Central Government vide its order No. L-12012/120/76-D-II A, dated 4-8-77 has referred the following dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of India, Kanpur in stopping two increments with cumulative effect of Shri R. N. Srivastava, Clerk, State Bank of India, Main Branch, Kanpur is justified or not? If not, to what relief is he entitled?"

It is a common ground that the workman Shri R. N. Srivastava is still in the employment of the management's Bank. On 12th August 1972 he was served with a show cause notice, why diciplinary action should not be taken against him in relation of the allegations that the workman resorted of the unfair means in the Indian Public Finance and Financial Administration examination of the Indian Institute of Bankers held on 30-10-71 which act was highly prejudicial in the interest of the bank and has brought the bank's name in disrepute. The workman submitted his explanation. Allegedly he was found in possession of some paper during the examination. In view of violation of rule 14 regarding the conduct of examination which reads as follows :

"Institute after considering the relevant facts cancelled the result of the workman and debarred him from appearing in the associate examination for three years".

Despite that the bank served with the above mentioned show cause notice to which workman gave explanation and as the same was not found satisfactory he was consequently served with a charge sheet to which he submitted his explanation. The explanation was found unsatisfactory. The Enquiry Officer after a detailed enquiry and after affording the workman full opportunity to defend himself came to the conclusion that the charge sheet had not been established. The diciplinary authority did not accept the finding of the enquiry officer and after careful consideration of the proceedings of the enquiry officer and his findings came to the conclusion on the basis of facts fully established in the enquiry proceedings that the charge framed against the workman was established.

The deciplinary authority thereafter decided to award punishment to the workman by way of stopping his two increements w.e.f. 1975. The show cause notice for the said proposed punishment was given to the workman and after considering the explanation of the workman the punishment was confirmed. The workman preferred an appeal against the said punishment order which was rejected. On the averments of the parties, following issues were framed.

ISSUES

1. Whether the reference is involved on the ground alleged ?
2. Whether Shri R. N. Srivastava is workman ?
3. As in order of reference ?
4. Whether the dispute has been properly espoused ?

FINDINGS

Issue nos. 1 and 2

A perusal of the reference order does not show that it is an industrial dispute arose under sec. 2-A of the Act. Further it is not a case of discharge dismissal, retrenchment or termination of the workman as admittedly he continues in service. On the basis of reference order it appears that the dispute was between the workman and employer of State Bank of India, Main Branch, Kanpur, and it was on that account that a copy of the reference was forwarded to the Secretary (Deputy) State Bank of India Staff Asso.

The next objection is that the workman having been promoted as officer in the bank is no longer workman. The reference order itself shows that at the time when the dispute was arose Sri R. N. Srivastava was a clerk in the State Bank. If he has been promoted as officer in the bank that will not take away his rights to raise industrial dispute through his association. I therefore, decide issue nos. 1 and 2 accordingly against the management bank.

Issue no. 3 :

As observed earlier Shri R. N. Srivastava has admitted in his affidavit that he was debarred by Indian Institute of bankers from the said examination for three years for allegedly being found in possession of three sheets of papers in the examination hall which as a matter of fact he had handed over to the invigilator before the start of the examination and before commencing his writing answer to paper and in this way a penalty was imposed on him by the said institute.

In cross examination again he admitted that he was debarred by Indian Institute of Bankers and he did not challange that order and it is a fact that the institute is an independent body with no control of the bank over it.

The management examined one Shri B. R. Gupta on affidavit who averred in para 12 thereof that the enquiry officer vide his finding dt. 5-7-73 had observed that the facts namely Shri Srivastava, the workman, admittedly was in possession of the papers at the time of the commencement of the examination and it was established that the workman had been in possession of the said papers containing answer of some of the questions appearing in the question paper even after 15 to 20 minutes of the commencement of the examination. The enquiry officer, however, came to the conclusion that the charges against workman had not been established as he had not actually copied the answers of the questions written on the paper found in his possession in the examination hall. Despite the finding of the enquiry offi-

cer on the established fact the deciplinary authority came to the conclusion that the charge framed against the workman was established and consequently gave him punishment.

In cross examination Shri B. R. Gupta has admitted that the candidates appearing in the examination of Indian Institute of Bankers were not treated on duty as the examination were conducted at that time beyond duty hours of the bank. He has however, admitted that it is a fact that the bank served a memo to the workman knowing it fully well that the offience of mistake if any was not done by the workman during the banking hours. He has further admitted that if the workman was exhonerated in the departmental enquiry by the enquiry officer a show cause notice was given to the workman but alongwith that notice copy of enquiry proceedings and its report was not enclosed. He has further admitted that no reason was given why report of enquiry officer was not acceptable and why punishment has been proposed.

It has been argued on behalf of the workman that two punishment can not be meeted out for the same offence under article 20 of the constitution of India. He having been given punishment of debarment of three years could not be punished again by the bank for the same. It is further argued that wrong if done by the workman was beyond the duty hours of the bank, hence it was outside the jurisdiction of the bank, to have punished on the point of double jeopardy. the workman representative has drawn my attention to the ruling State of U.P. Versus Sughar Singh A.I.R. 1974 S.C. page 423 wherein it was observed :

"In all such cases the order is to be taken as a punishment. Sometimes again the order of reversion may bring upon the officer certain penal consequences like forfeiture of pay and allowances or loss of seniority in the subordinate rank of the stoppage or postponement of future chances of promotion. In such cases also the government servant must be regarded as having been punished and his reversion to the substantive rank must be treated as reduction in rank."

Thus stoppage of increment would amount to loss of seniority forefeiture of pay and allowance and future chances for promotion would amount to punishment. On the other hand, the representative for the management has drawn my attention to law laid down in R. P. Kapoor Vs. Union of India A.I.R. 1964 S.C. 787, wherein it was observed that "the trial of the criminal charge results in conviction, disciplinary proceedings are bound to follow against the public servant to convicted, even in case of acquittal proceedings may follow where the acquittal is other than honourable. The usual practice is that where a public servant is being tried on a criminal charge the government postpones holding a departmental enquiry and waits the result of the criminal trial and departmental proceedings follow in the result of the criminal trial".

On the point of double jeopardy my attention was drawn to para 531(2)(b) of the Shastri Award which provides that if a workman is acquitted for an offence he may be dismissed from the date of his conviction|may be given any lessor form of punishment. Thus despite the fact that the authority taking examination i.e. Indian Institute of Bankers itself debarred the workman from taking subsequent examination for the next three years|chances yet the bank was bound to take disciplinary action in view of the rules referred above. The bank employee is an employee for 24 hours and not an employee only for banking hours i.e. 10 to 5 p.m. Further the nationalised banks comes under the definition of State and the emplovees of such banks are treated servant of the bank within the meaning of a public servant.

It is not disputed that the enquiry officer in his report exhonerated the workman of the charge. The charge was to the effect "that you reported to unfair means in the Indian Public Finance and Financial Administration Examination of the Indian Institute of Bankers held at this office on 30th October 1971. This wilful action on your part was highly prejudicial to the interest of the bank in as much as it has brought the bank's name into disrepute".

Unfairmeans, means some thing more than attempt for unfair means and suggests completion of the act not by fair means. It is not the case of the prosecution that the workman was actually seen conving or he had copied out from the paper. It was in view of this context that the enquiry officer held as follows :

"Taking a comprehensive view of the whole case, I am inclined to hold the view that the charge against Shri Srivastava is not proved."

In the body of his report the enquiry office has observed from the evidence that during the examination a written sheet was seen in the hand of Shri Banerjee Examination Suptd. which he had recovered from the workman. The other two corroborating invigilators produced as witness did not see the recovery of the paper from the workman by Shri Banerjee. The witnesses in the enquiry were also not clear as to whether the paper was recovered soon after the commencement of the examination or latter. Examination Superintendent Sri Banerjee himself has stated that the workman was completely confused and could not satisfy as to why he had kept the paper. On being questioned during the enquify as to whether the workman himself has given the paper to the examination superintendent he replied that he could not say definitely. It is not the case of the management that the workman was copying from any paper. If soon after the commencement of the examination he recollected about possession of some paper with him which he forget to keep out of the examination hall and handed over it to the examination superintendent, it can not be said that he resorted to unfair means. If possession of any paper is unlawful that being established he was rightly debarred by the examining body for the three years and as the charge sheet was regarding resorted to unfair means in the examination, the enquiry officer was fully justified in giving his opinion in the negative holding that the charge was not proved.

The note of the personnel department that even if the paper was recovered on the start of the examination, the workman was guilty of the rules. Chief Manager agreed in the mid and the conclusions of the personnel department were noted and it was endorsed as follows :

> In view of the foregoing it will be observed that the charge against Shri Srivastava in our view has been proved and the chief manager has noted his agreement that and further to the suggestion "that having regard to the gravity of the misconduct it would be necessary to stop two increments of Shri Srivastava which would also have the effect of postponing his future increments.

The appellate authority in his order dated 20th July 1975 discriminated himself on the main charge and pose a question himself as follows. "The main question appears to be whether the intention of Srivastava was to adopt unfair means or not." He has further observed from the enquiry proceedings it would appear to have been established that Shri Srivastava was detected while taking out the impugned slip from his pocket and he was asked to leave the examination hall. This observation of the appellate authority that the workman resorted to unfair means in the examination It may called to be intention as observed by the appellate authority was utmost it may be an attempt and not completion of the act i.e. resorted to unfair means.

The disciplinary authority can not differ from the findings of the enuiry officer but the reasons for difference should be passed on cogent evidence and there should be a reason out speaking order. In the instant case appellate authority did not take into notice the charge framed but came to another finding i.e. possession of paper during the examination which was not the charge. The charge being resorting to unfair means will not amount to recovery of a paper during examination as held by the appellate authority.

In Raghubir Singh Versus Union of India 1121 Delhi High Court it was observed "Even assumng that the commending Officer can differ from the findings of the court of enquiry, he must do so by stating his reasons particularly when the three courts of inquiry had established innocence of the petitioner. A finding of guilt ought to state as to why the findings of the court of enquiry are wrong. A speaking order in these circumstances is a sine quo non of fair play".

In T S. Srivastava Vs. State of Assam A.I.R. 1972, Gauhati page 2 in this case it was held "Where although the enquiring officer had substantially observed the petitioner from the

charges specifically levelled against him, the disciplinary authority in fact disagreeing with those findings and without recording the reasons for the disagreement held him guilty of four of the charges and also gave a different picture of some of the finding which involved certain charges not levelled against the petitioners and for which he was never given any opportunity of hearing it was held that the order withholding three increments should be struck down as being in violation of rule 9 and the principles of natural justice."

In view of the reasons given above I hold that the charge of resorted to unfair means was not proved against the workman Shri R. N. Srivastava.

Issue No. 3 is decided accordingly.

ISSUE NO. 4 :

On the point of espouser I may refer to the law laid down U.K. Roller Floor Mills Vs. Industrial Tribunal, Nagpur 1979 LIC 45 Bombay DB, wherein it was held that "reference order can be challenged in High Court Tribunal is not empowered to consider and question the authority of justifiability of the order of reference issued by appropriate government". As regards espouser the order of reference itself shows that that the industrial dispute existed between the management in relation to the S.B.I. Main Branch, Kanpur and their workman and the information of the reference order sent by the Govt. to the Dy. General Secy. S.B.I. Staff Association, Kanpur and not to the workman. Further the statement of claim in this case has been filed by Shri P. N. Tewari on behalf of the orkman for State Bank of India Staff Association, Kanpur. Further the dispute about proper espouser should have been raised at the earlier stage of conciliation proceedings and not after reference order. When the government has referred the dispute for adjudication after considering all the points of the case and treating the union as sponseror of the dispute. I, accordingly decide this issue against the management.

In view of the above findings, I give my Award, that the action of the management of State Bank of India, Kanpur in stopping two increments with cumulative effect of Shri R. N. Srivastava, Clerk State Bank of India, Main Branch, Kanpur is not justified.

The result is that the workman is entitled to his normal increments if not stopped for any other reason.

I, therefore, give my award accordingly.

Let 6 copies of this award be sent to the Government for publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/120/76-D. II(A)/(Pt.)]

नई दिल्ली, 6 मई, 1985

का. आ. 2216:—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चन्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23 अप्रैल, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 6th May, 1985

S.O. 2216.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd April, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D| 144 of 1981 (DELHI); 51 of 1984 (CHANDIGARH)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab National Bank.

AND

Their Workman; Ramji Lal Gupta.

APPEARANCES :

For the Employers—None.

For the Workman—None.

ACTIVITY :

AWARD

Dated the 16th of April, 1985

The Central Govt., Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-12012|275|80-D. II. A dated the 30th October, 1981 read with S.O. No. S-11025 (9)|84-D. IV(B) dated the 26th October, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Punjab National Bank in proposing to withdraw the payment of Teller Allowance to Shri Ramji Lal Gupta, Teller, Minto Road Branch, New Delhi of the said Bank, is justified ? If not, to what relief is the workman concrned entitled ?"

2. On the receipt of the case on transfer from my counter part at New Delhi a notice was sent to the parties calling upon them to appear before this Tribunal for the projection of their respective versions. But for the reasons better known to them despite service neither of the parties cared to put in appearance. All the same I scrutinised the record on my own.

3. Perusal of the terms of reference itself is indicative of the premature nature of the dispute because it appears that withdrawal of the Teller Allowance was at the proposal stage and had not yet been implemented. And perhaps for this precise reason the parties did not take interest in persuing the matter any more.

4. Accordingly, I return my Award with the finding that the reference is redundant.

Chandigarh.

Dated 16-4-85.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-12012/275/80-DII(A)]

का. आ. 2217:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार युनाइटिड इंडिया इम्सोरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध

में, निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं 2, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 23 अप्रैल, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2217.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of United India Insurance Co. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd April 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/29 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of United India Insurance Company Limited Nagpur.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande,

Presiding Officer

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. D. Chadha, Advocate.

For the Workmen.—Shri N. G. Vaidani, Shri C. N. Talang Advocates.

INDUSTRY : General Insurance STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 8th April, 1985

AWARD

By their order No. L-17012/8/84-D. IV(A) dated 10-9-1984 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :

"Whether the action of the management of United India Insurance Company Limited, Nagpur in relation to their Gondia Branch in terminating the services of Shri Anil N. Shah, Clerk-cum-Cashier with effect from 24-9-1983 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The employee concerned is Shri Anil N. Shah, who supports his case by the claim statement Ex. 2/W whereby it is te contention of the workman that after the inauguration of the Gondia Branch of the United India Insurance Company Ltd., on 27-7-1981 and after it started functioning from 1-8-1981 when Shri S. Neelkanthan was the Branch Manager, the workman worked in the said office as clerk-cum-Cashier for about two months i.e. August and September without receiving any remuneration or salary. It is alleged that after he was acclimatised with the work he was paid Rs. 15 per day for all the working days and that in the beginning he was being paid daily wages. It is alleged that although he was appointed as a Clerk-cum-Cashier he used to perform all clerical job like writing of Premium Register, Monthly Progress Reports, Maintenance of Cattle Insurance Registers, Police Copy Documents and Premium receipts. It is alleged that during his tenure of service he was getting Rs. 300 at the rate of Rs. 15 for 20 days only but was being paid on monthly basis and that he was in the employment from October, 1981 and continued to work till 1983. The dispute started when on 24-9-1984 Shri Shah was asked not to attend the office and therefore his services stood terminated. It is his contention that though he worked for more than 240 days and was continuously employed for more than 240 days Provisions of Section 25F were not followed rendering the termination null and void and hence the request for reinstatement with back wages.

2. By their written statement Ex. 3/M these contentions have been refuted. It is firstly urged that the dispute is not an industrial dispute as defined under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act because having not been espoused by any Union of the workmen. It is further alleged that there was no relationship of employer and employee between the parties and that there were no fixed hours of work nor he was working exclusively for the company. It is alleged that the workman was paid remuneration of Rs. 15 for every day when he worked and that when to work was at the volition of the workmen and he was never a monthly paid employee but was being paid on the basis of daily casual worker. It is further stated that the workman executed receipts or vouchers for the money paid to him, that the workman never attended the office daily but intermittently and that from October, 1982 to September, 1983 he worked only for 231 days as is evidence from the vouchers executed by the workman himself. On these grounds, therefore, it is urged that the workman deserves no relief.

3. On the above pleadings the following issues arise for determination and my findings thereon are :—

ISSUES	FINDINGS
1. Is this an industrial dispute or individual dispute ?	An industrial dispute.
2. Is not the Clerk-cum-Cashier a workman ?	A workman.
3. If it is an individual dispute, is it tenable ?	Does not arise.
4. Does the workman prove that during the period of 12 calendar months preceding the date of alleged termination he actually worked with the United India Insurance Co. Ltd. for not less than 240 days ?	No.
5. If yes, was the service terminated legally ?	Not proved to be illegally terminated.
6. If not is the workman entitled to reinstatement or any other relief ?	No.
7. Whether the action of United India Insurance Co. Ltd. in terminating the services of clerk-cum-cashier justified ?	Yes.
8. If not to what relief or reliefs he is entitled ?	Nil.

REASONS

4. Relying on the definition of industrial dispute under Section 2(k) of the Act and further relying on the fact that admittedly the workmen is fighting out the cause single handedly without any support from the co-workmen or any Union, it was urged that this dispute is an individual dispute having never achieved the status of an industrial dispute. However, while advancing this argument, Section 8A of the Act was lost sight of here any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the service of an individual workman, any dispute or difference between that workman and his employer has to be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workman is a party to the dispute. Consequently in the light of section 2A of the Act the objection cannot have any force.

5. It was urged that there is no relationship of employer and employee between the parties and therefore the employee cannot raise the dispute. Now the fact that Shri Shah was serving as a clerk doing duties like preparing the register etc. stands admitted and therefore he cannot be excluded from the operation of the definition of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act provided the relationship of employer and employees established. Now it is an admitted fact that for the work performed like doing clerical duties the employee was being paid at the rate of Rs. 15 per day. It

is one thing to say that he was a casual worker working on daily basis and not on monthly basis workman and it is another thing to say that he was not in the employment. Nowhere there is any allegation in the written statement that the work was being done on contract basis or that the workman was a contractor and not a workman. May be he was not a monthly rated workman but in the absence of any allegation that he was a contractor, against which there is evidence of payment of wages though on daily basis, it is not possible to accept the management's contention. The record speaks that the workman was doing the work of RTO Agent as well as Canvesser for LIC and though in the cross-examination an attempt was made to suggest that this work was being done outside the office hours of the Insurance Company, having regard to the office hours of the RTO office, such a contention is not possible to be believed. The management's witness Shri B.K.B. Sahu states that frequently the workman was receiving telephone calls regarding his RTO agent work during the office hours, and that is bound to be because if he was working as Agent in the RTO office, his presence during the office hours of the said office must have been necessary. However it merely shows that even those days when the workman was working with the Insurance Company he had other duties to perform and this might be the reason why the arrangement of daily service basis continued till September, 1983. Had the workman been in regular wages and absorved on monthly basis, he could not have been performing any other work much less during office hours. However the only effect would be that if otherwise the reliefs are possible the reinstatement if at all there may be any would be on part time work basis.

6. This then brings us to the crucial question namely whether the workman is entitled to the benefits under Section 25F of the Act and the continuous service under Section 25B. In this regard before we decide which of the sub-section of Section 25B of the Act is attracted it would be useful if we again have a glance at the statement of claim Ex. 2/W. The workman says that he was paid Rs. 15 per day for all the working days that he was not being paid on monthly basis and that his services were terminated on 24-9-1983 although he worked for more than 240 days and was continuously employed. It is therefore evident that on his own showing he was being paid Rs. 15 per day for the days for which he worked, he was never absorbed as monthly rated employee and that he wants to take advantage under Section 25B(2) of the Act. The record speaks that the workman is merely a matriculate while the rules of the Insurance Company require an Assistant before he is appointed to be a Graduate. The record further shows that he was not answering the test of typing for recruitment. It is just possible therefor as suggested by the management that because the father of the workman was serving as Inspector at the relevant place at his request the Manager allowed the boy to work on daily basis though not holding sufficient educational qualification. However if otherwise Section 25B read with Section 25F is attracted the other difficulties may become insignificant atleast for determining the real nature of termination.

6. Though an attempt was made to suggest that the workman was in continuous employment so as to attract Section 25B(1) of the Act, the record signed by the workman namely vouchers Ex. 13/M to 23/M for the relevant period namely from October, 1982 to September, 1983 shows that he could not have been in uninterrupted service but must be working day to day receiving the remuneration on the days he worked and no wages during the days of absence. An attempt was made by the workman to suggest that he signed blank receipts and therefore he is not aware of the contents, which it is impossible to believe. It is true that at the relevant time Shri Shah was a novice but he was having his father who was an Inspector in the same Branch, it is therefore not possible to believe that the Branch Manager would prepare any false record prejudicial to the workman. There was no reason for anybody to act adversely to the interest of the workman. It is then tried to urge that the contract was to pay Rs. 300 but the receipts were prepared for daily remuneration. Here again as seen from Ex. 14/M which is a voucher bearing No 72 dated 30-11-1982 for Rs. 270 and Ex. 23/M dated 2-9-1983 for Rs. 375, we find that the payments vary on account of number of days having varied. It is not therefore a payment on monthly basis as tried to be contended but the payment was on the basis of days the workman worked.

7. If we calculate on the strength of these vouchers we find that during the months of October, 1982 to September, 1983 the workman put in all 231 days. An attempt was made to suggest that the number of days put in must have been more and for the said purpose my attention was drawn to records like Premium receipts, Cattle Insurance Paying-in Slips, Policy Stamp Register etc. There is also a reference to monthly progress report. What I find at Ex. 54/W a statement on the strength of the inspection of the company's records, that many of the days are over-laping and what I find is that during 12 months next before termination, 3 days for monthly progress report, 181 days for Premium Receipts and 16 days for cattle Insurance Paying-in-Slips can be considered. Regarding Policy Stamp Register, when the workman says that he was maintenance the register daily the suggestion of the management is that was being maintained at the close of the month after the policies were signed by the workman's father. Shri Shah admitted in the cross-examination that after the policies are signed by the person authorised to do so the policies are handed over to the Policy Holders when adhesive stamp is fixed. He has admitted that on 8-3-1983 he made entries relating to Policy Nos. 24031, 033, 036 to 038, 040, 042 to 047 but at the same time he admitted that these policies were signed by his father on 11-3-1983. Similarly the policy entries in the same register dated 7-3-1983 were signed on 12-3-1983. Policy entries dated 5-3-1983 were signed on 15-3-1983 and on the say day i.e. 5-3-1983 there are entries of policies which were signed on 9-3-1983 and the entries dated 1-3-1983 relating to policy Nos. 244010 to 017 and 019 to 023 were signed on 11-3-1983 the Policy entry in the same register of 26-2-1983 were signed on 15-3-1983 and so on and so forth. He had admitted that the date of signing the Policy may not be the same as the date of entry appearing in the Stamp Register. Even though he did not admit that the dates of entries in the same register were put on the basis of dates appearing in the Paying-in Slips, he had admitted that Policy Nos. 244031, 33 etc. were entered in the stamp register on 8-3-1983 on which date the Paying-in-slips were prepared. He has also admitted other instances although he denied that the entries in the stamp register were made at the close of the month, but there is great force in this suggestion, evident from the replies and therefore considering that the stamp register is not the document like Paying-in slips etc. having been linked with other institution like Bank, there is every reason to believe that the dates of entries in the stamp Register necessarily may not reveal the dates of writing those entries. Therefore although I find that about 49 days are different than the earlier ones, (showed by underline as against tick marks which show overlapping) it is not possible to add them to the list particularly when the dates of other record he worked show 200 (3+181+16) days while from the vouchers we notice that he worked for 231 days and it is just possible that the difference might be because of the days when the entries in the stamp register were made. Having regard to the fact that the agrement was to pay daily basis, and having regard to the fact that the workman received salary for 231 days only during the relevant period, the only conclusion possible is that number of days worked by him must never have exceeded the said figure of 231 days.

8. Under Section 25B(1) the workman can be said to be in continuous service if he is, for that period, in uninterrupted service including service which may be interrupted on account of sickness or authorised leave or an accident or a strike which is not illegal, or a lockout or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the workman. It was urged that during the course of relevant 12 months there must have been atleast 52 Sundays and a good number of holidays on which days the cessation of work was not due to the fault of the workman and therefore these days shall have to be added to the list of 231 days, when so done the total days may exceed more than 240 days. However, the question paramount in this regard would be whether Section 25B(1) or sub-Section (2) applies. We have already seen for sub-Section (1) of Section 25B the workman has to put in uninterrupted service then along the benefits of holidays etc. would be available. In Ramesamis Narsingh Upadhyaya Vs. Vinubhai M. Mitra 1982(II)LLJ page 186 it was held that Section 25B(1) provides that the workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service. The real test therefore is whether the work-

man was in uninterrupted service. In the insistant case having regard to the admission in the statement of claim namely that the workman was working on daily basis and was never being paid on monthly basis, he was getting Rs. 300 for 20 days and was paid for the working days and having regard to the days on which he worked as revealed from various register, it is clear that he was never employed on continuous basis but he was free to work as he chose. There was never any attendance Register and at the close of the month on calculating the days of work he was being paid his wages. It is just possible that this arrangement was mutually beneficial, on the said of the management because the workman had not the requisite educational qualification against which on the side of the workman because he was also working as LIC Agent and Canvasser and RTO Agent. Whatever may be the reason the fact remains that it was not continuous service but interrupted by the day of absence and therefore it is not Section 25B (1) but Section 25B(2) stands attracted and unless during the course of 12 months preceeding the date of termination the workman had worked for more than 240 days, he cannot be said to be in continuous service for a period of one year so as to attract Section 25F. It is true that the number of days fall short by nine days but when legal fiction is being resorted to for showing continuous service for one year, the short fall of even one days may effect adversely the case of the party concerned. I, therefore, hold that the workman during the relevant period from October, 1982 to September, 1983 having worked only for 231 days, Section 25B(2) dose not come to the rescue and his case therefore is not covered by Section 25F of the Act.

9. If the workman was not a Graduate, if he was not answering the recruitment rules, had lack of sufficient English knowledge, then having regard to the educational qualification prescribed the action of termination cannot be said to be unjustified.

10. Once we arrive at this conclusion no relief relating to illegal termination is possible and since the workman was on daily basis that too when work was available, the termination would not attract any relief.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
[No. L-17012/8/84 D. IV. A]
N. K VERMA, Desk Officer

New Delhi, the 3rd May, 1985

S.O. 2218.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd May, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASHISTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 34|84

PARTIES:

Employers in relation to the management of Food Corporation of India.

AND

Their workman—Pal Singh.

APPEARANCES:

For the Employers: Shri N. K. Zakhmi.

For the Workman : Sh. Hardyal Singh.

INDUSTRY : Food Corporation of India STATE : Punjab.

AWARD

Dated the 29th of April, 1985

The Central Govt. Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act, 1947, vide their Order No. L-42012(6)|83.IV(B)|D V, dated the 19th September, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the termination of services of Sh. Pal Singh Casual Labour by the management of the Food Corporation of India is legal and justified ? If not, to what relief is Sh. Pal Singh entitled to and from what date ?"

2. For the reasons detailed in the Award of the even date in the matter of FCI and their workman Jagdish Kumar Reference No. 30 of 1984, per Ministry's Order No. L-42012(8)|83.D.IV(B)|DV dated the 7th of July 1984, petitioner—Workman's termination stands set aside.

CHANDIGARH,
29-4-1985.

I. P. VASHISTH, Presiding Officer
[No. L-42012(6)|83-D.IV.B|DV]
R. K. GUPTA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 2 मई, 1985

का. आ. 2219—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सिंगरेनी कालरीज़ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 22-4-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 2nd May, 1985

S.O. 2219.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri Division and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd April, 1985.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)

AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 95 of 1984

BETWEEN

The Workmen of M|s. Singareni Collieries Company Limited, Mandamari Division, Adilabad District. (AP).

AND

The Management of M|s. Singareni Collieries Company Limited, Mandamari Division, Adialabad District. (AP).

PRESENT:

Sri J. Venugopala Rao, Industrial Tribunal.

APPEARANCES:

Sri K. Srinivasa Murthy and Miss G. Sudha, Advocates for the Management.

None present on behalf of the Workmen.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012|33|84-DIIIB, dated 23-11-1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of Messrs. Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri Division and their workmen to this Tribunal for adjudication.

"Whether the demand of the Tandur Coal Mines Labour Union for confirmation of Shri Narkuntala Odelu, Casual Labour of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri Division as General Madoor Category-I with effect from

10-7-1981 is justied ? If so to what relief is the workmen concerned entitled ?

This reference was registered as Industrial Dispute No. 95 of 1984 and notices were issued to both the partie,, and acknowledged by them.

2. On 31-12-1984 the President, Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli sent a telegram praying for extension of time to file claims statement. Shri X. Srinivasa Murthy and Kum G. Sudha filed vakalat for the Management. Time was extended upto 15-1-1985 for filing claims statement. On 15-1-1985 claims statement was filed in the office. Workmen and their representative called absent. Counsel for the Management present. For counter it was adourned to 11-2-1985. On 11-2-1985 workmen and their representative called absent. Management counsel present and requested some more time for filing counter. Time was extended till 11-3-1985. On 11-3-1985 Sri Saigal, counsel for the Management filed counter. Workmen and their representative called absent. For enquiry adjourned to 15-4-1985. On 15-4-1985 workmen and their representative called absent. Counsel for the Management present. Institute of giving several adjournments the workmen and their representative were called absent & no representation were even made. I find that the workmen are not interested to contest their case for best reasons known to themselves. Hence the reference is terminated and the relief prayed for in the reference is not entitled.

Award passed.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 15th day of April, 1985.

[No. L-22012(33)/84-DIII(B)]

INDUSTRIAL TRIBUNAL

Appendix of Evidence

NIL

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal.
M. L. MEHTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 मई, 1985

का.आ. 2220—उत्प्रवास अधिनियम 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी श्री सुशील कुमार को 6 अप्रैल से 7 अप्रैल 1985 तक उत्प्रवास संरक्षी दिल्ली के सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

[संख्या ए-22012/3/84- उत्प्रवास-II]
राजीत मित्तर, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd May, 1985

NIL

S.O. 2220.—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Emigration Act,, 1983 (31 of 1983) the Central Government hereby authorises Shri Sushil Kumar Section Officer Ministry of Labour to sign all relevant documents as Protector of migrants Delhi with effect from 6th May, 1985 to 7th May, 1985.

[No. A-22012(3)/84-Emig.II]
RAJEET MITTER, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 मई, 1985

आदेश

का.आ. 2221—श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए आदेश संख्या एल-51037/2/83- आई. एंड ई. (एस. एस.), दिनांक 30 मई, 1984 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड और बंगलौर में स्थित चार अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को उक्त निर्देशन आदेश में राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है, न्याय-निर्णयन के लिए भेजा गया था।

और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के कर्मकारों ने, जिनका नेतृत्व सक्रेटरी भारत इलेक्ट्रानिक्स एम्पलाइज यूनियन, जालहल्ली, बंगलौर करती है, रिट याचिका संख्या 1984 की 13098 द्वारा उपरोक्त औद्योगिक विवाद में कतिपय प्रतिष्ठानों को शामिल करने हेतु केन्द्रीय सरकार को अभिवेदन किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर विचार करने तथा उपर्युक्त आदेश देने के लिये निदेश दिया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि प्रश्नागत प्रतिष्ठानों के कर्मकारों की सेवा शर्तें इन प्रतिष्ठानों के मामले के सदृश है जो इस औद्योगिक विवाद के पक्षकार है तथा उनके उक्त औद्योगिक विवाद द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त न्याय निर्णयन के आदेश में निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को भी उक्त औद्योगिक विवाद के पक्षकारों के रूप में शामिल करती है :—

1. बी. ई. एल. यूनिटें	1. बी. ई. एल. गाजियाबाद 2. बी. ई. ए. पुणे
2. एच. एम. टी. यूनिटें.	1. एच. एम. टी. मशीन टूल्स एंड लैम्पस, हैदराबाद 2. एच. एम. टी. बीयरिंगस, हैदराबाद 3. एच. एम. टी. वाच फैक्टरी श्रीनगर 4. एच. एम. टी. ट्रैक्टर डिवीजन पिंजौर हरियाणा 5. एच. एम. टी. अजमेर 6. एच. एम. टी. कालामासारी एर्नाकुलम (डीटी.) केरल 7. एच. एम. टी. वाच फैक्टरी—4, तुमकुर
3. एच. ए. एल. यूनिटें :	1. एच. ए. एल. बंगलौर 2. एच. ए. एल., हैदराबाद 3. एच. ए. एल., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 4. एच. ए. एल., कानपुर (उत्तर प्रदेश) 5. एच. ए. एल., आगरा (उत्तर प्रदेश)

		6. एच. ए. एल., कोरापुट, उड़ीसा
		7. एच. ए. एल. नासिक, महाराष्ट्र
		8. एच. ए. एल. कोरवा (उत्तर प्रदेश)
4 आई. टी. आई. यूनिटें :	1	आई. टी. आई. नैनी
	2	आई. टी. आई. रायबरेली
	3	आई. टी. आई. पालघाट

[सं.-एल- 51037/2/83-आई. एच ई. (एस. एस.)]

वी. एस. एलावादी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 3rd May, 1985

ORDER

S.O. 2221.—Whereas an Industrial Dispute between the Employers in relation to M/s. Hindustan Machine Tools Ltd and four other Bangalore based Public Undertakings and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule to the Order No. L-51037/2/83-I&E(SS), dated the 30th May, 1984 issued by the Ministry of Labour was referred in the said order for reference to adjudication to the National Industrial Tribunal with Headquarters Bangalore.

And whereas the workmen of Bharat Electronics Ltd. led by the Secretary, Bharat Electronics Employees Union Jalahalli, Bangalore by a writ Petition No. 13098 of 1984 have represented to the Central Government for inclusion of certain establishments to the aforesaid industrial dispute; and the Hon'ble High Court has directed to consider this request and pass appropriate orders.

And whereas the Central Government is satisfied that the working conditions of the workers of the establishments in question being similar as in the case of establishments parties to the industrial dispute and are likely to be affected by the said industrial dispute;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 5 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby includes in the said Order of reference for adjudication the following establishments also as parties to the said industrial dispute:

1. B.E.L.	1. B.E.L. Ghaziabad 2. B.E.L. Pune
2. H.M.T. UNITS	1. H.M.T. Machine Tools & Lamps, Hyderabad. 2. H.M.T. Barings, Hyderabad 3. H.M.T. Watch Factory III Srinagar 4. H.M.T. Tractors Division, Pinjore, Haryana. 5. H.M.T. Ajmer 6. H.M.T. Kalamasarry, Earnakulam (DT) Kerala. 7. H.M.T. Watch Factory IV, Tumkur.
3. H.A.L UNITS	1. H.A.L. Bangalore 2. H.A.L. Hyderabad 3. H.A.L. Lucknow (UP) 4. H.A.L. Kanpur, UP) 5. H.A.L. Agra (UP) 6. H.A.L. Koraput, Orissa 7. H.A.L. Nasik, Maharashtra 8. H.A.L. Korwa (UP)
4. I.T.I UNITS	1. I.T.I. Naini 2. I.T.I. Rai Bareli 3. I.T.I. Palghat

[L-51037/2/83-I&E(SS)]
V.S. ALLAWADI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985